चिंतन

पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव को रोकना जरूरी

पश्चिम एशिया में युद्ध उन्माद तेजी से विस्तार ले रहा है। इजराइल एक साल से आतंकी गुट हमास के खिलाफ गाजा में लड़ रहा है, अब इजराइल ने लेबनान में हमास के हमदर्द आतंकी गुट हिज्बुल्ला के विरुद्ध भी मोर्चा खोल दिया है। हिज्बुल्ला के एक एक कर दस से अधिक शीर्ष कमांडरों को मारने के बाद उसके प्रमुख हसन नसरल्लाह को भी इजराइली फौज आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। इजराइल की हिज्बुल्ला से पुरानी दुश्मनी भी है। अपने पड़ोसी लेबनान में सत्ता में शामिल प्रतिबंधित शिया आतंकी गुट हिज्बुल्ला के खिलाफ पेजर व वॉकीटॉकी अटैक के बाद उसके मुख्यालय को निशाना बनाकर इजराइल ने भीषण हवाई हमले किए, जिसमें हिज्बुल्ला तहस-नहस हो गया है। हिजबुल्ला ने बदला लेने की बात कही है, वह भी चुप नहीं बैठेगा। रविवार को आईडीएफ (इजराइली डिफेंस फोर्स) ने हिजबुल्ला के एक और प्रमुख सदस्य नबील कौक को मार गिराया है। इसी दिन अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमला किया है, जिसमें 35 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। इस्लामिक स्टेट के आतंक के चलते सीरिया पहले से ही हिंसक संघर्ष से जूझ रहा है। इराक भी अशांत है। इस क्षेत्र में हमास, हिज्बुल्ला, हुती, अल शबाब, आईएस आदि इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी गुट सक्रिय हैं, जो इस क्षेत्र में हिंसा में लिप्त हैं। इजराइल के लेबनान में हिज्बुल्ला पर आक्रामक रवैये के बाद देर सवेर ईरान के युद्ध में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा होगा तो इजराइल को एक और मोर्चे पर युद्ध करना होगा। बड़ी बात है कि अभी तक इजराइल अपने दुश्मन आतंकी गुटों के सफाये के लक्ष्य के लिए जंग कर रहा है, लेकिन ईरान के कूदने से यह राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाएगा। इस क्षेत्र में इजराइल को ईरान सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अगर ईरान युद्ध में उलझता है तो इसका भारत पर भी बड़ा असर पड़ेगा। भारत के इजराइल से अच्छे संबंध हैं व ईरान के साथ भी। अभी कूटनीतिक रूप से इजराइल अधिक मजबूत है, इसका पहला कारण है कि उसके अमेरिका से बेहतर संबंध हैं, ईरान के यूएस से खराब संबंध हैं। दूसरा, इजराइल के अरब मुल्कों सऊदी अरब, यूएई से भी बेहतर ताल्लुकात हैं। इसलिए 55 इस्लामिक देशों का समूह ओआईसी (इस्लामिक सहयोग संगठन) का सामूहिक रुख इजराइल के खिलाफ होना कठिन है। ईरान ने ओआईसी की बैठक जरूर बुलाई है, लेकिन हमास, हिज्बुल्ला, हुती जैसी आतंकी गुटों के प्रति मुस्लिम देशों में भी विरोध है, इसी के साथ सुन्नी व शिया के बीच की अदावत भी इजराइल के प्रति ओआईसी के एकजुट होने की राह में बाधा है। अभी इजराइल बेशक आक्रामक है, लेकिन वह प्रतिक्रियात्मक भूमिका में है। पहले हमास ने इजराइल में बेकसूरों नागरिकों पर हमला किया, फिर हिज्बुल्ला, हुती, ईरान, कतर आदि हमास के पक्ष में आए, जो आतंक के समर्थन का द्योतक है। भारत के करीबी मित्र हिज्बुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके समर्थन में दुख जताया जाना चिंताजनक है, भारत के मुस्लिमों को आतंकी व सामान्य मुसलमान में फर्क करना सीखना होगा। हसन के नेतृत्व में हिज्बुल्ला लड़ाकों ने गैर शिया मुस्लिमों व गैर मुस्लिमों के बीच मानवता के खिलाफ हिंसा ही मचाई थी। हमास के पक्ष में भी कुछेक भारतीय मुस्लिमों ने आंसू बहाए थे, ये भी शर्मनाक थी। भारत के इजराइल से दोस्ताना संबंध है, ईरान जंग शुरू करेगा तो भारत को कूटनीतिक समझदारी दिखानी होगी। क्योंकि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है। लेबनान से भारत केवल उर्वरक का आयात करता है, तो अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल व लेबनान संघर्ष में ईरान के कूदने से प्रभाव जरूर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका व इजराइल के गठजोड़ व इस क्षेत्र में 40 हजार यूएस आर्मी के तैनात रहने के चलते ईरान के सीधे युद्ध में उतरने की संभावना क्षीण है, फिर भी भारत के लिए खाड़ी देशों में काम कर रहे अपने करीब 90 लाख नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। ईरान के आने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के 195 अरब डॉलर के ट्रेड भी हैं, इस पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बेशक भारत रूस व यूक्रेन जंग की तरह तटस्थ नीति अपनाए, लेकिन वह खाड़ी व पश्चिम एशिया में किसी भी उथलपुथल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इजराइल की आक्रामकता को रोकना जरूरी है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र का चुप बैठे रहना भी ठीक नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव को रोकना आवश्यक है। भारत को भी शांति की पहल करनी चाहिए।

आधी दुनिया
डॉ. मोनिका शर्मा

सुरक्षा और सम्मान हर महिला का हक

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान जुड़े नियमों-क़ानूनों का किसी भी तरह के भेदभाव से परे होना ही आधी आबादी एक लिए समानता का धरातल बना सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा कहा गया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम- 2005, भारत की हर महिला पर लागू होता है, चाहे उसकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अगुवाई वाली इस पीठ ने यह भी कहा है कि स्त्रियों को भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए ही यह कानून है, जो सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। यह अधिनियम एक सिविल कोड की तरह है। जिसके चलते प्रत्येक धर्म एवं समुदाय से सम्बंध रखने वाली महिलाओं से सम्बद्ध है। ध्यातव्य है कि 2015 के इस मामले में मजिस्ट्रेट ने डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट- की धारा 12 के तहत पत्नी को मासिक भरण-पोषण के रूप में 12,000 रुपये और मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया था। 5 वर्ष बाद पति ने परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर आदेश को रद्द या संशोधित करने की मांग करते हुए फिर से आवेदन दायर किया। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन खारिज करने के बाद सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पत्नी की पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यह बात कही है। पत्नी ने तर्क दिया कि पति द्वारा 2015 में पारित मूल आदेश को निरस्त कर पत्नी को दी गई पूरी राशि लौटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जो कि स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दुःखद है कि भारत में कई बार धार्मिक और सामुदायिक सम्बद्धता भी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार पाने के मोर्चे पर बाधा बन जाते हैं। ऐसे में भरण-पोषण और मुआवजे से संबंधित इस मामले में आया यह निर्णय महिला अधिकारों से जुड़ी अहम बात लिए हैं। तकनीकी तरक्की और सामाजिक बदलाव के दावों के इस दौर में भी आधी आबादी घरेलू हिंसा का दंश झेल रही हैं। गांवों-कस्बों में ही नहीं, उच्च शिक्षित शहरी तबके में भी स्त्रियां हिंसा की शिकार हैं। वर्ष 2019-2021 में आए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 आंकड़ों के मुताबिक 18 से 49 वर्ष की आयु के बीच की 29.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने घरेलू एवं यौन हिंसा का सामना किया है। इतना ही नहीं, 18 से 49 वर्ष की आयु की 3.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ी। दर्ज करवाये गए इन आंकड़ों के अलावा बड़ी संख्या ऐसे मामले भी होते हैं, जिनकी शिकायत तक नहीं की जाती। सर्वे में भी खुलासा हुआ है कि पीड़ादायी हालातों में भी सहायता लेने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तीसरी रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों में गिरावट आई है। इस हिंसक व्यवहार की जड़ लैंगिक भेदभाव की सोच ही है। ऐसे दुर्व्यवहार और हिंसा की प्रवृत्ति को किसी भी धर्म या समुदाय से अलग करके नहीं देखा जा सकता। साझी भावना के आधार पर समझना होगा कि अपने आंगन में तो हर इंसान सम्मान और सुरक्षा उम्मीद रखता है। आशाओं को पोषण देने वाले परिजनों का साथ हिंसा, अपमान एवं उपेक्षा की आंच से बचाने के लिए ही तो होता है। अफसोस कि कई भारतीय महिलाओं को घर में भी सहयोगी और सम्मानजनक माहौल नहीं मिलता।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार व स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अर्थव्यवस्था
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

बंदरगाहों से बढ़ेगा कारोबार-निर्यात

भारत दुनिया की खाद्य टोकरी बनता जा रहा है और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब निर्यात लागत घटने के कारण खाद्य प्रसंस्करण निर्यात और बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि इस समय देश के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ उन्हें समुद्री व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी। यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।

इन दिनों पूरी दुनिया में भारत के बंदरगाह विकास अभियान को सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे भारत का वैश्विक कारोबार तथा निर्यात बढ़ेगा। विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स -2023 में शीर्ष वैश्विक 100 बंदरगाहों में भारत के नौ बंदरगाहों को स्थान मिला है। गौरतलब है कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बढ़ते विदेश व्यापार घाटे, लाल सागर में बढ़ते संकट और कंटेनरों की किल्लत की चिंताओं के बीच बंदरगाहों से विदेश व्यापार बढ़ाने और निर्यातकों की सहायता के लिए अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत शिपिंग कॉरपोरेशन बड़े कंटेनर जहाज चलाएगी। बंदरगाह शुल्क में कटौती की जाएगी तथा निर्यात की खेपों को जल्दी भेजने के लिए प्रक्रिया में तेजी के उपाय शामिल हैं। 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर नए तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए अपने संदेश में कहा कि यह टर्मिनल भारत के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सितारा है। इस नए टर्मिनल से वीओ चिदंबरनार पोर्ट के सामर्थ्य में भी विस्तार होगा। खास बात यह भी है कि बंदरगाह से निर्यात बढ़ाने के नए फैसलों से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्यात भी बढ़ेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक देश दुनिया की खाद्य टोकरी बनता जा रहा है और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब निर्यात लागत घटने के कारण खाद्य प्रसंस्करण निर्यात और बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि इस समय देश के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ उन्हें समुद्री व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। विगत 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वधावन देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी। यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि भारत की 7517 किमी लंबी समुद्री तटरेखा है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करती है। देश के विशाल समुद्र तटों पर, 13 प्रमुख बड़े और 212 छोटे बंदरगाह हैं।

भारतीय बंदरगाह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक व्यापार के लिए शताब्दियों से महत्वपूर्ण बने हुए हैं और बंदरगाहों से विदेश व्यापार लगातार बढ़ता गया है। इस समय भारत का माल्रा के हिसाब से 95 फीसदी और मूल्य के हिसाब से 70 फीसदी व्यापार

बंदरगाहों के माध्यम से होता है। निसंदेह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होने के कारण भारतीय बंदरगाहों ने समुद्री (तटीय) राज्यों को देश में औद्योगिक विकास के महेनजर पसंदीदा स्थल बना दिया है। परिवहन संबंधी न्यूनतम बाधाओं के साथ-साथ लॉजिस्टिक लागत में कमी बंदरगाहों के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण है। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में भारत अपने बंदरगाहों को समुद्री व्यापार की धुरी बनाने के लिए लगातार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। निजी बंदरगाहों को प्रोत्साहन दिया गया है। भारत कार्गो और जहाजों को संभालने में अपनी दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से अपने बंदरगाहों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। वर्ष 2015 में सागरमाला कार्यक्रम के लॉन्च होने के बाद से बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। मार्च 2022 तक सागरमाला कार्यक्रम के लिए 5.40 लाख करोड़ रुपए की निर्धारित लागत वाली कुल 802 परियोजनाओं में से 1.12 लाख करोड़ रुपये की 221 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4.28 लाख करोड़ रुपये की 581 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति प्रदान की जा रही है। ज्ञातव्य है निजी भागीदारी बंदरगाह आधारित विकास की मुख्य रणनीति है। इस संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की सभी परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत सूचीबद्ध हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो समुद्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (एनएलजी) जनवरी, 2023 में शुरू हुआ है, वह एक ऐसा वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है जो लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को आईटी के माध्यम से जोड़ता है। इसका उद्देश्य लागत और समय की देरी को कम करते हुए दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। सरकार ने बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी हुई है। इसके अलावा, 11.8 अरब डॉलर के योजनाबद्ध आउटले के साथ समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) भी अत्यधिक लाभप्रद है।

अब मेरी टाइम इंडिया मिशन 2030 के तहत बंदरगाहों के विकास और लॉजिस्टिक लागत घटाकर समुद्री अर्थव्यवस्था से देश को लाभांवित करने का नया अध्याय आगे बढ़ रहा है। इन सबके साथ-साथ वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (जीएमआईएस) के दौरान तय किए गए व्यापक रोडमैप के साथ समुद्री अमृतकाल विजन 2047 भारत के समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। निःसंदेह सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा समन्वित रूप से किए जा रहे समुद्री विकास और बंदरगाहों के विकास के रणनीतिक प्रयासों के अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन दुनियाभर में माल ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और वरीयता वाला माध्यम है। हम उम्मीद करें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बंदरगाहों से निर्यात बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उनके कारगर क्रियान्वयन पर शुरू से ही ध्यान दिया जाएगा। वधावन देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में भारत के समुद्री व्यापार की नई धुरी बनेगा। पीएम गति शक्ति योजना, नई लॉजिस्टिक नीति और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का सफल क्रियान्वयन रफ्तार से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था को 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय और 2047 तक देश को विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

जीवन का मार्गदर्शन करती है अंतःकरण की आवाज

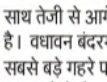

संकलित
दर्शन

हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है, लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज थी। इसी कारण गांधीजी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है। भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती है। जब हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करते हैं तो अंतरात्मा से हमारा संपर्क कमजोर हो जाता है।

जब काम बड़ा हो तो बुद्धि से काम लेना चाहिए

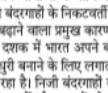

संकलित
प्रेरणा

गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और इससे संबंधित एक कथा है। शास्त्रों के मुताबिक, एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी के बीच प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे पहले संसार का चक्कर लगाकर लौटता है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मयूर यानी मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, जो कि मोर की अपेक्षा बहुत धीरे चलता है। कार्तिकेय तो अपने वाहन मयूर पर बैठकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा है तो उन्होंने विचार किया कि अगर मैं चूहे पर बैठकर संसार की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कार्तिकेय ये प्रतियोगिता जीत जाएंगे। उन्होंने कुछ सोचा और फिर शिव-पार्वती की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। गणेश जी ने कहा कि मेरा संसार को मेरे माता-पिता ही हैं। गणेश जी की बुद्धिमानी से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पुत्र गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। हालांकि इस बात से कार्तिकेय स्वामी गणेश जी के साथ ही शिव-पार्वती से भी नाराज हो गए थे। नाराज होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। ये पर्वत वर्तमान में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहां है, वहां स्थित है। गणेश जी तो प्रथम पूज्य बन गए, लेकिन नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव-पार्वती ने बहुत कोशिशें कीं। जब कार्तिकेय स्वामी की नाराजगी दूर नहीं हुई, तब शिव-पार्वती ने तय किया कि अब से वे हर अमावस्या और पूर्णिमा पर बारी-बारी से कार्तिकेय से मिलने पहुंचेंगे। मान्यता है कि इसी कथा की वजह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव-पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजित रहते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

'मेक इन इंडिया' से भारत को कितना लाभ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की थी। इस योजना को 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में यह योजना कितनी कामयाब हुई, इस पर सभी के अपने-अपने विचार हो सकते हैं। कोई इसी पानी के आधे भरे गिलास की तरह देखेगा, तो कोई खाली। हालांकि मेक इन इंडिया की एक शाखा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार देश में पिछले लगभग 10 वर्षों में अरबों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर दिखते हैं। मेक इन इंडिया सरकार की अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री हमारे देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ने की बात कहते हैं। - वेदैव उपाध्याय, दुर्ग

ट्रेंड

'मन की बात' अनूठा मंच

एक विशेष प्रतिष्ठित 'मन की बात' 10 वर्षों से अनूठा मंच बन गया है। भारत की आवाज का जहन बनाता है और राष्ट्र की लगातार ताकत का प्रदर्शन करता है।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

दलितों की हो रही उपेक्षा

हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साफ़ है कि पार्टी में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, वरना है तो आगे क्या होगा? ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खत्म कर दें।
-मायावती, बसपा प्रमुख

बेंगलुरु टेक समिट

भारत की तकनीकी प्रगति के केंद्र के रूप में, बेंगलुरु वह जगह है जहां परिवर्तन शुरू होता है, लगातार पनपता है और सहयोग उड़ान भरता है। यह वास्तविक ऊर्जा शक्ति के सबसे बड़े केंद्र तो बेंगलुरु टेक समिट 2024 में एक साथ आती है।
-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

हमें अपने सैनिकों पर गर्व

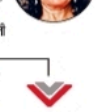

अटारी सीमा पर हमने बहुत अच्छा समय बिताया। अपने सैनिकों और देश पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इतना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। फिल्म 'सावरकर' लिखेमाखते ने 4 अक्टूबर को आ रही है।
-मुरुड रंधावा, गायक-संगीतकार

करंट अफेयर

माइक्रोप्लास्टिक अध्ययन की पहली प्रयोगशाला स्थापित

सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा पिछले दशक में माइक्रोप्लास्टिक पर किए गए अध्ययन ने गोवा के तट पर किस हद तक प्रदूषण है, इसे उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोना पाउला स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने राज्य और केंद्र सरकारों के आंशिक सहयोग से 2013-14 में माइक्रोप्लास्टिक पर अपना शोध शुरू किया था। सीएसआईआर की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. माधुआ साहा के नेतृत्व में शोधकर्तालों की एक टीम प्लास्टिक की बोतलों और अन्य कचरे से अटे पड़े समुद्र तटों से नमूने एकत्र कर रही है, ताकि माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी और प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के निदेशक डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि समस्या यह है कि पानी (नदियों और समुद्र) में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक भोजन में और मानव शरीर में प्रवेश करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है, जल प्रणाली में प्रवेश करता है, तथा तत्पश्चात मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के माध्यम से मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है।

ऑफ बीट

नकारात्मक भावनाओं की रोक है भोजन का प्रयोग

क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप उदास, ऊबे हुए या चिंतित होते हैं तो आपकी खान-पान की आदतों में कोई बदलाव आता है?

कई लोगों का कहना है कि जब वे परेशानी में होते हैं तो इससे निपटने में मदद के लिए वे अधिक या कम खाना खाते हैं। यद्यपि यह एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है लेकिन इससे खाने का आनंद खत्म हो सकता है और यह कष्टकारी हो सकता है तथा शर्म एवं आत्म-आलोचना की अन्य भावनाएं भी पैदा कर सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आहार संस्कृति अपरिहार्य है और खाने, भोजन एवं शरीर की छवि के साथ हमारा रिश्ता जटिल और भ्रामक हो सकता है। भावनात्मक भोजन आम बात है भावनात्मक रूप से भोजन तब होता है जब आप मुश्किल भावनाओं से निपटने के लिए खाना खाते हैं। शोध से पता चलता है कि लगभग 20 प्रतिशत लोग नियमित रूप से भावनात्मक रूप से भोजन करते हैं। किशोरों और महिलाओं में इसका प्रचलन अधिक है। पंद्रह सौ से अधिक किशोरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 34 प्रतिशत किशोर उदास होने पर भावनात्मक रूप से भोजन करते हैं जबकि 40 प्रतिशत किशोर चिंतित होने पर भावनात्मक रूप से भोजन करते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 30 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

आतंक का खात्मा

इस्राइली सेना के बेरुत के दहिखेह पर हवाई हमला करके चरमपंथी समूह हिज्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह (64) को मार गिराने के दावे की पुष्टि हिज्बुल्लाह ने कर दी है। इस्राइल और हिज्बुल्लाह के संघर्ष में संगठन के सबसे ताकतवर नेता की मौत से यकीनन हिज्बुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। तीन दशक से ज्यादा समय से वह हिज्बुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। अपने लेबनानी शिया अनुयायियों के आदर्श और अरब तथा इस्लामी जगत के लाखों लोगों के बीच सम्मानित नसरुल्लाह को सैयद की उपाधि दी गई थी। इस्राइल के 'चीफ ऑफ स्टाफ' लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा है कि नसरुल्लाह का खात्मा अंत नहीं है। मतलब यह कि इस्राइल की तरफ से अभी

और भी भीषण हमले होने हैं। उधर, हिज्बुल्लाह भी अपने चीफ की मौत के बाद ज्यादा आक्रामकता से प्रति हमले करेगा। शनिवार को उसकी तरफ से इस्राइल की तरफ दर्जनों रॉकेट दागे गए। इस्राइली हमलों से दक्षिणी बेरुत के उपनगरों और पूर्वी लेबनान में धुएं का गुब्बार छाया गया। शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। अनेक लोग चौराहों, समुद्र तटों या अपनी कारों में सोए। राजधानी के ऊपर पहाड़ों की ओर जाने वाली सड़कों पर सैकड़ों लोग पैदल ही पलायन करते देखे गए। पलायन कर रहे लोगों की गोद में बच्चे और हाथों में जरूरी सामान थे। लेबनान की राजधानी में मौजूदा संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदलने की प्रबल आशंका है। इसी हफ्ते लेबनान पर हमलों में सात सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में तब्दील हो चुकी अनेक इमारतों में हताहतों की तलाश की जा रही है। ईरान की तरफ से भी अब ज्यादा खतरा पैदा हो गया है क्योंकि जिस हवाई हमले में नसरुल्लाह मारा गया है, उसी हमले में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरान के अर्धसैनिक संगठन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल अब्बास निलपोरुशान की भी मौत हो गई। यह ईरान के लिए नवीनतम क्षति है। ईरान ने एहतियातन अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया है। कहना होगा कि लेबनान के मौजूदा घटनाक्रम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की कोशिशों पर विराम लग गया है। जिस प्रकार से इस्राइल ने लगातार इमारतों को निशाना बनाने की वक्ती रणनीति अपनाई है, उससे लगता नहीं है कि वह तनिक भी थमना चाहेगा। संघर्ष के और भीषण टकराव और पूर्ण युद्ध में तब्दील होने की आशंका है।

दिव्यांग बच्चों को संरक्षण

पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे तथा उन कार्रवाई करे। बाल संरक्षण पर हुए नौवें नेशनल एनुअल स्टेकहोल्डर वर्कशॉप को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा। दिव्यांग बच्चों को उनकी शारीरिक चुनौतियों के साथ-साथ समाज में मौजूद गलत धारणाओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति मिल कर और भी भेदभाव पैदा करती हैं। न्यायिक व्यवस्था में पुनर्स्थापनात्मक न्याय के

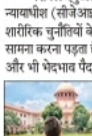

तरीकों को शामिल करने पर जोर देते हुए उन्होंने बच्चों की शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने की बात भी की। सीजेआई ने समानता, सम्मान और भेदभावरहित व्यवहार बच्चों का मौलिक अधिकार बताया। पॉलसी बनाने वालों को उन्होंने सेक्सुअली अफेंस से पीड़ित बच्चों का डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाने को प्राथमिकता देने की बात की। कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए न्याय तक पहुंचने का रास्ता सुविधाजनक हो तथा बच्चों की छोटी-छोटी कमजोरी को समझने के लिए न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग लेने की बात भी की। जस्टिस चंद्रचूड़ की दो बेटियां दिव्यांग हैं इसलिए दुनिया को देखने का उनका नजरिया प्रभावित हुआ है, जिन्हें वे विशेष मानते हैं। देश में बच्चों की कुल संख्या का 1.7% भाग दिव्यांग बच्चों का है। संविधान के अनुच्छेद 26 में दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। परंतु कुल दिव्यांगों में आधे से अधिक अशिक्षित हैं। परिवहन, अवरोधों को हटाना, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में संशोधन के साथ ही दिव्यांगजा पेंशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं भी हैं। स्वरोजगार के लिए उन्हें ऋण दिए जाने की भी सुविधा दी गई है परंतु अपने समाज में दिव्यांगों के प्रति अनुचित बर्ताव किया जाता है। उनके साथ होने वाले यौन शोषण पर आज तक कोई लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। दिव्यांगों के प्रति दया-भाव रखने से ज्यादा जरूरी है, उनके साथ भेदभाव रोका जाए और गलत धारणाओं पर लगाम लगाई जाए। पुलिस, न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशासन को भी इन खास बच्चों के प्रति अपना रवैया बदलने के साथ ही उनके प्रति सम्मान का भाव लाना सीखना होगा।

परिधि/ राजीव मंडल

अब बोझ नहीं बनेंगे मरीज

देश में इच्छामृत्यु को लेकर एक बार फिर से बहस तेज होने के आसार हैं। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। यह ऐसी स्थिति है जब मरीज गंभीर और न ठीक होने वाली बीमारी से जूझ रहा हो। उसके ठीक होने की कोई उम्मीद न बची हो।

केंद्र सरकार ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए लाइफ सपोर्ट जारी रखना बेमानी हो और मरीज के परिवार या प्रतिनिधि भी इस बात से सहमत हों, तो अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की अनुमति से लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। अलबत्ता, इस मसले पर बहस कई बरस से चल रही है। मरीज के स्वस्थ होने की उम्मीद न के बराबर होने के बावजूद परिवार समाज के दबाव में रहता है। निःसंदेह इस तरह की स्थिति में परिवार के लोग भावनात्मक बोझ तले दबे रहते हैं। आर्थिक और भावनात्मक बोझ-ये दो बड़ी वजह हैं, जिनके कारण परिवार पैमाल हो जाते हैं। यह स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं कही जाएगी। इस लिहाज से सरकार का यह कदम क्रांतिकारी माना जाएगा। हां, इसका दुरुपयोग न हो इस बात का खास ख्याल रखना हर किसी के लिए जरूरी होगा। हमने देखा है किस तरह जनता की भलाई के लिए लाए गए फैसलों या नियमों का बड़ी संख्या में लोग बेजा इस्तेमाल करते रहे हैं। इस मामले में भी इस बात का डर बना रहेगा कि कोई इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा?

मरीज की ओर से इस पर फैसला कौन करेगा? डॉक्टरों और अस्पतालों को भी ऐसे मामलों में बेहद सतर्क रहने की दरकार है। आए दिन इस तरह की खबरें सुर्खियां बनती हैं कि लोग लालच में आकर अपने खून के रिश्तों को दगा दे गए। बहरहाल, इस तरह की नामुराद्मीदी और मनोबल को तोड़ने वाली खबरों के बीच सरकार की इस पहल की सराहना की जानी चाहिए। इस फैसले पर पहुंचने से पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और फिर एक अन्य मेडिकल बोर्ड द्वारा मरीज की स्थिति जांच की जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में मरीज और उसके परिवार की स्वायत्तता का सम्मान किया जाए। यह निर्णय निश्चित रूप से एक जटिल मुद्दे पर एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

जहर हो चुका है भू जल

दिल्ली

पंकज चतुर्वेदी

देश की राजधानी की आबादी बढ़ती जा रही है, और उसी गति से यहां पानी की मांग भी बढ़ रही है। यमुना से जल निकालने के प्रयास असफल हो रहे हैं, और करोड़ों रुपये खर्च करके भी दिल्ली की सीमा में 'रिवर' को 'सीवर' बनने से नहीं रोका जा सका है। दिल्ली में सारे साल पानी वितरण का तंत्र जिन टैंकर पर टिका है, उनकी जलापूर्ति भूजल के ऐसे स्रोतों से हो रही है, जो जहर बन चुके हैं, और उस जल को शुद्ध-निरापद बनाने के न तो कोई उपाय हैं, और न ही प्रयास। कितना दुखद है कि मजबूरी में लोग उस जल का प्रयोग कर रहे हैं जो बीमार बना रहा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खतरनाक रसायनों से परिपूर्ण है, हड्डी के रोग, दांतों की कमजोरी से लेकर कैंसर जैसे रोग उपजा रहा है। सीमा से बहुत अधिक फ्लोराइड वाले इलाकों में अलीपुर, द्वारका, नजफगढ़, महरौली, चाणक्यपुरी, कंझावला, रोहिणी, सरस्वती विहार, पटेल नगर शामिल हैं जबकि कैसरकाफ आर्सेनिक सीलमपुर, ठिकिंस कालोनी के भूजल में अधिक है। अलीपुर, नरेला, मंडिल टाउन, द्वारका, कापसहेड़ा, नजफगढ़, दिल्ली कैंट, बर्सत बिहार, कंझावला, रोहिणी, सरस्वती विहार, पटेल नगर, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन के पानी में लवणता का आधिक्य है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देती है। इससे हड्डियों में मुड़ाव होने से लेकर जोड़ों में दर्द की दिक्कत होती है। आर्सेनिक की अधिक मात्रा से त्वचा रोग, नेत्र रोग, कैंसर, फेफड़ों और किडनी की बीमारी होती है। क्यों लवणता बढ़ने से ब्लड प्रेशर और पथरी की शिकायत हो सकती है। एक तो दिल्ली में भूजल और गहराई में जा रहा है, उस पर गुणवत्ता भी खराब हो रही है।

सीजीडब्ल्यूबी ने दिल्ली की 34 तहसीलों में भूजल का आकलन किया है, जिनमें से प्रत्येक को मूल्यांकन इकाई कहा जाता है। इन 34 मूल्यांकन इकाइयों में से 13 (38%) को 'अति-दोहित', 12 (35%) को 'गंभीर', चार (12%) को 'अर्ध-गंभीर' और पांच इकाइयों (15%) को 'सुरक्षित' श्रेणी में रखा गया। राजधानी में भूजल की उपलब्धता सालाना 291.54 मिलियन घन मीटर है। पाताल खोद कर निकाले गए पानी से यहां 47 हजार पांच सौ हैक्टेयर खेत सींचे जाते हैं। 142 मिलियन घन मीटर पानी कारखानों और पीने के काम आता है। दिल्ली जल बोर्ड सालाना 100 एमजीडी पानी जमीन से निकालता है।

गुणवत्ता के पैमाने पर यहां का भूजल लगभग जहरीला हो गया है। जहां 1983 में यहां 33 फुट गहराई पर पानी निकल आता था, आज यह गहराई 132 फुट हो गई है और उसमें भी

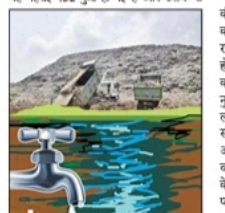

नाइट्रेट, फ्लोराईड और आर्सेनिक जैसे रसायन बेहद हानिकारक स्तर पर हैं। सनद रहे कि पाताल के पानी को गंदा करना तो आसान है, लेकिन उसका परिशोधन करना लगभग असंभव। जाहिर है कि भूजल के हालात सुधारने के लिए बारिश के पानी से रिचार्ज और उसके कम दोहन की संभावनाएं खोजनी होंगी और यहां से ज्यादा पानी नहीं लिया जा सकता।

आखिर, दिल्ली के गर्भ के जल को जहरीला कौन बना रहा है? महानगर में कूड़े का सही तरह से प्रबंधन न होना। कूड़े के तीन विशाल पहाड़ और उनका हर दिन बढ़ता कद, सारी दुनिया से बैष-अवैध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कूड़े का आना और उसके गैर-वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण से उपजे खतरनाक रसायन बहुत चुपके से धरती में गहरे तक समा गए और जीवनदायी जल को जहर बना दिया। ई-कचरे के लगभग 97 फीसद को अवैज्ञानिक तरीके से जला कर या तोड़ कर कीमती धातु निकाली जाती हैं और शेष को यूं ही कहीं फेंक दिया जाता है। इससे रिसने वाले रसायनों का एक अदृश्य लेकिन भयानक तथ्य यह है कि इस कचरे की वजह से पूरी खाद्य शृंखला बिखर रही है। ई-कचरे के आधे-अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्त्व मिल जाते हैं, जो पेड़-पौधों के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। इसके चलते पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और जिसका सीधा असर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर होता है। पारा, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, सिलिकॉन, निकेल, जिंक, मैंगनीज, कॉपर आदि भूजल पर भी असर डालते हैं।

सबसे खतरनाक कूड़ा तो बैटरियों, कंप्यूटरों और मोबाइल का है। इसमें पारा, कोबाल्ट, और न जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। कैडमियम से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुएं और धूल के कारण फेफड़े और किडनी, दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कंप्यूटर का वजन लगभग 3.15 किग्रा. होता है। इसमें 1.90 किग्रा. सीसा, 0.693 ग्राम पारा और 0.04936 ग्राम आर्सेनिक होता है, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री 'गलती-सड़ती' नहीं है, और जमीन में जज्ब हो कर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। ठीक इसी तरह का जहर बैटरियों और वेकार मोबाइलों से भी उपज रहा है। इनसे निकलने वाले जहरीले तत्त्व और गैसें मिट्टी और पानी में मिल कर उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। फसलों और पानी के जरिए ये तत्त्व हमारे शरीर में पहुंच कर बीमारियों को जन्म देते हैं।

बैटरियों से निकलने वाला तेजाब, नालों के रिसाव, वाहन प्रदूषण का बरसात या ओस के साथ मिल कर धरती पर गिरना और उसे सोख लिए जाने जैसे कई कारक हैं, जिनने धरती में जहर भर दिया। यहां के खेत और यमुना के कछार में सब्जी उगाने में बेशुमार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने गहरे तक धरती की कोख के पानी को विष में बदला है। दिल्ली में जल आपूर्ति बगैर भूजल के संभव नहीं है, और ऐसे जल के सेवन से बढ़ी आबादी के बीमार होने से लोगों पर आर्थिक-सामाजिक बोझ बढ़ रहा है, इंसानी कार्य क्षमता और आर्थिक तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। जरूरी है कि दिल्ली के आसपास 100 किमी. दायरे में कचरे की खंती बनाने, कचरा निष्पादन-खासकर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के-कड़ी और स्पष्ट नीति बने। इस समूचे इलाके में जैविक खेती अनिवार्य की जाए।

(लेखक के निजी विचार हैं)

> दिल्ली के गर्भ के जल को जहरीला कौन बना रहा है? महानगर में कूड़े का सही तरह से प्रबंधन न होना। कूड़े के तीन विशाल पहाड़ों का हर दिन बढ़ता कद, इलेक्ट्रॉनिक कूड़े के गैर-वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण से उपजे खतरनाक रसायन चुपके से धरती में गहरे तक समा गए और जल को जहर बना दिया। ई-कचरे के लगभग 97 फीसद को अवैज्ञानिक तरीके से जला कर या तोड़ कर कीमती धातु निकाली जाती हैं और शेष को यूं ही कहीं फेंक दिया जाता है

990 अरब डॉलर पर पहुंचेगा एआई का वैश्विक बाजार

- कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का वैश्विक बाजार 2027 तक 990 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है
- एक रिपोर्ट के मुताबिक, एआई से संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर का बाजार अगले तीन वर्षों में सालाना 40 से 50 फीसद की दर से बढ़ेगा
- रिपोर्ट में कहा गया है कि आपूर्ति और मांग में कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव से अस्थिरता पैदा हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक और टिकाऊ वृद्धि यही रहेगी

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

इस्राइल द्वारा नसरुल्लाह का खात्मा बड़ी सफलता है, लेकिन इससे हिज्बुल्लाह से उसे खतरा कम नहीं हो जाएगा। बल्कि जब भी इस्राइल ने किसी उग्र नेता का सफाया किया है, उसके स्थान पर पहले से कहीं ज्यादा उग्र और कट्टर नेता उभर आया। इसलिए नसरुल्लाह के स्थान पर और भी कट्टर सोच वाला सरगना आ सकता है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक@Chellaney

हठयोग साधें

श्रीराम शर्मा आचार्य

भारतीय अध्यात्म विद्या के जानकारों ने चार प्रकार के योग माने हैं-मंत्रयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग। हठयोग में व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक अपने आपको बाहरी विषयों और विचारों से अलग करना चाहता है। मान लीजिए, हमारा मन बार-बार किसी प्रकार की खाने की वस्तु में जाता है, हठयोग द्वारा मन को उस वस्तु के प्रति उदासीन किया जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ को सेब से बड़ा प्रेम था। जब सेब को देखते तो उनका मन और सब वातें भूल कर उसी का चिंतन करने लगता था। इस प्रकार मन के चंचल हो जाने से विचार में विक्षेप हो जाता था। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सेब खरीदा और उसे अपने पढ़ने की मेज पर सामने ही रख लिया। प्रति दिन उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते थे। इस प्रकार आठ दिन तक उन्होंने उसकी ओर देखा। जब वह सूख गया तो उसे उठा कर फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने एक महीने तक अभ्यास किया और कई सेवों को सड़ाकर फेंका। इसके बाद उनके मन में सेब की वात कभी नहीं आती थी। बार-बार वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने से वे शिथिल हो जाते हैं और मन वश में हो जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का निर्देश अपने आपको देता है, उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। उसमें अज्ञात शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब मनुष्य प्रति दिन यह अभ्यास करता है तो सुंदर से सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता। इसका एक उदाहरण 'साइकोलजी एंड मोरल्स' नामक पुस्तक में दिया गया है। एक व्यक्ति को कोकीन खाने की आदत पड़ गई थी। वह चाहता था कि मैं इस हानिकारक आदत को छोड़ दूं पर प्रयत्न करने पर भी वह नहीं छूटती थी। वह अपने पास कोकीन नहीं रखता था पर जब कभी कोकीन की दुकान के पास से निकलता तो अनायास ठहर जाता और कोकीन खरीद कर खा लेता। इस लत को नष्ट करने के लिए उसे 'मति निर्देश' का अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास में वह व्यक्ति कल्पना में अपने को उस दुकान के पास से निकालता और उसकी कुछ भी परवाह न करता हुआ ध्यान करता था। इस प्रकार के अभ्यास से कुछ समय में उसमें अद्भुत परिवर्तन हो गया। अब उस व्यक्ति को उस दुकान से बार-बार निकल जाने पर भी उसकी याद नहीं आती थी और इससे उसका कोकीन का व्यसन छूट गया। हठ ऐसी क्रिया है जिससे असाध्य भी साध्य हो जाता है।

रीडर्स मेल

प्रेममय होने पर ही मिलेगी शांति

बिना प्रेम संसार में शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता लेकिन प्रेम की बात की जाए तो ज्यादातर लोग प्रेम को सेक्स का पर्याय समझ बैठे हैं जबकि प्रेम अलग चीज है। समर्पण की चीज है। भावना की चीज है। निर्वहन की चीज है जबकि सेक्स शारीरिक सुख की चीज है। हवस-वासना की चीज है। जबरदस्ती की चीज है। प्रेम का दायरा सेक्स की अपेक्षा लाख गुना व्यापक है। प्रेम कहां नहीं है। मानव मानव के बीच में है। रिश्तेदारों के संग है, ईश्वर से प्रेम होता है। मानव का प्रकृति के कण-कण से प्रेम होता है लेकिन सेक्स की बात करें तो यह दो विपरीतलिंगी के बीच बहुत ही संकीर्ण दायरे में संभव हो पाता है। लोगों को अपनी सोच विकसित करने की आवश्यकता है। ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम जिसे समझ पाना आसान बात नहीं है। अगर प्रेमपूर्वक जीवन जिया जाए तो न केवल व्यक्ति, बल्कि समाज और राष्ट्र, सबका कल्याण संभव है। हमारे सामाजिक परिवेश में युवक-युवती चंद मिनट बात भी कर लें तो देखने वाले की नजरों में प्रेमी-प्रेमिका हो जाते हैं, जो देखने वालों का नजरिया मात्र होता है। सच्चाई इससे आगे बहुत कुछ हो सकती है। आज प्रेम सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं रह गई है, बल्कि प्रेम काफी व्यापक अर्थों में लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। आज हर कोई प्रेम का भूखा है। हर कोई प्रेम पाना चाहता है। प्रेम में डूब जाना चाहता है क्योंकि प्रेममय संसार में ही समृद्धि है, उसी में शांति है, उसी में विकास है। इस बात को समझने की जरूरत है। प्रेम को सींचने की जरूरत है।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

हिन्दीभाषी छात्रों के साथ अभद्रता

कुछ हफ्ता पहले सिलीगुड़ी में एसएससी जीडी परीक्षा देने गए कुछ हिन्दीभाषी छात्रों के साथ अभद्रता का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उसी प्रकार की एक घटना असम के धुबरी में घटित हुई है जहां पर कुछ असामाजिक तत्त्वों ने अपने ही राज्य के परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को बाहरी राज्य के समझ कर पीटना शुरू कर दिया। असम के अंदर अपने छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कदापि नहीं किया जा सकता। इस पर राज्य एवं केंद्र को गंभीरता से कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसे कृत्य करने वाले लोग बाज आएं।

समराज चौहान, कार्बी आंग्लांग, असम

शिक्षा के मंदिर में अंधविश्वास

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मन को विचलित और झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें स्कूल के प्रबंधकों ने कक्षा 2 के 7 वर्षीय मासूम छात्र की हत्या इसलिए कर दी कि बलि दिए जाने से स्कूल की प्रसिद्धि और प्रगति हो जाएगी। अंधविश्वास के चलते शिक्षा के मंदिर की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस घटना से कैसे सबक लिया जाए यह भी चिंता का विषय है। आदमी के चांद पर पहुंचने के बावजूद देश में तंत्र-मंत्र और कर्मकांड की सैकड़ों घटनाएं सामने आती हैं जिनसे मन दुखी और शर्मसार होता है, मन में घृणा का भाव पैदा होता है। दुख इस बात का है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड एवं जादू-टोने की चपेट में देश का शिक्षित वर्ग भी जकड़ा हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड तो गरीब और वेसहारा महिलाओं को अंधविश्वास के चलते 'डायन' के रूप में प्रस्तुत करते हुए जान से मार तक दिया जाता है। यह बुराई नित बढ़ने भी ही है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

भारत को हासिल क्या

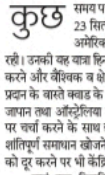

क्वाड

गिरीश चंद्र पाण्डे

कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21-23 सितम्बर, 2024 की तीन दिनी अमेरिका यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण रही। उनकी यह यात्रा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के वास्ते क्वाड के अन्य सदस्य देशों यानी अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के साथ ही यूक्रेन और गाजा में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर भी केंद्रित थी।

जहां तक विलमिंगटन डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 21 सितम्बर, 2024 को आयोजित क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 'क्वाड' लीडर्स शिखर सम्मेलन में प्राप्त भारत की उपलब्धियों का प्रश्न है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से अप्रत्यक्ष तौर पर चीन को संदेश देते हुए कहा कि हम सभी नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, और भारत विस्तारवाद के स्थान पर विकासवाद का समर्थक है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समुद्र और आसमान, दोनों सुरक्षित नहीं हैं, तो उनका संकेत चीन की तरफ था क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन इसलिए कब्जे का प्रयास कर रहा है कि उसमें उसके देश का नाम शामिल है। ऐसे बेहूदे तर्कों के आधार पर जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाता है, तो स्वयं तो उपहास का पात्र बनता ही है, साथ में पूरी दुनिया को भी संकट में डालता है। मोदी की यात्रा ने भारत को 14 सदस्यों वाले हिन्द-प्रशांत आर्थिक समृद्धि ढांचे (आईपीईएफ) को और नजदीक लाने में भी सहायता की है। यह पहल क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2022 में शुरू की थी।

क्वाड-अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान-चार देशों का चौमुट है, जो हिन्द-प्रशांत के भीतर मौजूद समस्याओं से निपटने और क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के

लिए बना है। इसीलिए चीन इस संगठन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करता रहता है। आज जबकि कई वैश्विक मंचों की असहमियत नहीं रह गई है, ऐसे में क्वाड लीडर्स के सम्मेलन में क्वाड के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता और कहना कि यह संस्था बनी रहेगी, सदस्य देशों के बीच आपसी साझेदारी होगी तथा तालमेल भी बना रहेगा तो निश्चित ही पर चीन को नागवार ही गुजरेगा। क्वाड के चारों नेताओं की बातचीत के बाद विलमिंग्टन घोषणापत्र जारी किया गया। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि शोध, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, चुनियादी ढांचा, इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, महत्त्वपूर्ण और उभरती तकनीक, तटरक्षक सहयोग, अंडरसी केबल और डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आदि पर भी अपने भावी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। निश्चित तौर पर ये सभी पहलकदमियां क्वाड सहयोग की बढ़ती सार्वभौमिक प्रकृति को रेखांकित करती हैं।

क्वाड नेताओं ने 'इंडो-पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की घोषणा की ताकि क्षेत्रीय साझेदारों को इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और अन्य क्वाड पहलों के उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिल सके ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके और नागरिक समुद्री सहयोग में समुद्री सुरक्षा को लेकर सुधार किया जा सके, अपने जल की निगरानी और सुरक्षा की जा सके, अपने कानूनों को लागू किया जा सके और गैर-कानूनी व्यवहार को रोका जा सके। इस प्रकार क्वाड में भारत की भागीदारी जहां चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगा रही है, वहीं एक ईस्ट पॉलिसी और पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी के अलायंस पार्टनर्स हैं, लेकिन भारत की दिलचस्पी औपचारिक अलायंस में नहीं रही है। इसके बावजूद क्वाड हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और सबके लिए खुला बनाए रखने और इस क्षेत्र के लिए समावेशी रूप के साझा लक्ष्यों को लेकर जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, और चार वर्ष पहले बने इस संगठन ने अब तक जिस प्रकार से सफलतापूर्वक छह शिखर सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं, उससे इस संगठन की प्रासंगिकता निकट भविष्य में और बढ़ेगी और दक्षिण प्रशांत, हिन्द महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की हरकतों से परेशान देश भी इसमें जुड़ते जाएंगे। गौरतलब है कि भारत जहां 2025 में 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा वहीं अमेरिका 2025 में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, कारोबार टावर, नवरोज हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 47
भा.एल.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BIR /CZZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संकलन तथा कानूनी बातों के लिए उत्तरदायी

21.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) यानी वंचित समाज की आबादी है उत्तर प्रदेश में। राज्य की लगभग 40 प्रतिशत लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां की 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है।

आजकल

संयुक्त राष्ट्र में भारत का भारी होता पलड़ा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र निकाय के विस्तार की वकालत भी की है। मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। इससे लगता है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सहमति बढ़ रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैश्विक प्रभाव और सफल कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मुखर पैरवी। फाइल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही वे ऐसे देश भी होने चाहिए, जिन्हें अफ्रीका प्रतिनिधित्व के लिए अनुशंसा करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित तुर्किये के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को झटका दिया है। उन्होंने इस बार कश्मीर का जिक्र नहीं किया। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे से किनारा किया। इससे लगता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सहमति बढ़ रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैश्विक प्रभाव और सफल कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारी होते पलड़े के संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्किये ब्रिक्स का सदस्य देश बनना चाहता है। इसके लिए उसे भारत की मदद जरूरी है। यदि भारत असहमति जता देता है तो उसे सदस्यता मिलना मुश्किल है। ब्रिक्स में इस वक्त ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। भारत इसमें प्रमुख सदस्यों में से एक है। तुर्किये को नाटो देशों के समूह से भी बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए तुर्किये ब्रिक्स देशों की सदस्यता चाहता है।

भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की लक्ष्यपूर्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, परंतु पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। इनमें से प्रत्येक देश के पास ऐसी शक्ति है, जिसका प्रयोग कर वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते हैं। भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। किंतु दुनिया का जो वर्तमान परिदृश्य है, उससे निपटने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या दुनिया का हित साधने के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए मैक्रों को कहना पड़ा कि सुरक्षा परिषद के कामकाज के तरीकों में बदलाव, सामूहिक अपराधों के मामलों में वीटो के अधिकार को सीमित करने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैक्रों की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। वाकई इस समय कई वैश्विक संस्थाएं इसके अभाव में अपनी प्रासंगिकता खोती दिखाई दे रही हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी 15 सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद को पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बताकर आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इसकी संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो इस संस्था से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। याद रहे चीन जवाहरलाल नेहरू की अनुकंपा से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके शशि थरूर की किताब 'नेहरू-द इन्वेंशन आफ इंडिया' में लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने उसे चीन को दे दिया। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वह फाइल देखी थी, जिस पर नेहरू के इन्कार का जिक्र है। अतः कहा जा सकता है कि नेहरू की भयंकर भूल और उदारता का नुकसान भारत आज तक उठा रहा है। जबकि उस समय अमेरिका भारत के पक्ष में था।

भारत का दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। तालिबान की आमद के बाद अफगानिस्तान में किस बेरहमी से विरोधियों और स्त्रियों को रौंदा किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं रह गया है। इजरायल-फलस्तीन और रूस-अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैल चुके इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता। इसका उदाहरण मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर चीन द्वारा बार-बार वीटो का इस्तेमाल करना है। जबकि भारत विश्व में शांति स्थापित करने के अभियानों में मुख्य भूमिका निर्वाह करता रहा है। बावजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी एवं सामुदायिक बहुलता वाला देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है।

साफ है संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति निष्पक्ष नहीं है। कोविड के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मनवतावादी केंद्रीय भूमिका दिखनी चाहिए थी, पर वह महामारी फैलाने वाले दोषी देश चीन के समर्थन में खड़ा नजर आया। अलबत्ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका वैश्विक संगठन होने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उसके एजेंडे में प्रतिबंध लाग करने और संघर्ष की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार शामिल हैं। इस नाते उसकी मूल कार्यपद्धति में शक्ति-संतुलन उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर लंबी चर्चा होगी। इसमें बहुमत से बनी सहमतियों को खारिज करने का अधिकार पी-5 देशों को है। ये देश किसी प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं तो यथास्थिति और टकराव बरकरार रहेंगे। साथ ही यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल भी जाती है तो यह प्रश्न भी कायम रहेगा कि उसे वीटो की शक्ति दी जाती है अथवा नहीं?

हालांकि भारत कई दृष्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हैसियत रखता है, बल्कि वीटो-शक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी इसमें है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों ने अभी इन्हें हाईजैक किया हुआ है। अतः इन देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं।

-प्रमोद भार्गव

सुधार से बढ़ेगी सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता

संयुक्त राष्ट्र की लचर एवं पक्षपाती भूमिका के चलते उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तो यह लगने लगा है कि यदि सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार नहीं किए गए तो संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में परिषद के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन चुकी है। इसीलिए भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का प्रश्न उठाता रहा है। कालांतर में इसका प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देश भी इस प्रश्न की कड़ी के समर्थक बनते चले गए। जी-4 देश ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान इस मांग को निरंतर उठा रहे हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं वीटोधारी देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी अपना मौखिक समर्थन इस प्रश्न के पक्ष में देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से दो तिहाई से भी अधिक देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी 2015 में दे दी थी। इसके चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का अहम मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का भी प्रश्न बन गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होता है तो इसकी सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व की समतामूलक बनाए जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सुरक्षा परिषद में अभी पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः सुधार किया जाता है तो इन देशों की भूमिका भी रेखांकित होगी। निर्विवाद एवं समतामूलक वैश्विक लक्ष्य साधने हैं तो सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी अनिवार्य है। यह संख्या बढ़ाती है तो सुरक्षा परिषद की असमानता दूर होने के साथ इसकी कार्य-संस्कृति में लोकतांत्रिक भावना का समावेश होगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन प्रस्तावों का शामिल होना बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि तो थी, लेकिन परिणाम भारत और इसमें बदलाव की अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आएंगे ही, इसमें संदेह है। असमानता दूर करने के लिए बनाए रखने की भावना अंतर्निहित है, लेकिन वह इन प्रतिबद्धताओं की नजरअंदाज कर रहा है। गौया इस विश्व संस्था के प्रति विश्वास का संकट गहराया हुआ है। नतीजतन इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है।

खरी-खरी

छोटे आदमी का बड़ा पता

डा. प्रदीप मिश्र

पहले जमाने का पोस्टल-एड्रेस आजकल कूरियर-एड्रेस कहलाता है। जितना छोटा आदमी कूरियर-पता, उतना बड़ा। मास्टर प्रसाद का पता है- 'श्री मास्टर प्रसाद, निम्न श्रेणी शिक्षक, राजेंद्र नगर, दक्षिणी बड़े नाले के पार, नत्थू तांबूल भंडार के पीछे, वर्मा जी के मकान के आगे पाँचवीं गली के आठवें मकान के ऊपरी हिस्से का चौथा कमरा, मध्य प्रदेश, भारत।'

बड़े आदमी का पता एकदम छोटा होता है। लिफाफे पर 'अमिताभ बच्चन, जलसा, मुंबई' या इसकी जगह सिर्फ जलसा, मुंबई या सिर्फ अमिताभ बच्चन या बस बच्चन' लिखा हो तो कूरियर वाला बिना किसी दरियाफ्त चिट्ठी अमिताभ बच्चन को सौंप आएगा। पत्र इनकम टैक्स विभाग से हो तोग कि आपने जो टैक्स भरा उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बैंक से लोन लेते वक्त मैंने अपने लंबे पते को एकदम शार्ट में लिखा। सोचा था, इतने छोटे पते से कोई मुझ तक कैसे पहुंचेगा? लेकिन एक दिन उधरी वसूलने वाले मेरे घर पहुंच गए। मैंने पूछा, 'आपको घर का पता कैसे चला?' 'लोन देने वाले और यमराज को किसी का घर ढूंढ़ने के लिए पते की जरूरत नहीं पड़ती।' कहकर वे लोन वसूलने की कार्यवाही करने लगे।

लंबे पते वाला एक छोटा कर्मचारी दफ्तर के पते पर अपनी निजी डाक मंगाता था। कर्मचारी जवान था, इसलिए बास की नजर उसके आने वाले कूरियरों पर रहती थी। एक लिफाफे पर लिखी लिखावट, उन्हें जानी-पहचानी लगी। लिफाफा खोला तो पता चला, उसमें एक केक और प्रेमाष्टक ग्रीटिंग थी। जिससे ज्ञात हुआ कि उनके परिवार वाले के श्रीघ और कर्मचारी के मध्य मधुर संबंध विकसित हो चुके हैं। उन्होंने उसे डांटा, 'तुमने लंबे पते वाले से दोस्ती क्यों की? जबकि मेरे ही आफिस में छोटे पते वाले कई बड़े आफसर काम करते हैं। तुम्हें मेरे छोटे पते वाले स्टेटस का तो खयाल रखना था। खबरदार जो किसी लंबे पते वाले से कोई संबंध रखा तो।'

सोचता हूं, अपने पते को काट-छांटकर छोटा कर डालूं। बड़ा आदमी बनने के लिए पते का छोटा होना जरूरी है।

पोस्ट

हिजबुल्ला के सरगना हसन नसरुल्ला को इजरायल ने निपटा दिया है। आतंक से लड़ने का तरीका तो इजरायल से सीखना चाहिए। जब तक तेहे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, असल में उसे कहते हैं।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

नसरुल्ला के समर्थन में कश्मीर में जुलूस निकाला जाना बहुत चिंताजनक है। यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि नसरुल्ला आतंकवादी था, जो एक आतंकी संगठन को चला रहा था।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

कश्मीर को हिंदुस्थिन बनाने वालों को यह भान नहीं है कि उनके हिजबुल्ला-हमास प्रेम ने भारतीय जनता के एक हिस्से को 'इजरायल' बना दिया है। इजरायल आह्वान करे तो शायद देश की एक बड़ी आबादी उसके समर्थन में उतर आए।
रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

लेबनान सत्तर साल में ईसाई से मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन गया। ईसाई अपने देश में अल्पसंख्यक बन गए। लेबनान ने वही गलतियां कीं, जो भारत ने भी हुईं। आबादी की धार्मिक संरचना बदलती है तो देश बदल जाता है। भारत के लोग इसे हल्के में न लें।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या हिजबुल्ला के मुखिया की मौत के बाद इजरायल का संकट कम होगा?

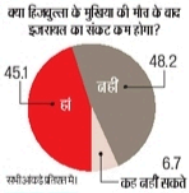

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का अपने बेटे उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण डॉटएनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'प्रीवी' जी स्कीम पर रोस दिया लुटाए, हुआ खजाना रिक्त तो रहे आजन्म पाय। रहे आजन्म फल पाय रुक गया वेतन-भत्ता, उत्तरन लए वंसि कहीं अब कपड़ा-लत्ता! आए जबहि पुराना बंटे मंत्राहल-टीवी, भले बने सिरदर्द बाद में पेंशनी 'प्रीवी'!!
- ओमप्रकाश तिवारी

अजय जायसवाल
रुपए चूसे गीध, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

वंचित समाज को लुभाने को सक्रिय नए दावेदार

राजनीति संभावनाओं का खेल है और यदि यूपी की दलित राजनीति में दूसरे राज्यों के नेता अब संभावनाएं देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसके पीछे बसपा के हाथ से बंचितों की ठोर का धीरे-धीरे खिसकते जाना ही है। इसलिए खबर छोटी जरूर थी, लेकिन खलबली भरी हुई थी कि बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभानेवाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान की कौशांबी के मूरतगंज कस्बे में सभा होने वाली है। सभा हुई भी। ठीकठाक लोगों की जमावड़ा भी रहा और जब पासवान ने भरे सम्मेलन में एलान किया कि वह बंचित समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर लड़ेंगे तो संदेश स्पष्ट था कि उनके लिए एक और लॉबरदार तैयार है, बसपा के एक विकल्प वह भी हैं। यह कहकर कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बार-बार बंचित समाज को डराने का ही काम किया है। आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्षी दल बंचित समाज में डर पैदा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनके रहते आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है, उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि आने वाले चुनाव के लिए उनकी पार्टी संभावनाओं की जमीन तलाश रही है।

अब सवाल यह कि कौशांबी में ही सभा क्यों? तो जवाब यह है कि एक समय जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सिराथू, मंझनपुर और चायल पर बसपा का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब एक पर भी नहीं है। बसपा के नेता दूसरे दलों में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और यदि यहां लोकजनशक्ति पार्टी थोड़ा सा भी लाभ हासिल करने में सफल हुई तो पूरे प्रदेश की दलित राजनीति में उनका भी कोणा स्पष्ट हो जाएगा। इसी उद्देश्य से चिराग ने यूपी में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी को यूपी का सहप्रभारी बनाया है। कौशांबी के बाद चिराग के गौरवपूर्ण, प्रतापगढ़, बलिया, प्रयागराज जिले में भी बंचित समाज सम्मेलन प्रस्तावित हैं।

कौशांबी के मूरतगंज में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान (दाएं से तीसरे) का अभिनंदन करते कार्यकर्ता। फाइल

उत्तर प्रदेश में बंचित समाज में एक बड़ा हिस्सा जाटव समाज का है। इनकी आबादी 21.1 फीसद अनुसूचित जाति (एससी) यानी बंचित समाज की आबादी है। उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की लगभग 40 प्रतिशत लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां की 25 फीसद से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। जिस कौशांबी से चिराग यूपी में पैर जमाने उतरे हैं उस जिले में ही एक तिहाई से ज्यादा 36 प्रतिशत आबादी बंचित समाज की है। आजादी से चार दशक तक कांग्रेस के साथ खड़े रहे बंचित समाज को कांशीराम-मायावती ने अपना बनाकर चार बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की। तकरीबन ढाई दशक तक राज्य का बंचित समाज बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी और बहन जी (मायावती) को ही अपना सच्चा हितैषी समझता था, लेकिन सबको साधने के चक्कर में बसपा प्रमुख ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग एवं सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की राह पकड़ी उससे बंचित समाज का धीरे-धीरे 'हाथी' से मोह भंग होता चला गया। सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती वर्ष 2007 में अकेले ही सत्ता हासिल करने में तो कामयाब रही, लेकिन उसके बाद पार्टी का ग्राफ गिरता गया। अब स्थिति यह है कि बसपा का न लोकसभा-राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और न ही राज्य की विधान परिषद में उसका कोई सदस्य है। वर्ष 2007 में 30.43 प्रतिशत वोट के साथ 206 विधायकों वाली पार्टी का आज विधानसभा में मात्र एक सदस्य है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली पार्टी को सिर्फ 9.39 प्रतिशत वोट मिले।

बंचित समाज में एक दशक पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई। बसपा चारों खाने चित्त होकर शून्य पर सिमट गई। हालांकि हालिया लोकसभा चुनाव में बंचित समाज का रुख सपा-कांग्रेस गठबंधन की ओर रहा। सपा, पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले और कांग्रेस बंचित समाज को भाजपा से आरक्षण एवं संविधान के खतरे की बात समझाने में कामयाब रही जिससे भाजपा 64 सांसद से घटकर 33 पर, जबकि सपा पांच से बढ़कर 37 एवं कांग्रेस के एक से छह सांसद हो गए। वैसे तो अगले विधानसभा चुनाव में दो दशक पुराने इतिहास को दोहराने के लिए मायावती ने इधर-उधर हाथ-पैर मारने के साथ ही अब अपने युवा भतीजे आकाश आनंद को भी पूरी तरह से आगे किया है, लेकिन लोकसभा और पड़ोसी राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनका जरा भी जादू नहीं दिखा। अलबत्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर नगीना से सांसद बनकर बंचितों के एक और नेता के रूप में उभर आए और प्रदेश में बसपा को चुनौती देते हुए अपनी जमीन पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। जाहिर है कि दलित राजनीति के दृष्टिकोण से 2027 का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है।

छत्तीसगढ़ डायरी

सुकमा के संकट पर चुप्पी

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

सुकमा के आदिवासी संकट में हैं। इतकल गांव में एक ही परिवार के पांच आदिवासियों की सामूहिक हत्या के 15 दिन गुजर चुके हैं। वहां 24 गिरफ्तारियों के बाद भी चुप्पी है। ग्रामीण बता रहे हैं कि सत्य कुछ ज्यादा ही कड़वा है। गले के नीचे नहीं उतर रहा। यद्यपि सत्तापक्ष कार्रवाई हो जाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर न्याय यात्रा कर रहा है। बस्तर के सांसद रहे आदिवासी समाज के ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अभी बलीदाबाजार के सत्नामी समाज और कवर्धा साहू समाज के मुद्दों पर आक्रामक हैं। उधर मुश्किल में बस्तर की आदिवासी संस्कृति है। गांव-गांव में तेजी से बढ़ रहे चर्च के साथ निवासियों के व्यवहार में हुए बदलाव की कोई चिंता नहीं कर पा रहा।

दो सप्ताह हो गए। 15 सितंबर, रविवार का दिन था जब ग्रामीणों ने अपने ही गांव के हेड कांस्टेबल मौसम बुच्चा सहित उनके माता-पिता, पत्नी और बहन को घर के दरवाजे पर पीट-पीटकर मार डाला। पिता गांव के बड़ेडे (सम्मानित ओझा) थे। जड़ी-बूटियों से इलाज करते थे। आरोप है कि जादू-टोना के शक में ग्रामीणों ने ऐसा कुकृत्य किया। दिन में 10 से 12 बजे के बीच की इस घटना को याद करके दिल दहल जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई है कि क्षेत्र में नक्सली अभी भी जन अदालत लगाकर सर्वजनिक हत्याएं कर रहे हैं। मुखबिरी का आरोप लगाकर एक या दो लोगों को मारा जाता रहा है। इतकल में तो गांव वालों ने ही दिन दहाड़े पांच आदिवासियों को मार डाला। प्रशासन ने दावा किया कि गांव में बड़ी संख्या में बच्चों और मर्दों की मौत से ग्रामीणों में रोष था। परंतु सच पर्दे से बाहर नहीं आ रहा। आसपास के गांवों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। सिर दर्द, बुखार, हाथ-पैर में सूजन के साथ ही उल्टी-दस्त से मौतें हो रही हैं। सरकारी और ग्रामीणों के आंकड़े में दो से तीन गुना का अंतर है।

सुकमा के इतकल गांव का सबसे कड़वा सच वर्ष 2016 के बाद यहां के 36 में से 29 परिवारों का मतांतरित हो जाना भी है। तब एक महिला किड़नी की समस्या के इलाज के बाद मतांतरित हुई थी। आठ वर्ष में गांव की पूजा पद्धति और संस्कृति ही बदल गई है। आस्था बदल गई है। यह सच जांच का हिस्सा नहीं है। साथ ही इसकी भी किसी को परवाह नहीं कि आमतौर पर सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक चलने वाली चर्च की प्रार्थना सभा घटनावाले दिन 10 बजे ही क्यों समाप्त हो गई थी? प्रार्थना का नेतृत्व कराने वाला कहां चला गया? राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामले कम मिलेंगे जब गांव वालों ने अपने ही गांव के सम्मानित परिवार के पांच लोगों को पीट-पीट कर मार डाला हो। बड़ोडे का परिवार मतांतरित नहीं हुआ था। वह देवगुड़ी में आदिवासी परंपरा का पालन करते थे। मतांतरण के प्रभाव में होने के बाद भी उनकी बेटी और बहू स्वाभाविक रूप से अपने पति, भाई, माता-पिता को बचाते हुए दिन-दहाड़े सामूहिक हत्याकांड की शिकार हो गईं। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव के साथ नक्सलियों की हिंसा ने पहले ही इसे पिछड़ेपन का पर्याय बना रखा है। अब मतांतरण पूरी संस्कृति पर चोट कर रहा है। फिर भी इसकी पड़ताल नहीं हो पा रही कि मतांतरण ने आदिवासी समाज को किस तरह खोखला कर दिया है।

तभी तो बस्तर के सांसद रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के लिए उनके क्षेत्र का यह विषय प्राथमिकता सूची में नहीं है। उनपर भी मतांतरण समर्थक होने का आरोप लग चुका है। कांग्रेस के लिए मतांतरित वोट बैंक हैं। कवार्धा लखमा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार विधायक हैं। अब तो गांव-गांव में अंतिम संस्कार के समय संघर्ष हो रहा है। आदिवासी अपनी श्मशान भूमि पर मतांतरितों को अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते। इस मुद्दे पर बस्तर के नारायणपुर तक में हिंसा भड़क चुकी है। केंद्र और राज्य की सरकारें नक्सलियों को कुचलकर आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मार्च 2026 तक नक्सल मुक्ति की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच नई चुनौती पनप रही है। पांच आदिवासियों की सामूहिक हत्या बदली हुई चुनौती की धमक ही है।

कांग्रेस की न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज (दाएं से तीसरे) और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (दाएं से दूसरे) एवं अन्य। फाइल

इधर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए छह दिनों की कांग्रेस की पदयात्रा दो अक्टूबर को रायपुर में पूरी होगी। यात्रा उसी बलीदाबाजार से शुरू हुई है जहां जून में डीएम-एसपी कार्यालय फूंके जाने के मामले में धिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार हैं। कांग्रेस की मांगें हैं-गिरफ्तार किए गए सत्नामी समाज के युवकों को छोड़ा जाए और कवर्धा में न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज हो। पक्ष और विपक्ष का ध्यान सुकमा तक पहुंच ही नहीं पा रहा। संदेश यह भी है कि मतांतरण विरोधियों की चुप्पी साधे रखने के लिए अज्ञात शक्तियों ने निर्देशित कर रखा है।

****

दैनिक जागरण
अपने कार्य से प्रेम ही जीवन में आनंद का स्रोत बनता है

मन की बात

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर जो प्रसन्नता प्रकट की और भावुक होकर इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को रेखांकित किया, वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि आम जनता से संवाद के इस लोकप्रिय कार्यक्रम के दस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक अनूठी उपलब्धि है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिये प्रधानमंत्री राजनीतिक मुद्दों से इतर विषयों पर चर्चा करते हैं और वह भी इस तरह कि लोग उससे प्रेरित होते हैं। इसकी मिसाल मिलनी कठिन है कि किसी शासनाध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक रेडियो कार्यक्रम के जरिये आम जनता से संपर्क-संवाद का सिलसिला कायम रखा हो। इस कार्यक्रम की व्यापकता और लोकप्रियता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यह 22 भाषाओं और विभिन्न बोलियों में प्रसारित होता है। इसके अतिरिक्त इसे कई विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। स्पष्ट है कि इसे कार्यक्रम को देश के साथ विदेश में भी लोग सुनते हैं। इस कार्यक्रम के जरिये प्रधानमंत्री ने आम जनता को विभिन्न विषयों के प्रति जागरूक करने का काम किया है। बात चाहे पर्यावरण सुरक्षा की हो अथवा बेटी बचाओ अभियान को लोकप्रिय बनाने की या फिर आम जनजीवन से जुड़े ऐसे ही अन्य अनेक मुद्दों की। यह कार्यक्रम इस बात का परिचायक है कि किस तरह आम जनता को उन विषयों के प्रति जोड़ा जा सकता है और उनमें उसकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है जो किसी न किसी रूप में उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। आज यदि स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ी हद तक प्रभावी दिख रहा है तो इसके पीछे मन की बात कार्यक्रम की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शायद सबसे अधिक बार इस अभियान की चर्चा की है।

भले ही विपक्षी दल इस कार्यक्रम को लेकर तंज कसते हों, लेकिन सच यही है कि प्रधानमंत्री इसमें केवल अपने मन की ही बात नहीं करते, बल्कि वह आम जनता के मन की बात देश के लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे लोगों के सुझाव आमंत्रित करते हैं, जो उन्हें चिट्ठियों और आडियो-वीडियो संदेशों के जरिये मिलते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर जनता से अपील की कि दीवाली के अवसर पर लोग स्वदेश निर्मित वस्तुएं खरीदें और यह भी सुनिश्चित करें कि उपहार में किसी को जो सामग्री भेंट करें, वह भी मेक इन इंडिया हो। उन्होंने झांसी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में जल संरक्षण की पहल का भी उल्लेख किया। स्वच्छता और जल संरक्षण के मामले में इस तरह के अनेक कार्य देश के दूसरे हिस्सों में आम लोगों ने मिलकर किए हैं। ऐसे कार्य यही बताते हैं कि यदि आम जनता को सही नेतृत्व मिल सके और उन्हें प्रेरणा प्रदान की जा सके तो समाज और राष्ट्र के हित में ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं। यह सही है कि सकारात्मक गतिविधियां प्रेरित करती हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज की राजनीति में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। आम जनता को स्वयं इस नकारात्मकता को हतोत्साहित करना होगा।

पीएम सूर्यघर

पीएम सूर्यघर योजना के प्रति उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, वह बना रहा तो भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। प्रदेश में योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए अब तक 17.75 लाख से अधिक परिवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 32 हजार से अधिक घरों में रूफ टाप पैनल लगाए भी जा चुके हैं। बेहद कम समय में जितनी संख्या में पंजीकरण हुए हैं उससे स्पष्ट है कि विद्युत ऊर्जा के संबंध में सरकार की इस पहल को महंगी बिजली से त्रस्त घरेलू उपभोक्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। योजना की घोषणा हुए अभी चार माह भी नहीं हुए हैं और इतनी संख्या में यदि लोगों ने पंजीकरण कराया है तो इसके पीछे केंद्र द्वारा इसके प्रोत्साहन के लिए दिए जा रहे अनुदान और उसमें प्रदेश सरकार की भी बड़ी भागीदारी मुख्य कारण है। उपभोक्ता को बेहद कम धनराशि में एक प्रकार से निश्शुल्क बिजली की गारंटी दी जा रही है। यह अनुदान तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने के लिए है। पीएम सूर्यघर योजना से उपभोक्ताओं को लाभप्रद निश्शुल्क बिजली तो मिलेगी ही, लेकिन इसके अन्य फायदे इससे भी बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को बिजली की बार-बार आवाजाही से राहत मिलेगी ही यह देश के जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में भी बड़ा योगदान देगी। इस समय पूरा विश्व कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित है और इस चिंता का एक अहम समाधान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश इसमें बड़ा योगदान करने के लिए तैयार है, किंतु जिस संख्या में पैनल लगाए गए हैं, उसमें अभी और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।

एक साथ चुनाव का बेतुका विरोध

सुरेंद्र किशोर

जब नेहरू के दौर में एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र मजबूत होता था तो आज वही काम करने से वह कमजोर कैसे हो जाएगा?

संविधान निर्माताओं को इस देश के मतदाताओं के विवेक पर पूरा भरोसा था। उन्हें यह अनुभूति थी कि मतदाता राष्ट्रीय हितों के साथ ही अपने राज्य के हितों का भी ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए संविधान में 'एक राष्ट्र और अलग-अलग चुनाव' जैसी कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि एक साथ चुनाव से उन्हें संघवाद पर कोई खतरा नजर नहीं आया। कुछ समय तक एक साथ चुनाव का सिलसिला भी सुगमता से चला, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1971 में अलग चुनाव कराने का इंदिरा गांधी का फैसला देशहित में न होकर अपने स्वार्थ से जुड़ा था। उसमें सुधार अब समय की जरूरत है। संविधान निर्माता जानते थे कि देश के मतदातागण इतने विवेकशील हैं कि वे एक ही चुनाव के समय लोकसभा के लिए एक पार्टी और उसी चुनाव में विधानसभा के लिए दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं। पूर्व उप-प्रधानमंत्री जगजीवन राम कहते थे कि 'तमाम भारतीय मतदाता भले निरक्षर हैं, पर वे बेवकूफ नहीं हैं।'

वर्ष 1957 के चुनाव में केंद्र में जहां कांग्रेस सरकार कायम रही, वहीं केरल में पहली बार गैर-कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार बनी। यह सिलसिला समय के साथ और तेज हुआ। वर्ष 1967 आखिरी ऐसा अवसर था जब केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। तब केरल सहित सात राज्यों के विधानसभा चुनावों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं, जिनमें से एक राज्य बिहार भी था। तब बिहार में लोकसभा की 53 सीटें थीं। उनमें से 34 सीटें यानी आधी से अधिक कांग्रेस को मिली थीं, मगर विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत नहीं मिल सका। यानी बिहार की जनता ने लोकसभा के लिए तो कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में गैर-कांग्रेसी सरकार चुनी। तब क्या किसी ने संघीय ढांचे के कमजोर होने का शोर मचाया था।

ऐसे में, यदि एक बार फिर देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ होने लगें तो उसमें किसी को भला क्यों परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि 1967 के बाद तो देश में साक्षरता से लेकर संचार के साधनों का काफी विस्तार हुआ है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आज राजग विरोधी दल और उनके नेता यह आरोप लग रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने पर केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय दल और उसके शीर्ष नेता में एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति पनपने का खतरा बढ़ेगा। वर्ष 1967 और 1971 के चुनावों के बाद के राजनीतिक विकास को जिन्हें गहरी जानकारी है, वे ऐसी बेतुकी दलील कतई नहीं देंगे। जब 1967 में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए तब इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थीं। उस चुनाव के बाद भी इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनीं, लेकिन उनमें 1967 से 1971 तक एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी थी, क्योंकि तब तक कांग्रेस पार्टी में ही एक हद तक आंतरिक लोकतंत्र कायम था। इंदिरा सरकार 1969 से 1971 तक अपने अस्तित्व के लिए दूसरे दलों पर भी निर्भर थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव में पूर्व रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन तक को लोकसभा का टिकट नहीं दिलवा सकीं। जबकि वह 1962 के चुनाव में बंबई (अब मुंबई) की एक लोकसभा सीट से जीतकर आए थे। तब कांग्रेस संगठन मेनन के खिलाफ था।

अवधेश राजपूत

हालांकि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीतकर आईं तो उनमें एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई। यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके जयप्रकाश नारायण को भी लग गया कि यह देशहित में नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी के एकाधिकारवाद पर एक लंबा लेख लिख दिया। उसी लेख के कारण जेपी से प्रधानमंत्री कुपित रहने लगीं। यह जेपी आंदोलन के शुरू होने से पहले की बात है। इसी पृष्ठभूमि में किसी कार्य से जेपी ने पटना से दिल्ली पहुंचकर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की कोशिश की तो श्रीमती गांधी ने उन्हें कहलवा दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल से मुलाकात कर लें। जेपी गुजराल से मिले बिना पटना लौट गए। अब जो प्रतिपक्षी दल यह आरोप लग रहे हैं कि एक साथ चुनाव से प्रधानमंत्री में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो वे 1971 के सत्ताधारी दल और आज के सत्ताधारी दल की बनावट एवं प्रवृत्ति में अंतर नहीं देख पा रहे हैं। फिर यदि ऐसी कोई प्रवृत्ति उभरती भी है तो मतदाता उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं।

एक साथ चुनाव कराने के विरोध में तरह-तरह के तर्क गढ़ने वाली कांग्रेस यह कह रही है कि वह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ होगा। दूसरी ओर वही कांग्रेस बार-बार यह तर्क दोहराती रहती है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में मजबूत लोकतंत्र की नींव डाली। यानी तब एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र मजबूत होता था, तो आज वही काम करने से वह कमजोर कैसे हो जाएगा? जबकि तब की अपेक्षा आज के भारतीय मतदाता अधिक जागरूक हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि फिर से एक साथ चुनाव की व्यवस्था से इंदिरा गांधी के उस बिवादास्पद फैसले के औचित्य पर प्रश्न चिह्न लग जाएगा, जिसके तहत उन्होंने 1971 में अलग से लोकसभा का चुनाव कराया था, जिसके पीछे उनका निजी स्वार्थ था। उनकी सरकार सीपीआइ और डीएमके जैसे दलों के सहारे आराम से चल रही थी। उस पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह इन दलों के दबाव से जल्द मुक्त होना चाहती थीं। सीपीआइ आदि के दबाव के कारण वह न तो खुद एकाधिकारवादी बन पा रही थीं न ही अपने पुत्र संजय गांधी के लिए कार संयंत्र की स्थापना करवा पा रही थीं। संजय गांधी ने लंदन के एक कार कारखाने में कुछ समय तक प्रशिक्षण भी लिया था। संजय की बड़ी इच्छा थी कि वह भारत में कारखाने की स्थापना करें। संजय ने अपने नाना के सिरहाने से हेनरी फोर्ड की किताब निकाल कर पढ़ी थी, जिससे उन्हें इसके लिए प्रेरणा मिली थी। इस बीच 1969 में कांग्रेस के महाविभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का लुभावना नारा गढ़ने के साथ ही कुछ लोकलुभावन काम भी किए। 1971 के चुनाव में जीत के बाद इंदिरा गांधी गरीबी हटाने का अपना वादा तो भूल गईं, लेकिन अपने पुत्र संजय के कारखाने का सपना जरूर पूरा किया। उसके मूल में अलग-अलग चुनाव कराने की जो एक विसंगति आरंभ हुई, उसे दूर करना मौजूदा सरकार का दायित्व है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

बोझिल नियमों से मुक्त हो विनिर्माण क्षेत्र

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

मजबूत विनिर्माण के बिना भारत सरीखा कोई भी बड़ा देश गरीबी से समृद्धि की ओर नहीं बढ़ पाया है

गति पकड़ता मेक इन इंडिया अभियान। प्रतीकात्मक

मेक इन इंडिया मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। 25 सितंबर, 2014 को शुरू हुई यह योजना दस वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अभियान के कुछ घोषित लक्ष्य थे, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12-14 प्रतिशत प्रति वर्ष करते हुए 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण के योगदान को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। अब इन लक्ष्यों को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मौजूदा गति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। कोविड महामारी के दौरान यह प्रचारित किया गया कि चीन छोड़ने वाली कंपनियां भारत में आएंगी, लेकिन इनमें से अधिकांश ने वियतनाम, ताइवान एवं थाइलैंड की राह पकड़ी और केवल कुछ ही भारत आईं।

यह सच है कि सरकार निरंतर आर्थिक विकास करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी कुछ क्षेत्रों में दिख रहे हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा कोविड टीकों का विकास एक बड़ा उदाहरण है। सरकार के प्रयासों के कारण 2014-2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। परंपरागत रूप से खिलौनों का आयातक रहा भारत अब निर्यातक बन गया है। अप्रैल-अगस्त 2022 में भारत के खिलौना निर्यात में 2013 की समान अवधि की तुलना में 636 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसे तरह मोबाइल उत्पादन 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार तक पहुंच गया। एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हो रही है। आइबीईएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विनिर्माण क्षेत्र ने अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया, जो 447.46 अरब डालर तक पहुंच गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज आफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 में भारत की रैंक 134वीं थी, जो 2023 में बढ़कर 63 हो गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर है, जो 2014 में 60वें स्थान पर था। इसके बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग में संभावनाएं पूरी तरह साकार नहीं हो पा रहीं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हाल के वर्षों में जनरल मोटर्स, मैन ट्रक्स, यूनइटेड मोटर्स, फिएट और हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार इन निकासियों के चलते 65,000 नौकरियां चली गईं। एक कंपनी के बंद होने से हजारों श्रमिकों का विस्थापन होता है।

हम चीन से तुलना करना पसंद करते हैं। उसकी जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। भारत की तुलना में जीडीपी में विनिर्माण का बड़ा हिस्सा रखने वाले अन्य एशियाई देशों में दक्षिण कोरिया (26 प्रतिशत), जापान (21 प्रतिशत), थाइलैंड (27 प्रतिशत), सिंगापुर और मलेशिया (21 प्रतिशत), इंडोनेशिया और फिलीपींस (19 प्रतिशत) शामिल हैं। चीन ने खुद को दुनिया के कारखाने के रूप में स्थापित किया है और वैश्विक विनिर्माण में उसका हिस्सा 22.4 प्रतिशत है, जबकि पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत वैश्विक विनिर्माण में बमुश्किल 2.9 प्रतिशत योगदान देता है। चीन से आयात छोटे उद्यमों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि सस्ते चीनी सामान के कारण घरेलू कंपनियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार कई आयातित उत्पाद स्थानीय एमएसएमई द्वारा बनाए जाते हैं और कम लागत वाले चीनी उत्पादों तक आसान पहुंच के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चीन भारत के 96 प्रतिशत छाते, 92 प्रतिशत कृत्रिम फूल और मानव बालों से बनी वस्तुओं की आपूर्ति करता है। चीनी आयात ने कांच के सामान में 60, सिरेमिक उत्पादों में 51.4 और संगीत वाद्ययंत्रों में 52, फर्नीचर, बिस्तर और लैंप में 48.7 प्रतिशत, औजार और कटलरी में 39.4 प्रतिशत, पत्थर, प्लास्टर और सीमेंट में 49.3 प्रतिशत, चमड़े की वस्तुओं के बाजार के 54 प्रतिशत तक पर कब्जा कर लिया है। सरकार द्वारा खिलौनों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने के बावजूद भारतीय खिलौना बाजार में चीन का 35 प्रतिशत हिस्सा है। इस स्थिति के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

हाल में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी वांछित नतीजे नहीं मिल सके हैं। पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप की संख्या 350 से 1.48 लाख हो गई, पर आज भी 80 प्रतिशत स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो उद्योगों की जरूरतों और मांगों से मेल खा सके।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र का विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एमएसएमई को अधिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआइ योजना को एमएसएमई और उभरते उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत भविष्य में खुद को अगला वैश्विक कारखाना बना सकता है, बशर्ते बोझिल नियमों से विनिर्माण क्षेत्र को मुक्त किया जाए। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि संसद के माध्यम से कोई विधेयक पारित करना, निवेशक सम्मेलन आयोजित करना आदि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं।

(संभवकार जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर एवं 'मेक इन इंडिया-ए रोडमैप' के लेखक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्षमा का भाव

क्षमा करने का गुण सात्त्विक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर ही होता है। कायर किसी को क्षमा करने का साहस नहीं दिखा सकते। क्षमा करने वाले सदैव मानवीय एवं दैवीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षमा मांगते हैं, उनका हृदय भी विनम्रता से भरा होता है। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी असाधारण ही होता है। कई बार अपराध करने के बाद भी हमारे भीतर अपराधबोध नहीं होता। हम स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। नाना प्रकार के प्रपंच रचकर स्वयं को सही ठहराने के प्रयास करते हैं। हालांकि जो विन्रमता से भरे होते हैं, जो अपनी गलती को मानने का साहस दिखाते हैं, ऐसे लोग तुरंत ही दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्षमा मांगने वाला अपने किए गए कृत्यों के लिए नतमस्तक हो जाता है। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाता है। वह क्षमा भी कर देता है। इसके विपरीत आचरण करने पर छोटी सी बात भी बहुत आगे निकल जाती है। फिर वह किसी बड़ी घटना अथवा अपराध को भी जन्म दे सकती है। क्षमा मांगने पर हम कई तरह की समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोज लेते हैं।

धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमाशीलता के आभूषण का वरण कर सकता है। भगवान श्रीकृष्ण क्षमाशीलता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। शिशुपाल के सौ अपराधों एवं चुनौतियों को क्षमा करना असाधारण बात है। भगवान महावीर स्वामी क्षमा के संबंध में कहते हैं, 'मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्रीभाव है। मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूं। सब जीवों से मैं सारे अपराधों को लेकर क्षमा मांगता हूं। सभी जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूं।' वस्तुतः क्षमा करने और क्षमा मांगने की वृत्ति हमें आगे ले जाती है।

ललित शैथ

खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत

ठेंद्रराज सुथार

जिस तरह स्वस्थ बीज से मजबूत वृक्ष पनपता है, उसी तरह स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं

जब तक हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ और सशक्त नहीं होगा, तब तक हमारी प्रगति अधूरी ही रहेगी। हाल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2024 में केरल और तमिलनाडु का शीर्ष स्थान प्राप्त करना प्रशंसनीय है। इन राज्यों ने साबित किया है कि दृढ़निश्चय और सुनियोजित प्रयासों से कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु इस सूचकांक में अंतर्निहित विषमता भी एक कटु सत्य है, जो हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती पेश करती है। खाद्य सुरक्षा का सवाल सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, हमारे सामाजिक ताने-बाने का आधार है। जिस तरह स्वस्थ बीज से मजबूत वृक्ष पनपता है, उसी तरह स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा में निवेश वास्तव में हमारे उज्ज्वल भविष्य में निवेश है। यह न केवल बीमारियों को रोकता है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को कम करता है।

इसमें सरकार की भूमिका निःसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ शासन तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी अपेक्षित है। खाद्य उद्योग को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, जो इस शृंखला की रीढ़ है। बीज से लेकर थाली तक हर स्तर पर गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। छोटा व्यापारी हो या बड़ा उद्योगपति, सभी को खाद्य सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण और सख्त दंड व्यवस्था जरूरी है। इस शृंखला की अंतिम कड़ी उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्हें समझना होगा कि सस्ता खाना हमेशा अच्छा नहीं होता और अच्छा खाना हमेशा महंगा नहीं होता। उन्हें गुणवत्ता से समझौता न करने का संकल्प लेना होगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनका त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूलों में खाद्य सुरक्षा सिखाई जानी चाहिए, ताकि वे अपने घरों में इसके संदेशवाहक बन सकें। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

असुरक्षित भोजन से सालाना 60 करोड़ लोग खाद्य जनित बीमारियों के शिकार बनते हैं और चार लाख बीस हजार लोग काल के गाल में समा जाते हैं। कृत्रिम खाद्य रंग, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जैसे नए-नए खतरे उभर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए नियमों को निरंतर अद्यतन करना होगा और नवीन शोध को प्रोत्साहित करना होगा। सबा ही ऐसे खाद्य व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की जानी चाहिए, जो उच्च मानकों का पालन करते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रदूषण से निपटना साझा जिम्मेदारी

'प्रदूषण से निपटने के त्रिस्तरीय उपाय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने एक प्रमुख समस्या पर प्रकाश डाला है। यह सही है कि कुछ सजग नगरिकों के अलावा किसी को भी प्रदूषण से निपटने की कोई खास परवाह नहीं दिखती। यह स्थिति तब है जब सर्दियों के दौरान देश की राजधानी किसी 'गैस चैंबर' में तब्दील हो जाती है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव भले ही लोगों को प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई पड़ें, लेकिन वास्तव में ये बहुत घातक और दूरगामी असर लिए होते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण ही लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। इससे दवा-उपचार पर तो उनका खर्चा बढ़ता ही है, बल्कि सेहत खराब होने से उनके काम की उत्पादकता भी घटती है। यह दोहरा नुकसान है। कई बीमारियां लोगों की आयु को घटा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के पीछे भी प्रदूषण एक बड़ी हद तक जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इससे जानमाल का भारी नुकसान होने के साथ ही जनजीवन भी अस्त-व्यस्त होता है। यदि समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय न किए गए तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रदूषण से निपटने के लिए निजी प्रयासों के साथ ही सामुदायिक और सरकारी स्तर पर हरसंभव प्रयास करने होंगे।

केशव तिवारी, आजमगढ़

फिर आ गया मनडे

विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़, पौधे, जल, पहाड़, इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कंपनियों से कोई शिकायत न हो? साफ है कि काम के दबाव से जुड़ी शिकायतें कंपनियां छुपा लेती हैं या उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की असंवेदनशीलता कर्मचारियों के काम के प्रति आलगाव को बढ़ावा देती है। साथ ही वे काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव से गुजरते हैं जिस कारण उनके बेहतर तरीके से काम करने की क्षमता कम होती जाती है। यही कारण है कि पूरे सप्ताह मानसिक तनाव से गुजरने के बाद जब सन्डे के बाद मनडे आता है तो लोग यही कहते हैं कि लो! फिर आ गय मनडे। अपने पैर पसारते इस 'आई हेट मनडे' वाले कल्चर से बचने के लिए एक पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण वर्क कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। संवेदनशील एवं मानवतापूर्ण व्यवहार का हकदार हर एक कर्मचारी होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कर्मचारी भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

मेलबाक्स

अनाज आदि ये सभी मनुष्य जीवन का आधार हैं, लेकिन मनुष्य लालच और स्वार्थ के कारणवश इनका दोहन एवं शोषण करने लगा है जिस कारण प्रकृति में असंतुलन की स्थिती पैदा हो रही है। ठीक इसी प्रकार कारपोरेट जगत में कंपनी के कर्मचारी उसके आधार होते हैं जिनकी मेहनत से कंपनी आगे बढ़ती है। 'कार्य-जीवन में खतरनाक असंतुलन' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में 'गौरव बल्लभ' ने कानून एवं नीति में मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को प्रमुख स्थान देने का उचित सुझाव दिया है। पर देखा जाए तो अक्सर कानून एवं नीतियां स्वार्थ और बेईमानी के आगे धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कानून एवं नीतियों के साथ-साथ आवश्यक है कि लोग व्यक्तिगत संवेदनशीलता और आपसी समझ पर भी ध्यान दें। कर्मचारियों पर कार्यबल का जरूरत से ज्यादा दबाव या कम कार्यबल से अधिक से अधिक उत्पादन कराने की खतरनाक व्यवस्था आज भयावह रूप लेती जा रही है। जिसके परिणाम काम से संबंधित तनाव के कारण पुणे में एक युवा सीए का निधन, चेन्नई में साफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। कंपनियों में शिकायत प्रकोष्ठ का प्रावधान भी होता है। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग द्वारा 2023 में जारी डाटा के अनुसार 944 कंपनियों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अब सवाल यह कि क्या ऐसा संभव है कि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

दवाओं की गुणवत्ता

चिन्ता का विषय

दवाओं की गुणवत्ता चिन्ता का विषय है क्योंकि सीडीएससीओ ने 50 से अधिक दवाओं के अधोमानक होने पर सवाल उठाए हैं जो गंभीर चिन्ता का विषय है। एक चिन्ताजनक घटनाक्रम में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन-सीडीएससीओ ने अपनी नवीनतम गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में पैरासीटामाल व पैन डी समेत 50 सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली दवाओं को 'मानक गुणवत्ता वाली नहीं' घोषित कर दिया है। इन दवाओं में महत्वपूर्ण दवायें, जैसे कैल्शियम और विटामिन सप्लीमैंट, उच्च रक्तचाप की दवायें तथा मधुमेह-रोधी गोलियां शामिल हैं। संगठन की अगस्त, 2024 रिपोर्ट में सार्वजनिक प्रयोग के लिए इनकी सुरक्षा तथा प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सीडीएससीओ की मासिक गुणवत्ता जांच में राज्य औषधि अधिकारियों द्वारा नमूने एकत्र करना शामिल है। इसमें अनेक दवाओं को 'मानक गुणवत्ता नहीं-एनएसक्यू चेतावनी' की सूची में रखा गया है। प्रभावित उत्पादों में सीधे ग्राहकों को बेची जाने वाली दवायें जैसे विटामिन सी व डी3 गोलियां, कैल्शियम व विटामिन डी3 का मिश्रण 'शेलकाल', मधुमेह की दवा 'ग्लीमीपिराइड', उच्च रक्तचाप के लिए 'टेलीमिसार्टन' और एंटी-एसिड 'पैन डी' शामिल हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली ये दवायें हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लेबोरेटरीज व कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाती हैं। अपनी अधोमानक गुणवत्ता के कारण इनके प्रयोगकर्ताओं को खतरा हो सकता है।

सीडीएससीओ की रिपोर्ट में दो सूचियां हैं। इनमें से एक में 48 दवायें शामिल हैं जो गुणवत्ता जांच में विफल हो गई हैं, जबकि दूसरी सूची में 5 दवायें हैं जिनकी जांच हो रही है और वे संभवतः नकली हैं। इन नतीजों को देखते हुए कुछ निर्माताओं ने दावा किया है कि उत्पादों के कुछ बैच नकली थे और उनके द्वारा उत्पादित नहीं थे। लेकिन यह बचाव का केवल एक तरीका है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ गंभीर जांच होनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीडीएससीओ ने असुरक्षित औषधियों के खिलाफ कार्रवाई की हो। इसके पहले अगस्त में केन्द्रीय नियामक ने देश भर में 156 'फिक्स डोज कंबीनेशन्स'-एफडीसी को 'मनुष्यों के लिए संभवतः खतरनाक' बता कर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बार-बार होने वाली ऐसी घटनायें भारत के औषधि उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रक मानकों के बारे में खतरे की घंटी बजाती हैं। इससे बाजार में बिकने वाली दवाओं की गुणवत्ता के प्रयोग से स्वास्थ्य पर संभावित खतरे भी स्पष्ट होते हैं। नकली दवाओं की जांच जारी रहने के साथ ही दवाओं की सुरक्षा के बारे में जनता का विश्वास डगमगा गया है। पिछले साल अफ्रीका की सप्लाई कफ सीरप के कारण कथित रूप से 141 लोगों की जानें गई थीं। यह न केवल अमानवीय कृत्य है, बल्कि इससे दुनिया में भारतीय दवा उद्योग के सम्मान को धक्का लगता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे खासकर कम ज्ञात स्रोतों से खरीदी और प्रयोग की जाने वाली दवाओं के बारे में सतर्क रहें। इसके साथ ही नियामक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वह दवा कंपनियों पर कठोर गुणवत्ता मानक बनाए रखने के लिए निगरानी सुनिश्चित कर सके। सीडीएससीओ रिपोर्ट ने केवल 65 बिलियन डालर बाजार की थोड़ी पर्त उघाड़ी है। लालच के कारण अनेक कंपनियां अधोमानक तथा यहां तक कि फर्जी दवाइयां भी बनाती हैं। उनको मानव जीवन की जरा भी चिन्ता नहीं है और वे केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान देती हैं। वास्तव में सरकार को उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर उनके अपराध की कठोर सजा सुनिश्चित करनी चाहिए।

हिंद-प्रशांत में सुरक्षा को प्राथमिकता

चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्वाड सम्मेलन ने क्षेत्रीय स्थिरता तथा टिकाऊ विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। इसके साथ ही उसने अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार किया है।

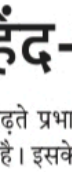

सुधीर हिंदवान
(लेखक, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

अमेरिका के विलिंगटन, डेलावेयर में आयोजित चौथे क्वाड सम्मेलन ने सदस्य देशों-अमेरिका, भारत, जापान व आस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्वाड सम्मेलन ने क्षेत्रीय स्थिरता तथा टिकाऊ विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। आधिकारिक रूप से 'क्वाडीलेटरल सिक्यूरिटी डायलग'-क्वाड के रूप में जाना जाने वाला मंच अनेक मोर्चों पर सहयोग का आवश्यक अंग बन गया है। यह खासकर हिंद-प्रशांत, दक्षिणपूर्व एशिया व हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करता है। समय बीतने के साथ ही इस साझेदारी का विस्तार कर इसमें आपदा प्रबंधन, डिजिटल ढांचों व जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिससे यह सुरक्षा तथा विकासके लिए बहुआयामी पहल बन गया है।

इस सम्मेलन का एक प्रमुख तत्व भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच नए सहयोग का प्रस्ताव था। मोदी ने 'अमेरिकन-इंडियन'-एआई शक्ति पर जोर देते हुए कृत्रिम बुद्धि तथा विकास कर रही अमेरिका-भारत साझीदारी की ओर संकेत किया। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने 'ए-आई' को नए ढंग से परिभाषित किया है। अनिवासी भारतीयों को एक विशाल सम्मेलन में संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि सारी दुनिया 'ए-आई' को आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस कहती है, पर मैं इसे 'अमेरिकन-इंडियन' के रूप में परिभाषित करता हूं।

इस प्रकार उन्होंने अनिवासी भारतीयों या अमरिकन इंडियन की अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया जिसमें एआई व चिप निर्माण शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच चिप निर्माण में यह सहयोग उत्तर प्रदेश में नोयडा के निकट सेमीकंडक्टर सुविधा पर केन्द्रित है और उत्कृष्ट तकनीक का वादा करता है जिसमें भारतीय और अमेरिकन सुरक्षा के लिए आवश्यक चिपों पर नियंत्रण करना शामिल है। इस कदम को वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पर चीन और ताइवान के प्रभुत्व को चुनौती देने की तरह देख जा रहा है। इस प्रकार भारत और अमेरिका के बीच की जाने वाली साझेदारी की इस पहल का उद्देश्य भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक तकनीकी परिवर्तन करना है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग के साथ ही क्वाड की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में समुद्री व साइबर सुरक्षा भी शामिल है। हालिया सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज तथा जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भाग लेते हुए इन क्षेत्रों में रणनीति का महत्व रेखांकित किया। क्वाड नेता अनेक क्षेत्रीय टकरावों का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं जिनमें रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तथा हिंद-प्रशांत में उभरने वाले परंपरागत व गैर-परंपरागत खतरे शामिल हैं। सदस्य देशों को खासकर हिंद महासागर तथा दक्षिण व पूर्वी चीन सागर के कुछ हिस्सों में चीन को लगातार बढ़ती आक्रामकता से चिन्ता है क्योंकि ये क्षेत्र विश्व व्यापार तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। संवाद और समन्वित प्रयासों के माध्यम से क्वाड का उद्देश्य खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटना है। राजनयिक संपर्क मजबूत कर तथा टकराव-समाधान व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए क्वाड को उम्मीद है कि वह सभी सदस्य देशों के बीच स्थायित्व को बढ़ावा देते हुए उनकी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। समूह का साझा दृष्टिकोण एक बहुआयामी व बहुपक्षीय रणनीति तैयार करना है जो लगातार परस्पर जुड़ती दुनिया में सुरक्षा चुनौतियों से निपट सकती है। क्वाड न केवल एक सैनिक गठजोड़, बल्कि एक ऐसा मंच है जो शिक्षा, विज्ञान, जैव-प्रौद्यागिकी तथा रणनीतिक नियोजन जैसे क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित कर अपने सदस्य देशों के बीच संबंध मजबूत करना चाहता है।

भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का उसके द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व है जिसमें जी20 शामिल है। इसके साथ ही वह शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ को भी मजबूत कर रहा है। इन भूमिकाओं ने भारत को वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में अपनी राजनयिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी है। क्वाड सम्मेलन भारत के लिए एक और अवसर है जहां वह एक जीवन व सहयोगी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने में योगदान कर सकता है। सम्मेलन में हुई चर्चा में विश्व व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले देशों के खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया गया है।

सम्मेलन का एक प्रमुख केन्द्र बिंदु हिंद-प्रशांत क्षेत्र था जहां क्वाड का उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला व सुरक्षित समुद्री परिवेश सुनिश्चित करना है। यह क्षेत्र अनेक टकरावों का केन्द्र बन सकता है क्योंकि चीन का 'बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव'-बीआरआई क्षेत्रीय स्थायित्व को बड़ी चुनौती दे रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए क्वाड के सदस्य देशों ने अनेक पहलों में सहयोग किया है। इसमें खासकर 'क्वाड एट सी' मिशन है जो जहाजों पर नजर रखेगा। इससे 2025 तक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ ही क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं में भारी निवेश की योजना बना रहा है जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनायें तथा उच्च गुणवत्ता वाली ढांचागत परियोजनायें शामिल हैं। क्वाड का अगला सम्मेलन 2025 में भारत में होगा।

उम्मीद की जाती है कि तब तक इस व्यवस्था की रूपरेखा पूरी तरह तैयार हो जाएगी। क्वाड के भारत में होने वाले अगले सम्मेलन में नए अमेरिकन राष्ट्रपति शामिल होंगे क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्वाड की इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना तथा क्वाड सदस्य देशों समेत सारी दुनिया की चीनी-नेतृत्व वाली पहलों पर निर्भरता कम करना है। क्वाड सम्मेलन में हुई महत्वपूर्ण चर्चा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का भी विशेष महत्व है। क्वाड देशों के नेताओं ने 'क्वाड कैंसर मूनशाट इनीशियेटिव' से सर्वाइकल कैंसर का मुकाबला करने में सहयोग की नींव डाली है। इसका प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखा था जो भारत की व्यापक वैक्सीन निर्माण क्षमताओं तथा इस दिशा में दुनिया की एक सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी के साथ सहयोग पर आधारित है।

भारत ने कोरानावायरस की वैक्सीन बहुत सस्ते दामों में बनाने तथा इसे दुनिया के अनेक देशों को सप्लाई कर सारी दुनिया में प्रशंसा प्राप्त की है। यह मानवतावादी दृष्टिकोण क्वाड समूह के सुरक्षा मजबूत करने के प्रयासों के साथ ही आया है। इससे क्वाड की क्षेत्रीय स्थिरता व समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। आधुनिक आतंकवाद की समस्या को संबोधित करने में इसकी फंडिंग पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर खतरों से निपटने के क्वाड के दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि वह उभरते सुरक्षा खतरों और चुनौतियों से निपटने में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रहा है।

क्वाड देशों के बीच वर्तमान सहयोग केवल परंपरागत सुरक्षा उपायों तक सीमित नहीं है। इस समूह के देश पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और व्यापक सुरक्षा के लिए तकनीकी खोजों को बढ़ावा देने के मामले में भी सहयोग कर रहे हैं। ये प्रयास उन 'गैर-राज्य कारकों' को नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं जो स्मगलिंग, नशे के व्यापार तथा साइबर हमलों में शामिल हैं। सुरक्षा उपायों को मजबूत कर तथा खुफिया सूचनाओं का साझा बढ़ा कर क्वाड देशों को उम्मीद है कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा मजबूत व्यवस्था बनाने में सफल होंगे। क्वाड का प्रभाव मानवीय सहायता के रूप में भी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। उसने पापुआ न्यू गाइना को समर्थन देने का फैसला किया है जो अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन ने सुरक्षा के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन पुरानी पड़ चुकी रणनीतियों को अस्वीकार भी किया है जो अब वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में उपयुक्त नहीं रह गई हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में शिक्षा

> जैसे-जैसे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योगों को नया आकार दे रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है।

रजनीश भंडारी
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बढ़ते विवाद, खासकर पेपर लीक को लेकर, ने हमारी शिक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। एक स्पष्ट समाधान कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं में बदलाव है, जिन्हें पहले से ही जेईई मेन परीक्षा, विटरीट और कैट जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए लागू किया जा चुका है। इन परीक्षाओं में यादृच्छिक रूप से उत्पन्न प्रश्न और विभिन्न नोड्स में एक साथ वितरण की सुविधा होती है, जिससे पेपर लीक को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तत्काल ग्रेडिंग की संभावना पारदर्शिता प्रदान करती है। साल में कई बार ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों पर पड़ने वाले भारी दबाव को भी कम किया जा सकता है।

हालांकि, परीक्षण की विधि एक महत्वपूर्ण चर्चा है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, और क्यों मूल्यांकन करना है जैसे प्रश्न इस बहस के केंद्र में होने चाहिए।

ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, शिक्षा एक सराहनीय चीज है, लेकिन सीखने लायक कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। यह कथन शिक्षा की वर्तमान स्थिति से गहराई से मेल खाता है। हमारी प्रणाली एक ही मॉडल का पालन करती है, यह मानते हुए कि एक कक्षा में साठ छात्र एक ही गति से एक ही सामग्री सीख सकते हैं और, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं।

रटकर सीखने की पद्धति, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली पर हावी है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह दृष्टिकोण कितना पुराना हो गया है, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में। 2011 तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइपराइटिंग को एक विषय के रूप में पेश किया, जो दर्शाता है कि पाठ्यक्रम के कितने पुराने हिस्से हैं। छात्रों पर दबाव चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिससे प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में आत्महत्या की दर चिंताजनक रूप से बढ़ गई है। कई छात्र नीचे कक्षा से ही आईआईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो उनके बचपन और समग्र विकास में बाधा डालती है।

प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, और प्रत्येक मानव मस्तिष्क अलग-अलग तरीके से कार्य करता है। शिक्षाशास्त्र में प्रगति के बावजूद - सीखने का विज्ञान - हम एक पुराने, कुकी-कटर दृष्टिकोण का पालन करना जारी रखते हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। सामूहिक शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तियों को नौकरियों के लिए तैयार करना था। हालांकि, ऑटोमेशन और अब इनमें से कई नौकरियों को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। तकनीकी प्रगति तेजी से कुछ कौशल को अप्रचलित बना रही है।

आज बड़ी संख्या में युवा पेशेवर ऐप और वेब डेवलपमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, जो काम अब चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई सिस्टम द्वारा किए जा सकते हैं। ये सिस्टम सरल संकेतों के आधार पर ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा, जेनरेटिव एआई जैसे टूल के साथ, कोई भी लेखक, कलाकार, संगीतकार या कोडर बनने की क्षमता रखता है, जो विशेषज्ञों और नौसिखियों के बीच मौजूद कौशल अंतर को काफी कम कर देता है।

इसलिए, भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण कौशल एक विशिष्ट कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, बल्कि लगातार सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता होगी। लगातार बदलती दुनिया में, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा या तो अप्रासंगिक हो जाएगा या उसे लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होगी।

शिक्षा को जीवन के शुरुआती वर्षों में किए गए एकमुश्त निवेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, सीखने को जीवन भर की यात्रा के रूप में पहचाना जाना चाहिए। अपने करियर की शुरुआत में अर्जित की गई डिग्री आधे रास्ते तक अप्रासंगिक हो सकती है।

पारंपरिक डिग्रियां, जो कभी नौकरी पाने के लिए महत्वपूर्ण थीं, आने वाले वर्षों में अपनी प्रासंगिकता खो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई सॉफ्टवेयर डेवलपर औपचारिक विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के बजाय कोर्सेरा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोग्रामिंग सीखते हैं। कंपनियों द्वारा नौकरी के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने का तरीका भी विकसित हो रहा है। रिज्यूमे की जगह अब पोर्टफोलियो समीक्षा ले रही है, जहां व्यक्ति अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते हैं।

शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव पहले से ही स्पष्ट है। पिछले साल, चैटजीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा, लॉ स्कूल परीक्षा और गूगल की कोडिंग परीक्षा पास करके सुर्खियाँ बटोरीं। इसने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में एआई टूल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नसीम तालेब ने हाल ही में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, चैटजीपीटी पास करना चैटजीपीटी का नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली का प्रतिबिंब है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के संसाधनों को सीमित करके उनका परीक्षण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कैलकुलेटर कई अंतरराष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य उपकरण है, लेकिन अभी भी सीबीएसई जैसे कुछ भारतीय बोर्डों में प्रतिबंधित है।

जनरेटिव एआई व्यक्तिगत पाठ योजनाएं और आकलन तैयार करके शिक्षा में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। खान अकादमी और डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए वास्तविक समय में फ्रीडबैक देने वाले वर्चुअल ट्यूटर पहले से ही उपलब्ध हैं। शिक्षा का भविष्य ऐसी शिक्षा में निहित है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सहज रूप से शामिल हो, तथा पारंपरिक शिक्षकों के बजाय मार्गदर्शकों द्वारा सुगम बनाई जाए।

आप की बात

संरा. में सुधार जरूरी

दुनिया आज तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, इजराइल-हमास युद्ध थमा नहीं और इसका विस्तार लेबनान तक हो रहा है। दुनिया में चल रहे युद्धों तथा बढ़ते तनावों को दूर करने एवं अन्य वैश्विक सामजिक, राजनीतिक व मानवीय समस्याओं के समाधान व शान्ति के लिए गठित संयुक्त राष्ट्रसंघ कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण उसमें शामिल कतिपय प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों का दबदबा व स्वार्थी दृष्टिकोण है। शक्तिशाली राष्ट्रों को अपना स्वार्थ छोड़कर विकासशील व गरीब राष्ट्रों के उत्थान में सहयोग देना चाहिए। दुनिया की अनेक समस्याओं के समाधान तथा खासकर युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा खासकर सुरक्षा परिषद में सुधार और परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में भारत के साथ ही कई अफ्रीकी देशों को शामिल करने पर विचार होता रहता है, पर यह कार्यरूप में परिणत होते नहीं दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्वरूप बढ़ाने के लिए नए व खोजी विचारों की आवश्यकता है ताकि दुनिया के वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों व निजी क्षेत्र के उद्यमियों के स्वरों को भी उसमें समुचित स्थान मिले तथा वह केवल कुछ शक्तिशाली राजनेताओं का अखाड़ा बन कर ही न रह जाए।

- **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

मोदी का रिटायरमेंट

प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर विपक्षी नेता सवाल उठाते रहते हैं क्योंकि अगले साल 17 सितंबर को वे 75 साल के हो जाएंगे। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट की उम्र का कोई जिक्र नहीं है। रूस और चीन के राष्ट्रपति भी दीर्घजीवी हैं और संभवतः आजन्म अपने पद पर बने रहेंगे। वह अपना काम बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। इसका कारण इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में जनता हर पांच साल पर मतदान करती है और वह किसी भी नेता और उसकी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। देश-दुनिया में मोदी की छवि और कामकाज अधिकांश लोगों को पसंद है। इसे देखते हुए उनको निश्चित रूप से अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। मोदी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। ऐसे में उनके रिटायरमेंट की बात उठाना विपक्ष का एक सोचा समझा दांव है। भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता कई बार कह चुके हैं कि मोदी न केवल अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे, बल्कि वह 2029 में भी भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। मोदी के रिटायरमेंट की बात करने से विपक्ष को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वर्तमान समय में राजनेताओं में उनका कद सबसे बड़ा है।

- **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

छात्र राजनीति का रूप

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान परिसर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का निंदनीय मामला सामने आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त कार्यवाही करते हुए सप्ताह होने तक वोटों की गिनती पर उचित ही रोक लगाई है। अदालत का मानना है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति को पोस्टरों, रंग रोगन आदि से नुकसान हुआ है, उसे साफ करने का खर्च चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से वसूला जाए। छात्र राजनीति के कारण अनेक छात्रों के अध्ययन में बाधा पहुंची है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने पोस्टर, पेंटिंग एवं नारेबाजी से चुनाव भले ही रोमांचक बना दिया हो, पर चुनाव में जातिवाद की चर्चा विधानसभा चुनावों की तरह रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के रूप पर हमेशा विवाद होता रहा है। इस संबंध में सालों पहले गठित लिंगदोह कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। लेकिन विडंबना है कि इस समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। छात्रों को देश-दुनिया की समस्याओं पर विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, पर उनका मुख्य उद्देश्य अपने साथी छात्रों को अधिकाधिक कुशल बना कर जीवन में संघर्ष हेतु तैयार करना होना चाहिए।

- **सुगल किशोर शर्मा,** फरीदाबाद

प्रशंसनीय निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव की मतगणना पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव के दौरान फैलाई गई गंदगी पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, नतीजे घोषित नहीं होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का यह अनुकरणीय और स्वागत योग्य कदम है। पहले स्कूल-कॉलेज के चुनाव में बैनर, पोस्टर और प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और बिना कुछ खर्च किए चुनाव हो जाते थे। उसके बाद मैरिट अंकों के आधार पर छात्रसंघ के पदाधिकारी चुन लिए जाते थे ताकि छात्रों में द्वेष नहीं फैले और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। मगर आज कॉलेजों के चुनावों का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। भले ही चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 5,000 रुपये तय की गई है, मगर अब छात्रसंघ चुनावों में लाखों रुपए खर्च होने लगे हैं। ऐसे में कोर्ट को गंदगी साफ करने का खर्च छात्रसंघ उम्मीदवारों से वसूल करने के साथ चुनाव में उनके द्वारा किए खर्च पर भी नजर रखनी चाहिए। इस संबंध में समुचित दिशानिर्देशों की जरूरत है।

- **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 30 सितंबर 2024

बेक़ाबू न हो जाए युद्ध

लेबनान में शुक्रवार को हुए इस्राइली हमले में हसन नसरल्लाह का मारा जाना हिज़्बुल्ला के लिए ऐसा झटका है, जिससे उबरना उसके लिए आसान नहीं होगा। इस्राइली सेना और नेतन्याहू सरकार के लिए यह उतनी ही बड़ी कामयाबी है। अफसोस की बात यह है कि इस कथित झटके या कामयाबी के बाद भी इस क्षेत्र में शांति की संभावना मजबूत नहीं हुई है। इसके उलट संघर्ष के बेकाबू होने का खतरा बढ़ गया है।

टॉप लीडरशिप खत्म | पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से हिज़्बुल्ला का नेतृत्व कर रहा नसरल्लाह मध्यपूर्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शुमार किया जाता था। उसकी कमी की जल्द भरपाई होना मुश्किल है। मगर हिज़्बुल्ला के लिए यह इकलौता झटका नहीं है। हाल के हमलों में उसके एक दर्जन से ज्यादा टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं। बहुचर्चित पेजर और वॉकी टॉकी हमलों ने उसके इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को भी लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में खुद को समेटकर इस्राइल पर दोबारा वैसा ही हमला करना हिज़्बुल्ला के लिए काफी मुश्किल होगा।

मध्य पूर्व में तनाव चरम पर

समर्पण के आसार नहीं | ताजा झटका कितना भी बड़ा हो, यह समझना गलत होगा कि इससे हिज़्बुल्ला इस्राइल के सामने समर्पण कर देगा। पिछले कुछ दशकों में हिज़्बुल्ला दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर बन चुका है। उसकी सैन्य ताकत किसी मिडल साइज के देश के बराबर मानी जाती है। हिज़्बुल्ला ने कहा भी है कि वह इस्राइल के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा।

इस्राइल का रवैया | कुछ समय पहले तक 12 देशों की ओर से प्रस्तावित युद्धविराम को लेकर जो भी बची-खुची उम्मीद थी, वह अब समाप्त हो गई है। ताजा कामयाबी ने इस्राइल का उत्साह और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हिज़्बुल्ला की मिसाइलों का खतरा समाप्त करने के बाद इस्राइल अपने सैनिकों को लेबनान में घुसने का आदेश देता है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक और लंबी लड़ाई की शुरुआत साबित हो सकती है।

ईरान पर निगाहें | निगाहें ईरान पर भी टिकी हैं। वह पहले से नाराज है। तेहरान के एक गेस्टहाउस में हमास नेता इस्माइल हानिये की मौत का बदला भी उसे लेना है। नसरल्लाह की मौत उसके लिए भी झटका है। देखना होगा कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी और कैसी होती है।

भारत का रुख | जहां तक भारत की बात है तो बाकी दुनिया की तरह वह भी यही चाहेगा कि संघर्ष की यह आग ज्यादा न फैले। इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकॉनमिक कॉरिडोर (IMEEC) जैसे दूरगामी हितों को फिलहाल छोड़ दें तो भी युद्ध का बेकाबू होना भारत ही नहीं, ग्लोबल इकॉनमी को भी चुनौतियों के भंवर में डाल सकता है।

नज़रिया

Social memory का बोझ

सुरक्षित गोस्वामी

आदि गुरु शंकराचार्य ने आठ साल की उम्र में निर्वाण षट्कम् में अपना परिचय देते हुए यह भी कहा था, 'न मे जातिभेदः' यानी, मेरे में जाति का भेदभाव नहीं है। अस्लियत में शंकराचार्य ने जिसे नकारा है, वह social memory है। यादों की वह गठरी, जो पैदा होने के साथ ही हमारे सिर-कांधों पर लाद दी जाती है। व्यक्तिगत तौर पर हमारा इन यादों से सीधे कोई लेना-देना नहीं होता। हम उन घटनाओं का हिस्सा भी नहीं होते, उन्हें देखा भी नहीं होता, जिया भी नहीं होता, लेकिन उन्हें इस तरह से हमारे दिल-दिमाग में रोप दिया जाता है कि हम उनके बाबू में आ जाते हैं। फिर हमारे लिए social memory ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। ये वो स्मृतियां हैं, जिन्हें कोई समाज मिलकर याद रखता है और आने वाली पीढ़ियों को बताता रहता है। आमतौर पर ये झूठी यादें ही व्यक्ति की सच्ची पहचान बन कर रह जाती हैं। हालांकि, परेशानी यह है कि कई बार इसे इतिहास मान लिया जाता है। यादें तो समय के साथ बदली जा सकती हैं, वह एक समाज के लिए बुरी और दूसरे के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इतिहास नहीं बदलता। social memory को तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, ताकि नई छवि गढ़ी जा सके तो जब इसमें हेरफेर की इतनी गुंजाइश है, फिर क्या इसके सहारे बैठे रहने का कोई फायदा है? social memory के कारण ही समाज में विभिन्न धर्मों के बीच आपसी द्वेष फैला रहता है। एक धर्म में भी अनेक शाखाएं बनाकर आपस में लोग लड़ते रहते हैं, फिर दूसरे धर्म की तो बात ही क्या? आज की तारीख में ज्यादातर हिंदू परिवारों का किसी मुस्लिम परिवार से सीधा द्वेष नहीं। किसी मुस्लिम परिवार ने किसी आम हिंदू परिवार का नुकसान भी नहीं किया होगा। लेकिन, यह social memory है, जिसने दोनों धर्मों को मानने वालों के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। यह memory हिंदुओं को याद दिलाती है कि सैकड़ों साल पहले बाहर से आए इस्लाम धर्म को मानने वालों ने हिंदू धर्म मानने वालों पर जुल्म किया था। बस यही नफरत आज भी जिंदा है। social memory की खासियत है कि यह बड़े ही गुप्त तरीके से व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए समय-समय पर विभिन्न देशों के राजनेता इसका फायदा उठाकर चुनाव जीतते रहते हैं। यह उनके हित में है कि जनता की वास्तविक चेतना पर सामाजिक यादें हावी रहें। व्यक्ति जब इन काल्पनिक यादों में लगातार डूबा रहता है, तब इनकी गिरफ्त और मजबूत होती जाती है। अगर जीवन का आनंद चाहिए तो इन जालों को काटना होगा, इन यादों से ऊपर उठना होगा। हमें अतीत से निकलकर वर्तमान में जीना होगा।

Subrata Dhar

एकदा

गुण का सम्मान

चीन में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, लाओत्से। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि आसपास के जंगलों को काटा जा रहा है। सिर्फ एक पेड़ था, जिसे काटा नहीं गया था। उसके नीचे काफी संख्या में लोगों ने आश्रय लिया था। लाओत्से ने उस पेड़ की तरफ और फिर कट रहे पेड़ों की तरफ देखकर अपने शिष्य से कहा, 'इस बड़े पेड़ को छोड़कर लोग दूसरे सारे पेड़ों को काट रहे हैं। कारण पूछकर आओ, जरूर इसमें कोई रहस्य होगा।' शिष्य एक सज्जन के पास पहुंचे और उससे पूछा, 'भाई, तुम लोग सारे पेड़ों को काट रहे हो, सिवाय उस पेड़ के जहां सभी लोग इकट्ठा हैं और बैलगाड़ियां खड़ी हैं, ऐसा क्यों?' उस व्यक्ति ने जवाब दिया, 'उस पेड़ के नीचे लोग आश्रय पाते हैं। एक साथ काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। गर्मी जब अंगारे बरसाती है, तो वह पेड़ सबको छाया और शीतल हवा देता है। जो पेड़ कट रहे हैं, उनमें ऐसी बातें नहीं। वे न तो छाया देते हैं और न ही इनमें मीठे फल लगते हैं। उस बड़े पेड़ को काट देने से ये सारी सुविधाएं कहां से पाएंगे? लेकिन ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम सिर्फ जलावन में कर सकते हैं।' शिष्यों ने आकर लाओत्से को सारी बात बताई। यह सुनकर लाओत्से ने शिष्यों से कहा, 'जो पेड़ उपयोगी हैं, उन्हें नहीं काटा जा रहा है। जो किसी काम के नहीं हैं, उनमें अहंकार भरा हुआ है। इसी प्रकार सहज स्वभाव वाले और उपयोगी मनुष्य का हर कोई सम्मान करता है।'

Subrata Dhar

संकलन : प्रीति सिन्हा

चाइनीज मार्केट में तेज़ी, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के कारण भारत का बना रहेगा अट्रैक्शन

चीन में राहत पैकेज, भारत में क्या होगा

मृत्युंजय राय

पिछले सप्ताह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 75वीं सालगिरह मनाई, लेकिन शी चिनफिंग का मन शायद ही जश्न के मूड में हो। असल में, चीन की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। कभी दहाई अंकों में बढ़ने वाली चाइनीज इकॉनमी अब 5% की ग्रोथ के लिए संघर्ष करती दिख रही है, जबकि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बना हुआ है।

बड़ा राहत पैकेज | चीन की आर्थिक मुश्किलों का असर उसके शेयर बाजार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेशकों ने चीन से बेरुखी दिखाई है, जबकि भारत की अच्छी ग्रोथ और लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ यहां के स्टॉक मार्केट को मिला है। खैर, शी चिनफिंग सरकार ने पिछले हफ्ते देश को सुस्त आर्थिक ग्रोथ से बाहर निकालने के लिए बड़े राहत पैकेज का एलान किया। यह 2008 के ग्लोबल फाइनैंशल क्राइसिस के बाद का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है।

कर्ज़दारों की मदद | चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) ने 24 सितंबर को इस पैकेज का एलान किया। उसने ब्याज दरों में कटौती की, बैंकों के लिए जितना रिजर्व रखना जरूरी है, केंद्रीय बैंक ने उसमें भी कमी की। इससे बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए अधिक पैसा होगा। यही नहीं, उसने होम लोन की लागत में भी कमी लाने के उपाय किए। इससे करीब 5 करोड़ होम लोन लेने वालों को साल में 21 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। जो कंपनियां शेयर बायबैक करेंगी, चीन का केंद्रीय बैंक उसकी खातिर लिए गए कर्ज की रीफाइनेंसिंग करेगा।

प्रांतीय सरकारों की हेल्प | इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए सरकार चीन की GDP के करीब 1.5% के बराबर बॉन्ड जारी करेगी। इसमें से आधी रकम का इस्तेमाल प्रांतीय सरकारों को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया जाएगा, जबकि बाकी आधे का प्रयोग कंपनियों और लोगों की ओर से खर्च बढ़ाने के लिए। अगर खर्च में बढ़ोतरी करने का यह मंसूबा सफल रहा तो इससे चीन की इकॉनमी को बेशक मदद मिलेगी। हाल के वर्षों में आर्थिक सुस्ती की वजह से पढ़े-लिखे लोगों को भी अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही थीं।

डर दूर करने का प्रयास | सिक्योरिटीज कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों और दूसरे संस्थागत निवेशकों को फंड जुटाने में मदद मिले, इसके लिए उनकी वैलेंस शीट को मजबूत बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र की चीनी कंपनियों पर सख्ती के बाद निवेशकों के मन में डर बन गया था, ऐसा लगता है कि इसके जरिये उसे दूर करने की कोशिश की गई है।

चीन की मुश्किल
- फैकेज से मांग बढ़ाने का प्रयास
- 5% का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण
- स्ट्रक्चरल चैलेंज, बेरोजगारी

16 साल का रेकॉर्ड | स्टॉक मार्केट का चीन के राहत पैकेज पर जो रेस्पॉन्स रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि निवेशकों के बीच पॉजिटिव संकेत गया है। इसी वजह से पिछले हफ्ते चीन के शेयर बाजारों में 16 साल की सबसे बड़ी तेजी आई, जबकि हॉन्गकॉन्ग के मार्केट में ढाई दशक की सबसे बड़ी उछाल।

भारतीय बाजार महंगा | पहले चीन के मार्केट में सुस्ती और विदेशी निवेशकों के वहां से पैसा निकालने का फायदा भारत को मिला है। भारत में कोविड की मंदी के बाद बाजार में बुल रन चल रहा है और वैल्यूएशन अधिक हो गया है। म्युचुअल फंड बड़े पैमाने पर कैश होल्ड कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वैल्यूएशन अधिक होने से बाजार में गिरावट आनी चाहिए और तब आकर्षक लेवल पर वे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे।

छोटे निवेशकों की ताकत | विदेशी निवेशक भी मौजूदा लेवल पर एहतियात के साथ भारत में निवेश कर रहे हैं। अगर वे भारी-भरकम राहत पैकेज के एलान के बाद भारत से पैसा निकालकर चीन ले जाते हैं तो इससे यहां के मार्केट पर दबाव बन सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से घरेलू छोटे निवेशक इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, उससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिल सकता है।

बुनियादी समस्या | वहीं, चीन को इकॉनमी प्रॉपर्टी की वैल्यू में आई गिरावट के बाद लो कंस्यूमर कॉन्फिडेंस का सामना कर रही है। उसके साथ दूसरी बुनियादी दिक्कतें भी हैं। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि क्या चीन के केंद्रीय बैंक के राहत पैकेज से ये मसले दूर हो जाएंगे?

भारत का टाइम | भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ दशकों तक यह तेज बनी रहेगी। ऐसे में संभावित ग्रोथ की वजह से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रह सकती है। खासतौर पर ऐसे विदेशी निवेशकों की, जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं।

चाइना प्लस वन | यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थन और इस बीच, हिंद-प्रशांत व ताइवान को लेकर अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ तनातनी बढ़ने की वजह से 'चाइना प्लस वन' की काफी चर्चा हो रही है। इसके तहत मल्टिनैशनल कंपनियां चीन से कुछ मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में ले जा रही हैं, जिसका फायदा भारत को भी मिल रहा है।

भारत का फायदा | अगर राहत पैकेज से चीन की इकॉनमी में रिकवरी होती है, तब भी इस ट्रेंड पर शायद ही असर पड़े। उसकी वजह जियो-पॉलिटिक्स है। इसलिए चाइना प्लस वन की पॉलिसी आगे भी जारी रह सकती है और उसका फायदा भारत को मिलता रहेगा।

अधूरेपन में सुंदरता? Wabi-sabi से समझिए

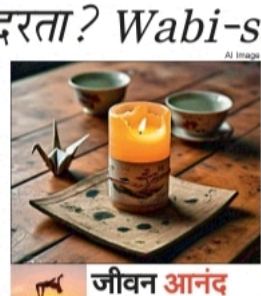

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

कुछ दीवारें मिट्टी की थी और कुछ सूखी-चूने की। बनाने वाले से जब जैसे बन पड़ा, उसने वैसे-वैसे ईंटें जमा दीं। हर कमरे की छत दूसरी से ऊपर या फिर नीचे और हर फर्श असमतल। फिर भी कुछ खास था उसमें। दरारों से झांकती पुरानी चिनाई ऐसी लगती, मानो किसी पेंटिंग का खाका खींचा जा रहा। घिस चुकी चौखट इतने बरसों के मौसम का रेकॉर्ड सहेजे हुए थी और आड़ा-तिरछा आंगन उन पुरानी बातों का जो उसने सुने।

वह पुराना घर परफेक्ट नहीं था, लेकिन खूबसूरत था। उसमें कमियां थीं, लेकिन वही उसकी खूबियां थीं। वह अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन तो उसे मिटना ही था। वह अपरिपूर्णता में भी परिपूर्ण था। वह Wabi-sabi था।

जापानी दर्शन जीवन को देखने, समझने और उसे जीने का एक नया नजरिया देता है। ऐसा ही दर्शन है वाबी साबी, जेन बौद्ध धर्म से प्रभावित। यह खामियों, असमानताओं, नश्वरता और अधूरेपन में सुंदरता देखता है। हमें प्रेरित करता है कि कमियों को नजरअंदाज कर उसमें बसे सौंदर्य को देखें और उसका आनंद लें। लेखक लियोनार्ड कोरेन के शब्दों में, जब हम किसी चीज को बदसूरत मानते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं, तब सुंदरता आती है। ये दोनों स्थितियां अलग-अलग नहीं हैं। नजरिया, परिस्थिति और समय सही हो तो सुंदरता कहीं भी दिख सकती है।

दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और अगर हमारे हिसाब से कुछ परफेक्ट है भी तो वह हमेशा बना नहीं रहेगा। इसके बाद भी हम अपने जीवन का बहुत हिस्सा चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश में निकाल देते हैं। क्या कोई नदी देखी है सरल रेखा में चलते हुए या बिल्कुल त्रिभुज के आकार का कोई पहाड़? न बादल सम होते हैं और न हवा एक जैसी चलती है। फिर भी इनका तालमेल कितना खूबसूरत है। और हम हैं कि कप-प्लेट का सेट बिगड़ने से परेशान हैं, परेशान हैं कि नए सोफा पर दाग लग गया और ड्रॉइंगरूम की एक टाइल्स चिटक गई। वाबी साबी से पूछिए तो जवाब मिलेगा कि इस दाग में, बिगड़ने में और चिटकन में भी खूबसूरती है। आज जब सभी परफेक्शन की तलाश में भटक रहे हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी फिल्टर के पीछे असलियत को छिपाया जा रहा, तब यह जापानी दर्शन दिखावे से दूर रहने की सलाह देता है।

सभी जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला। वक्त का असर पड़ना ही है और उसके निशान बहुत गहरे होते हैं। कोई भी मरम्मत उन्हें छिपा नहीं सकती और वाबी साबी के हिसाब से छिपाने की जरूरत है भी नहीं। समय के साथ आने वाला बदलाव तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए उगेंगे। पीली पड़ती पत्तियों को देखकर शोक क्यों मनाना, जबकि यह स्वाभाविक है। जापानी दर्शन इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रकृति के चक्र को समझें और समय के साथ आने वाले बदलावों को सराहें। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर पड़ी झुर्रियां क्या बेकार लगती हैं? पुराने घर, पुराने पेड़, पुराने लोग- क्या इनकी अहमियत इस बात से कम हो सकती है कि ये पुराने हैं? किसी भी चीज का मोल उसकी उम्र और अनोखी स्वरूप से बढ़ता है।

यह दर्शन मदद करता है साधारण और कमजोर चीजों में भी खूबसूरती देखने में। सभी का अपना महत्व है और कोई भी कभी पूरी तरह बेकार नहीं होता। वाबी-साबी केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, एक आंतरिक अनुभव है। इससे जीवन के अधूरेपन को भी स्वीकार करना सीखा जा सकता है। आनंद पाने का यह भी एक तरीका है।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'जीवन आनंद'

डेटा की दुनिया में भी बराबर हक़ नहीं

ऑनलाइन मीडिया पर जेंडर वॉर चल रही है। ग्लोबल ऑनलाइन कम्युनिटी में ऐसे पुरुषों की कमी नहीं, जिनका मानना है कि वे शोषित हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी ये लोग मानते हैं कि बच्चे पालना और खाना पकाना औरतों का काम है, भले ही वे औरतें उनकी तरह कामकाजी हों। ये वही पुरुष हैं, जो यह भी मानते हैं कि औरतों में नेतृत्व क्षमता नहीं होती। उन्हें अगर वर्कप्लेस पर सराहा जाता है या प्रोमोशन मिलता है तो उसकी वजह उनका बेहतर पेशेवर होना नहीं है, उन्हें दूसरे कारणों से ऐसे रिवॉर्ड मिलते हैं। ऐसी सोच किस तरह से राजनीति पर असर डाल रही है, इसे जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा में बढ़ रहे पुरुषों के रुझान के रूप में भी देखा जा सकता है।

फेमिनिज्म के जरिये इस सोच से दुनिया में लंबी लड़ाई चलती आई है। फेमिनिज्म इस बुनियादी सोच पर आधारित है कि पुरुष और महिलाएं सभी अहम मामलों में बराबर हैं। इस बुनियादी बात को समझने की कोशिश काफी वक्त से हो रही है, फिर भी आपको समाज में ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जो शारीरिक बनावट या कुछ शारीरिक श्रम वाले कामों का हवाला देते हुए इसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि महिलाएं अच्छी मेकेनिक नहीं हो सकतीं। ऑयल रिग में पुरुष ही काम कर सकते हैं और करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुरुष ही होते हैं। उनके मुताबिक, अहम इनोवेशन करने वालों में पुरुष ही हैं, लेकिन ये लोग बड़ी चालाकी से साइंस की दुनिया में महिलाओं के योगदान पर परदा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि आज जो समूद्र दुनिया दिख रही है, इसमें दोनों ही जेंडर के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। वे एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन सबके बावजूद आज भी औरतों को अपने हक के लिए घर-बाहर संघर्ष करना पड़ रहा है। फेमिनिज्म से जुड़े लोगों ने इस बराबरी की बात को एक्टिविज्म, राजनीति, आर्थिक और यहां तक कि कला के जरिये व्यापक तौर पर पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी समाज के जो हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि यह लड़ाई और लंबी चलने वाली है।

2019 में **Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men** नाम की किताब आई, जिसने इस बहस को लेकर एक अलग ही पहलू सामने रखा। कैरोलाइन पेरेज (Caroline Perez) ब्रिटिश लेखक हैं, जिन्होंने अपनी किताब के जरिये 'जेंडर डेटा गैप' की ओर ध्यान दिलाया। इस किताब में कैरोलाइन विषय को समझाने के लिए हेल्थकेयर, पैमिली लाइफ और मीडिया से जुड़ी मिसालें देती हैं। वह लिखती हैं कि कारें, फोन, कपड़े, दवाएं और परिवहन व्यवस्था को पुरुषों के बारे में मिले डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए इसके अंजाम खतरनाक होते हैं। कैरोलाइन किताब में बताती हैं कि ब्रिटेन में जब महिलाओं को हार्ट अटैक आता है तो पुरुषों की तुलना में उनकी बीमारी के बारे में अस्पताल से गलती होने की आशंका 50% अधिक होती है। यानी अस्पताल या डॉक्टर उनके मर्ज के बारे में सही-सही पता नहीं लगा पाते। वहीं, कार हादसों में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मृत्यु होने की आशंका 17% ज्यादा होती है। जेंडर डेटा गैप की समस्या इतनी बड़ी है कि इससे आधुनिक तकनीक तक प्रभावित हैं। कैरोलाइन पेरेज बताती हैं कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी बेहद आधुनिक तकनीक में महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रह है। वह लिखती हैं कि जिस तरह से डेटा मशीनों को ट्रेंड किया गया है, उसी वजह से ऐसी गलतियां होती हैं।

AI Image

विचार विंडो

सरनेम का सवाल

प्रणव प्रियदर्शी

पिछले हफ्ते जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने सिंगेल इशिबा को अपना नया नेता चुना। वह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहीं साने ताकाइची। 67 साल के इशिबा और 63 साल की ताकाइची के बीच कांटे की टक्कर वाले इस चुनावी मुकाबले को जिन कुछेक बातों ने दिलचस्प बनाया उनमें प्रमुख थी शादी के बाद सरनेम बदलने से जुड़ी बहस। जापान में सदियों पुराना एक कानून आज भी लागू है, जिसके मुताबिक शादी के बाद कपल अपना अलग-अलग सरनेम नहीं रख सकते। लिहाजा 95% मामलों में महिलाओं को अपना सरनेम बदलना पड़ता है। इस कानून को लेकर वहां दशकों से बहस चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि पुरुष होने के बावजूद जहां इशिबा इस कानून को समाप्त करने के पक्ष में हैं, वहीं महिला होते हुए भी ताकाइची इसमें फेरबदल के खिलाफ। तो इशिबा की जीत इस मायने में भी अहम है कि अब जापानी महिलाओं को मेइजी युग (1868-1912) से चले आ रहे इस कानून से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। शादी के बाद सरनेम बदलने का कानून रखने वाला जापान भले ही दुनिया का इकलौता देश हो, यह चलन भारतीय समाज में भी है। इसके जरिए महिलाओं को उनकी अपनी वैयक्तिक, सार्वजनिक पहचान से वंचित कर दिया जाता है। पब्लिक स्पेस से महिलाओं को अदृश्य करने और इस तरह उन्हें सेकंड क्लास सिटिजन की हैसियत में डाल देने वाला यह चलन अगर आज भी बदस्तूर चला आ रहा है तो उसके पीछे परिवार और समाज की ओर से आने वाला भावनात्मक दबाव तो है ही, कानून की शक्तियां भी है। भले ही भारत में सरनेम बदलना अनिवार्य करने वाला कोई कानून न तो, पासपोर्ट बनवाने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने और बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाने तक हर कदम पर पत्नी के अलग सरनेम को एक बाधा के रूप में देखा जाता है।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

शक्ति और साहस

'जीवन आनंद' कॉलम में 23 सितंबर को प्रकाशित लेख 'वे सुपरहीरो अब भी वहीं, हम ही कहीं खो गए' पढ़ा। कॉमिक्स का जादू वास्तव में अद्वितीय है। वे न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी जिंदा रखती हैं। लेखक ने बिलकुल सही कहा है कि कॉमिक्स के किरदारों की शक्ति और साहस हमें प्रेरित करते हैं, जबकि उनकी सहजता में हम अपनी पहचान खोजते हैं। उन चरित्रों से हमें सीखने को मिलता है सही रास्ते पर चलना और जरूरतमंदों की मदद करना। कॉमिक्स के किरदार कभी पुराने नहीं पड़ते।

कृतिका झा, ईमेल से

कितावों में ताजगी

यह पत्र 16 सितंबर के लेख 'समय की खुशबू से भरी एक पुरानी किताब' से संबंधित है। पुरानी किताबों की खुशबू हमें अनोखी और पुरानी यादों में ले जाती है। जब हम उनके पन्नों को खोलते हैं, तो एक अजीब-सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई पुराना दोस्त वापस आ गया हो। यह खुशबू हमें अतीत की यादों से जोड़ती है। बचपन की बातें, पहली बार पढ़ी गई कहानियां और उन लम्हों की ताजगी जब हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। शब्दों का जादू हमें अपनी कल्पनाओं में खो जाने की अनुमति देता है।

मनोहर रावत, ईमेल से

समय का महत्व

समय पर कोई काम हो जाना एक अद्भुत अनुभूति है। यह न केवल संतोष देती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जब हम किसी काम को समय पर पूरा करते हैं, तो हमें एक उपलब्धि का अहसास होता है। यह खुशी उस पल से शुरू होती है, जब हम काम को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। समय पर काम करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम समय सीमा का पालन करते हैं, तो यह न केवल हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है, बल्कि हमें दूसरों की नजरों में विश्वसनीय बनाता है।

धर्मेंद्र सिंह, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

जीवन आनंद

अंतिम पत्र

एयर इंडिया के खाने में फिर मिला कॉकरोच - एक खबर
- लगता है, कॉकरोच और एयर इंडिया का पुराना नाता है।

कविता रानी

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलना सिखाता है श्राद्ध

ब्रह्मा कुमारी शुक्ला

पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, पिंड दान और तिल जल तर्पण से उनकी तृप्ति होती है। कहते हैं, मृत्यु के बाद मानव आत्मा देह के बंधन से तो मुक्त हो जाती है, पर पिंड और भोजन मिलने तक अतृप्त रहती है। इसलिए पिंड दान और ब्राह्मण, पशु-पक्षी आदि को खाना खिलाने की प्रथा है।

पितृ पक्ष मूल रूप से पूर्वजों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बेला है। यह समय पितरों के परिजनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह समय हमें दान देने, अहंकार का त्याग करने, बुराइयों से बचने, किसी का भी अपमान नहीं करने और पितरों के बताए कार्य को याद कर उनका आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। इस प्रथा से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि अपने जीवित माता-पिता और बड़ों का कभी अनादर, अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो उसी समय हम उनकी बद्दुआ के पात्र बनते हैं। दूसरा, उनकी मृत्यु के बाद किया गया श्राद्ध भी हमारे लिए उपहास और पश्चात्ताप का कारण बन जाता है।

इसलिए हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने माता-पिता, दादा-दादियों और बुजुर्गों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उनके लिए हमेशा आदर-सम्मान और श्रद्धा भाव रखना है। साथ ही, उनके शुभ विचार, भावना, बोल और शुभ उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और सेवांजलि है। देखा जाए तो मानवीय संबंधों के तीन आयाम हैं- भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक। हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंध अगर भौतिकता की नींव पर खड़े हैं तो वह संबंध क्षण स्थायी है। लेकिन नैतिकता और आध्यात्मिकता के आधार पर बने हुए रिश्ते दीर्घ स्थायी होते हैं। आध्यात्मिकता का समावेश होने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता, प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ सेवा भाव विकसित होते हैं। अंतर्मन में सचाई, स्पष्टई और अच्छाई की पुनर्स्थापना होती है।

भगवत गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा साधना के जरिए मनुष्य आत्माओं को इस मृत्युलोक से पितृलोक होकर ब्रह्मलोक, मुक्तिधाम और परमधाम में ले चलते हैं। वहां से दैवी संस्कारों वाली आत्माएं अवतरित होती हैं। वे दैवी-देवताओं के पिंड और चोला प्राप्त कर स्वर्ग और सतयुग में सुख-शांति-समृद्धि का जीवन जीती हैं। इसको ही परमात्मा की हम पर कृपा कहते हैं। इसे पाने के लिए हमें अपने रूहानी पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा विकसित करनी होगी। मनोविकारों का दान देना होगा व अपना और सर्व आत्माओं की श्रेष्ठ गति और सद्गति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और योग ध्यान का नियमित अभ्यास और योग तर्पण करना होगा।

इस परमात्म ज्ञान और सहज राजयोग के नियमित अभ्यास से ही हमारे जीवन में सकारात्मक वैश्विक सोच का विकास होगा। इससे न केवल जीवन, आचरण और सांसारिक संबंध बेहतर होंगे, बल्कि हम पूरे विश्व परिवार की आत्माओं के लिए सुख-शांति और मुक्ति की राह में पथ प्रदर्शक बन सकते हैं।

इस अंक में शामिल है: 24 पेज का 8 पन्नों का नवभारत टाइम्स। विविध जानकारी के लिए संलग्न है: 16 पेज का 8 पन्नों का अंतिम पृष्ठ। मुद्रक: प्रिंटमैक्स। संस्करणों की संख्या: 1 नई दिल्ली: 1 मुंबई: 1 कोलकाता: 1 चेन्नई: 1 बेंगलुरु: 1 हैदराबाद: 1 पुणे: 1 अहमदाबाद: 1 लखनऊ: 1 पटना: 1 रांची: 1 भोपाल: 1 चंडीगढ़: 1 जयपुर: 1 देहरादून: 1 शिमला: 1 श्रीनगर: 1 जम्मू: 1 रायपुर: 1 बिलासपुर: 1 भुवनेश्वर: 1 कटक: 1 गुवाहाटी: 1 कोलकाता: 1 पटना: 1 रांची: 1 भोपाल: 1 चंडीगढ़: 1 जयपुर: 1 देहरादून: 1 शिमला: 1 श्रीनगर: 1 जम्मू: 1 रायपुर: 1 बिलासपुर: 1 भुवनेश्वर: 1 कटक: 1 गुवाहाटी: 1 कोलकाता: 1 पटना: 1 रांची: 1 भोपाल: 1 चंडीगढ़: 1 जयपुर: 1 देहरादून: 1 शिमला: 1 श

सम्पादकीय

जान का दुश्मन प्रदूषण

इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। यह तो तब है जबकि दो दिन छोड़ दिये जायें तो पूरा सितंबर दिल्ली में पानी बरसा है। इसके बावजूद अगर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 200-250 पार कर रहा है तो चिंता बढ़ने लगती है। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से ही डट गयी है और सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान शुरू भी कर दिया गया है लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इसे रोका जाये। दिल्ली सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया है कि उसने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभी से टास्क फोर्स गठित कर दी है। एंटी स्मॉग गन के अलावा ड्रोन से निगरानी के प्लान घोषित कर दिये हैं। नारे दिये गये हैं- मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें लेकिन हमारा सवाल वायु गुणवत्ता के खराब होने की लेकर है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वायु प्रदूषण का स्तर 300-350 पार कर जाता है तो ऑड-ईवन से लेकर वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचा जा सकता है।

हर साल अक्तूबर-नवंबर में धान के ठूठ को जलाने का सिलसिला जब शुरू होता है तो वायुमंडल में धूएं की चादर बनती है और यह उत्तर भारत को लील लेता है। सोशल मीडिया के अनुसार पूरे उत्तर भारत में पराली पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी-मध्यप्रदेश तक जलती है लेकिन दिल्ली में दमघोंटू वातावरण बन जाता है। ताजा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जरूरी यह है कि वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए हरियाली का अभियान शुरू किया जाये। पिछली सरकारों ने हरियाली लाने के लिए दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। चाहे वह मदनलाल खुराना की सरकार रही हो या शीला दीक्षित की सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए अभियान चलाए और शीला दीक्षित ने तो विशेष रूप से दीवालों के पटाखों से युवा पीढ़ी को दूर रखने के लिए अभियान चलाए। वह दीवालों के दिनों में खुद स्कूलों में जाकर पटाखे न चलाने की अपील स्टूडेंट्स से करती रही, हालांकि इस कड़ी में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है और प्रदूषण के खात्मे के लिए अभी से जो तैयारी की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहां धूल उड़ती है उन डार्क स्पॉट पर ड्रोन उड़ाने की तैयारी है। इससे पहले कि प्रदूषण का आंकड़ा 400 पार हो तैयारी कर लेना अच्छी बात है।

मैंने इस बारे में जानकारी ली तो रोड स्वीपींग मशीन और छिड़काव करने वाली मशीनों के बारे में भी पता चला। निर्माण कार्य पर रोक भी जरूरी है। एंटी स्मॉग गन भी लांच की जा रही है। मेरा फिर भी व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पानी का छिड़काव बहुत बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। जो वायु प्रदूषण अक्तूबर-नवंबर में होना था वह अभी से खतरे की घंटी बजा रहा है, उसे लेकर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जब मैं सोशल मीडिया पर लोगों की अभिव्यक्ति को सुनती हूं तो हैरान हो जाती हूं कि दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ वाहन ही वाहन हैं। इनमें बैटरी चालित वाहन भी हैं और पैट्रोल तथा धुआं फैकने वाले वाहन भी हैं। एक दिन में दिल्ली की सभी सड़कों पर सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार बारह से बीस लाख वाहन चल रहे होते हैं।

महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा 29 नवम्बर से पहले घोषणा के पहले ही होगा कोई बड़ा खेला

अजित पवार के अलग ट्रैक पर दौड़ने के पीछे एक वजह सीट बंटवारे के पेच को भी बताया जा रहा है। महायुति में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में 105 सीटों पर जीत मिली थी। शिंदे की शिवसेना और अजित की एनसीपी, दोनों के ही 40-40 विधायक हैं। भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो वहीं शिंदे की पार्टी ने भी 107 सीटों पर दावेदारी कर दी है। अजित पवार भी यह दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 60 से 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग के पेच को देखते हुए भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि महायुति से किसी एक दल की एग्जिट हो सकती है।

अशोक भाटिया

ताजा समाचारों के अनुसार महाराष्ट्र में इस साल 29 नवम्बर के पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और चुनावों की घोषणा से पहले सत्ताधारी महायुति के घटक दलों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग, विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की थी। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को सम्मानजनक संख्या में सीटें देने का आश्वासन दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजित पवार बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। अजित की पार्टी महायुति में शामिल हुई तो उसके पीछे डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी नजदीकी के भी चर्चे रहे लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों नेताओं के बीच दूरियों की चर्चा जोरों पर रही है। इस तरह की चर्चा को लाड़ली बहिन योजना को लेकर छिड़े क्रेडिट वॉर ने भी और हवा दे दी। एनसीपी ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि लाड़ली -बहिन योजना के तहत अजित पवार पैसे दे रहे हैं। इसमें कहीं भी सीएम सिंदे या डिप्टी सीएम फडणवीस का जिक्र नहीं था। इसके बाद भाजपा की ओर से बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगवाई गई थीं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम सिंदे की छोटी-छोटी तस्वीरों के साथ देवेंद्र फडणवीस की बड़ी फोटो छपी थी। इन होर्डिंग्स पर अजित की न तो फोटो थी और ना ही कहीं नाम। ये होर्डिंग्स अजित पवार के इलाके बारामती के साथ ही वहां भी लगाई गईं, जिन्हें एनसीपी का गढ़ माना जाता है। बाद में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की तल्खी भी पिछले कुछ दिनों में खुलकर सामने आने लगी । तानाजी सावंत से लेकर गुलाबराव पाटिल तक, शिंदे सरकार में शिवसेना के मंत्री अजित पवार को टार्गेट करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। सावंत ने अजित पर निशाना साधते हुए कहा था कि जीवनभर कांग्रेस और एनसीपी के विरोध की राजनीति की है। कैबिनेट में उनके बगल में बैठता हूं लेकिन बाहर आने के बाद उल्टी आती है।

वहीं, मंत्री गुलाबराव ने भी हाल ही में वित्त विभाग को सरकार का सबसे बेकार विभाग बताया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजित के वित्त मंत्री होने को ही आधार बनाते हुए कई आरोप लगा शिंदे की अगुवाई में बगावत कर एमवीए सरकार गिराने वाले शिवसेना विधायक सरकार में अजित को लिए जाने, वित्त मंत्री बनाए जाने के बाद से ही असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल, एनसीपी और शिवसेना दोनों ही बगावत के बाद खुद को असली पार्टी बताते आए हैं। नाम-निशान की लड़ाई भी दोनों जीत चुके हैं लेकिन अब विधानसभा चुनाव में दोनों के सामने खुद को असली पार्टी के रूप में ले जाने की चुनौती भी है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने कुल 288 में से 164 और शिवसेना ने 126 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं, विपक्षी गठबंधन में एनसीपी के हिस्से 121 सीटें आई थीं। अब महायुति में शामिल हर दल चाहता है कि वह अपने पिछले चुनाव की पोजिशन बरकरार रखे। बताया यह भी जा रहा है कि अजित पवार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले तो नतीजे तो मनमाफिक नहीं ही आये थे ऊपर से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से निराश और भी बढ़ने लगी थी। बहरहाल अजित पवार कभी यात्रा के बहाने तो कभी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण लगातार लोगों के बीच रहने को कोशिश कर रहे हैं, और बीच बीच में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भाजपा पर दबाव बढ़ाया जा सके - राहुल गांधी के मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता का सरेआम विरोध, और महाराष्ट्र भाजपा के एक बड़े नेता का प्रोजेक्ट नामंजूर करने में उनकी भूमिका तो यही कहती है कि किसी न किसी तरीके से वो अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाये जाने के मामले में तो वो पहले ही अफसोस जता चुके हैं - और सच तो ये भी है कि संघ भी भाजपा के अजित पवार के साथ आने से खासा नाराज है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर हुई पारिवारिक लड़ाई पर अजित पवार का अफसोस जताना तो चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के आरक्षण पर आये बयान का सपोर्ट तो बिलकुल ही अलग मामला हो जाता है। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के बयान पर काफी विवाद हुआ था। इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन मायावती और भाजपा नेता तो धावा ही बोल दिये थे। और सबसे आगे तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ नजर आये। संजय गायकवाड़ ने तो सीधे सीधे राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की ही घोषणा कर डाली। महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बुलढाणा थाने में संजय गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना तो उनका हक बनता है, लेकिन अजित पवार की तरफ से इस मामले में नाराजगी जताया जाना तो हैरान ही करता है।

एनसीपी नेता अजित पवार ने संजय गायकवाड़ के बयान से इतने नाराज हुए कि वो उनको मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगे। अजित पवार का कहना था, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है ये अधिकार संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या और कोई भी होन जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए।जब भाजपा नेता ही नहीं बल्कि मायावती जैसी नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हों, ऐसे में अजित पवार का आगे बढ़ कर कांग्रेस नेता का पक्ष लेना, शक तो पैदा करता ही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें अजित पवार के चाचा शरद पवार वाली एनसीपी भी शामिल है।

पुणे में एनसीपी की तरफ से संविधान सभा कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में अजित पवार का धर्मनिरपेक्षता की बात पर खास जोर दिखा था। ये ज्यादा खास इसलिए भी लगा क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अजित पवार की तरफ से ये साफ करने की कोशिश लगती है कि वो भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे से खुद को पूरी तरह अलग रखना चाहते हैं। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत में अजित पवार कहते हैं, हमें राष्ट्रवाद के मामले में किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है> हम अपने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के मूल्यों के साथ खड़े हैं।

आज का राशिफल

गलते अनुभवों अकोशिकों तो रोत के अनुभव अब नई विधि लाने तो कुछ होगेंगे कब अब वह समझा पाते है कि अपने जीवन के ऐसे तौकतो बोल है, जब अपने जिंदगे कुछ होंगे और दूसरों तरफ, अपनी दिल बाते तो लगातार लगा रहेंगा। तब न किसी तरफ़ो सहज में और अंदित हुई तो सुलझते तक लगातारगत ऊर्जा को समझ सकेंगे, क्रीएट फाउन्डेशन सबसे हैं तो, सब तक लगातारगत सभी सहज और बराबरी में सहज प्रदान करेंगा

मेष
आज वाणी पर संयम रखें। खेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

वृष
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

मिथुन
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

कर्क
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। मित्रों और प्रियपात्र के साथ मुलाकात सुखद होगी।

सिंह
दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कन्या
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

तुला
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और खेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

वृश्चिक
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

धनु
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

मकर
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

कुंभ
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

मीन
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है। खेहीजनों के साथ परिहास बढ़ेगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

'हमें सिर्फ कर्म करना है, फल उस महाशक्ति के पास है,हम जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ करें क्योंकि कर्म हमारे हाथ मे है तो निश्चित ही फल मधुर ही मिलेगा '

नमस्कार मित्रों हमारी आज शख्सियत कॉलम के सुपर डुपर स्टार हैं भारतीय पुलिस सेवा के जांबाज अधिकारी के रूप में जाने वाले अजय पाल लांबा। इनका जन्म 7 अगस्त सन 1978 को सीकर जिले में हुआ जहां इन्होंने अपनी एजुकेशन पूर्ण की। शिक्षा में इन्होंने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में पूरी की इसके बाद सिविल सर्विसेज में आए और आईपीएस बन कर अंडर ट्रेनिंग हैदराबाद रहे । उसके बाद राजस्थान पुलिस अकादमी में अंडर ट्रेनिंग रहे। उदयपुर में अंडर ट्रेनिंग रहे उसे समय जब राजस्थान के जांबाज आईपीएस दिनेश में एसपी रहे उदयपुर थे। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक अलवर रहे, सबसे पहले एसपी शिप सीआईडी सीबी में मिली, उसके बाद एसपी झुंझुनू लगे, एसपी पाली, एसपी जयपुर ग्रामीण, डीसीपी जोधपुर, एसपी उदयपुर, एसपी अलवर, एसपी एएसटी जोधपुर, एसपी जयपुर ग्रामीण उसके बाद पदोन्नति होकर एडिशनल कमिश्नर सेकंड और बाद में सरकार ने इन्हें एडिशन कमिश्नर फर्स्ट लगाया। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में इन्होंने बड़े-बड़े बदमाशों के पेच ढीले किए। इसके बाद फिर पदोन्नति हुई और जिस जिले में अंडर ट्रेनिंग रहे जिस जिले में एसपी रहे वही रेंज आईजी बने और इस समय जयपुर रेंज आईजी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अपराधी और अपराध से इनका बाद विशेष नाता है अपराधी इनसे बचकर भागता है और अपराध इनसे माफी मांगता है। जी हां पूरे विश्व में सुर्खियों में आए जब यह उदयपुर थे तो यौन शोषण मामले में कथित बाबा आसाराम बापू को इन्होंने ही जेल में डाला। हालात विकट थे स्थिति विपरीत थी और व्यवस्थाएं अनुकूल थी उसके बावजूद भी सत्य का दामन थामा और आसाराम बापू को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया। बहुत जांबाज पुलिस अधीक्षक के रूप में इन्होंने जिले की कमान संभाली थी। आज सरकार ने इन्हें रेंज

अजयपाल लांबा
(रेंज आईजी, जयपुर)

आईजी जयपुर नियुक्त किया है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बहुत जांबाज अफसर हैं और अपने सबोर्डिनेट का पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी पीठ थापा कर उनका हौसला अफजाई करते हैं। यंग और डायनामिक पुलिस अधिकारी के रूप में वह युवाओं के आदर्श भी हैं। एक जज्बे के रूप में पुलिसिंग करना कोई उनसे सीखे। बेहद शानदार व्यक्तित्व और खुबसूरत अंदाज अजय पाल लांबा को अजय बनता है।

जय हिंद
रूपक शर्मा

आज का इतिहास

30 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- नीदरलैंड एवं स्वीडन ने 1681 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर 1687 को कब्जा किया।
- अमेरिकी आविष्कारक सैमुएल स्लॉकम ने 1841 में 'स्टेप्लर' का पेटेंट कराया।
- अमेरिकी डेंटिस्ट डॉ. विलियम मॉर्टन ने 1846 में सबसे पहले मरीज का दांत निकालने को 'निश्चेतक ईथर' का प्रयोग किया।
- हेनरी ड्रेपर ने 1880 में ओरायन नेब्यूला का पहला चित्र लिया।
- एण्डेटन में विश्व का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र 1882 में शुरु हुआ।
- लेबनान के प्रसिद्ध कलाकार, कवि और लेखक जिबरान खलील ने 1895 में शिक्षा आरंभ की।
- अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की स्थापना 1898 में हुई।
- मनुष्य को ले जाने योग्य पहले रॉकेट ने 1929 को उड़ान भरी।
- जर्मनी में मूनीख का ऐतिहासिक सम्मेलन 1938 में आयोजित हुआ। जिसमें जर्मनी के नेता हिटलर, इटली के नेता मोसोलीनी, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड डेलाडी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नोवल चेम्बरलेन ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जर्मनी और चेकोस्लावाकिया के बीच मतभेदों के दूर करने का मार्ग खोजना था।
- जर्मनी और रूस पोलैंड के विभाजन पर 1939 में सहमत हुए।
- पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्रसंघ में 1947 को शामिल हुए।
- फ्रेंच गुएना 1958 में आजाद होकर गुएना गणराज्य बना।
- सीरिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से 1961 में निकल गया।
- दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश संरक्षित राज्य बेचुआनालैंड ने 1966 में स्वतंत्रता की घोषणा की और बोत्सवाना गणतंत्र बना।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 1967 को मौद्रिक प्रणाली में सुधार किया।
- उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार 1984 में सीमाएँ खोली गईं।
- भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में 1993 को भूकम्प के कारण 10,000 हजार से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए।
- इस्रायल की आतंरिक मंत्रिपरिषद ने 2001 में फ़िलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी।
- पाकिस्तान में 2002 को कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा, चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की।
- विश्वनाथन आनंद ने 2003 में विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती।
- चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की 2004 में 2555वीं जयंती मनाई गयी।

विशेष आलेख

ग्रामीण भारत की सूरत बदलती कृषि

विजय शर्मा

तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी है। पहले सौ दिनों में ही सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की मंजूरी दी। सरकार का पूरा जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने पर है। इसके लिए वह भूमि रिकार्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ-साथ उसकी मानिटरिंग और नीकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां आज दिख रही हैं, उसकी कवायद लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले से ही शुरू कर दी थी। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वह अगले पांच साल का रोडमैप और सौ दिनों का एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान लागू करने के लिए सचिवों की दस समितियां बनाई गईं। सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। कारोबारियों, सिविल सोसायटी और युवाओं से भी सुझाव मांगे गए। इसके लिए दो हजार से अधिक बैठकें की गईं। इन सभी के निष्कर्ष से एक्शन प्लान का रोडमैप बना।

सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों का विकास हो। इसी को देखते हुए कृषि आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया है। गत दिनों इसके तहत सात योजनाओं के लिए 14, 200 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये और पशु स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये मुख्य हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में भी जुटी है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू होगा। किसानों को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने से सरकार को भी योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने अगले साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पहले सौ दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया, वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया, ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से

ही मोदी सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार नहीं आया। इसका कारण है कि देश में सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन का ढांचा गेहूं तथा धान जैसी चुनिंदा फसलों एवं इलाकों तक ही सिमटा है। अब सरकार दलहनी - तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद, भंडारण एवं विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेती से लेकर थाली तक विविधता आएगी। सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में तीन लाख पैक्स का गठन करना है, जो अभी 65,000 हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। राज्य सरकार एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपज की बिक्री का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। इससे गेहूं- धान वाली सफलता मोटे अनाजों एवं दलहनी- तिलहनी फसलों में दोहराई जाएगी। गेहूं-धान जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और उन पर आधारित उद्योग-धंधों के विकास पर फोकस कर रही है। इसी को देखते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। मछुआरों के कल्याण के लिए भी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत हर साल 170 लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है। इसी तरह पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी सरकार राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण से ही लगातार घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी बनाया जा सकेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हरीपुरा रोड़ खरगड़ा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पाठक* । प्रधान संपादक-राय विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-चेतराम सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

हिन्दुस्तान 1936

फिर सुलगती पराली

खेतों में धान की बालियों की कटाई के बाद खड़े-बचे सूखे पौधों अर्थात पराली को जलाने का घातक क्रम फिर शुरू हो गया है। उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में इस मौसम में वायु प्रदूषण का घना प्रकोप रहता है और एक समय ऐसा आ जाता है, जब घर से बाहर निकलने में भी परेशानी होने लगती है। अभी अक्तूबर का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, पर खेतों को जल्दी से जल्दी गहूं की फसल के लिए तैयार करने की होड़ में पंजाब-हरियाणा के किसान फिर खेतों में आग लगाने पर आमादा हैं। ऐसे में, प्रशंसनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय रहते संज्ञान लिया है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि पराली जलाने से निपटने के लिए आयोग को एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आयोग अपने आदेशों को जमीन पर उतारने में बहुत हद तक नाकाम रहा है। ऐसे में, न्यायालय की नाराजगी सराहनीय व स्वागत के योग्य है। संज्ञान में यह बात भी आई है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा मात्रा में पराली दहन हो रहा है।

न्यायाधीश अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा है कि आयोग ने कुछ कदम उठाए है, पर और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। आप मूकदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास और निर्देश वास्तव में प्रदूषण को घटा सकें। आयोग की जितनी बैठकें होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही हैं। आयोग ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 82 निर्देश जारी किए हैं, पर यह सुनिश्चित नहीं किया कि सभी निर्देशों की पालना हो। आयोग को अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने और उसके आदेशों का पालन न करने पर मुआवजा चुकाने का निर्देश देने का अधिकार है। अगर विभिन्न राज्यों में प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित अधिकारियों ने आदेशों-निर्देशों को नहीं माना है, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की तकलीफ आयोग ने नहीं उठाई है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक पूछा है कि अगर आयोग अपने निर्देशों की पालना नहीं करा पा रहा है, तो उसके निर्देशों का क्या महत्व है? अच्छे नेता, अच्छी संस्था, अच्छे निर्देश-आदेश का लाभ अगर प्रदेश-देश को न मिले, तो यह अफसोस और दुख की बात है। पराली दहन पर अनेक सरकारों का रुख लोग देख चुके हैं और इस मोर्चे पर शासन-प्रशासन की नाकामी किसी से छिपी नहीं है। पराली जलाने से रोकने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयास कतई पर्याप्त नहीं हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 82 आदेश-निर्देश जारी किए हैं, पर यह सुनिश्चित नहीं किया कि सभी आदेशों-निर्देशों की पालना हो।

पराली जलाने का दुखद दौर सितंबर से लेकर जनवरी तक चलता है। किसान तमाम अपील और चिंताओं को नकारकर पैसे बचाने के प्रति ज्यादा आग्रही होते हैं, जबकि स्वयं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। ऐसे किसानों को समय रहते सर्वोच्च न्यायालय की चिंता पर भी ध्यान देना चाहिए। पिछले साल भी न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि फसल अवशेष जलाने के क्रम को तत्काल रोका जाए, हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। राज्यों को भी एक-दूसरे पर दोष मढ़कर पीछा छुड़ाने की राजनीति से बाज आना चाहिए। इस बार लोगों को वायु प्रदूषण से राहत की बहुत उम्मीद है, पर अभी से जो लक्षण दिखने लगे हैं, वे चिंता बढ़ा रहे हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 सितंबर, 1949

बुनियादी इलाज

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की दक्षिण-पूर्वी एशियाई समिति का तीन दिन तक भारत की राजधानी में अधिवेशन इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की गिरी हुई दशा पर अच्छा प्रकाश डालता है। हमारे इस क्षेत्र में मनुष्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य-सुधार के लिए दवाइयों की कमी है, चिकित्सा के लिए व्यय करने की हमारी गुंजाइश कम है और जिस स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रहने तथा पौष्टिक आहार पर स्वास्थ्य का दारोमदार है, उसका भी हमारे यहां अभाव है। फलतः मलेरिया, हैजा, प्लेग, चेचक, क्षय और योनिजन्य रोगों का इस क्षेत्र में बाहुल्य है।.... प्रश्न यह है कि ऐसी हालत में क्या किया जाये?

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन का हमें आभार मानना चाहिए कि अपने विशेषज्ञों द्वारा वह हमारे क्षेत्र में बीमारियों के प्रतिबंध का प्रयत्न कर रहा है। क्षय, मलेरिया और अन्य रोगों के लिए उसके विशेषज्ञ हमारी सहायता को आ रहे हैं, विविध क्षेत्रों में अपने प्रयोग कर रहे हैं, रोगनाशक औषधियों का ज्ञान कराकर उन्हें यहां भिजवाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इससे हमें लाभ ही हुआ है और आगे भी होगा। अतः इस संगठन के अन्तर्गत हो रहे प्रयत्नों का हम समर्थन करते हैं। किन्तु, जैसा इसकी अध्यक्षता करते हुए श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्दरनायक ने कहा, इलाज या रोगनाशक औषधियां ही समस्या का निदान नहीं हैं। जिन बातों का स्वास्थ्य से निकट संबंध, यानी जिनके अभाव में स्वास्थ्य बिगड़ता है, उन पर भी ध्यान दिया जाना और उनका कुछ उपाय करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, खाद्य और पौष्टिक पदार्थों के अभाव को मिटाना होगा, गन्दगी दूर करनी होगी, रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना होगा, जिससे हमारे अन्दर रोग प्रतिबंध की क्षमता आयेगी और रोगी बनकर इलाज कराने के बदले हम रोग को रोकने में ही समर्थ होंगे। यह ऐसी बुनियादी बात है, जिस पर दोराय नहीं हो सकती और इसका दारोमदार इस पर है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। स्वास्थ्य संगठन के उपाध्यक्ष डा. ईलियट ने भी इसकी पुष्टि की, जब उन्होंने कहा कि 'आर्थिक स्थिति का स्वास्थ्य से बहुत संबंध रहता है, अतः स्वास्थ्य-सुधार के प्रयत्न के साथ आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न भी होना चाहिए।' अतएव रोगनाशक उपायों के साथ-साथ रोग के इस बुनियादी इलाज की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

छोटे निवेशकों से लूट पर लगे लगाम

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

आम लोगों की जेब से निकलकर पूरी रकम बड़ी मछलियों के खजाने में पहुंच जा रही है। नुकसान उठाने वाले निवेशकों में 75 फीसदी की सालाना कमाई पांच लाख रुपये से कम है।

भारत के शेयर बाजार में 1992 में एक घोटाला हुआ था। हर्षद मेहता घोटाले का नाम आज भी सुरसुरी पैदा कर देता है। पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला था और घोटाले से नुकसान उठाने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बड़े-बड़े बैंक व वित्तीय संस्थान थे। आम आदमी तक तो इसकी आंच तब पहुंची, जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ और शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा।

लेकिन आज की तारीख में जो हो रहा है, उसको क्या कहें? सेबी पिछले तीन-चार साल से लगातार चेता रही है। स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिए गए हैं और हरेक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते ही सबसे पहले चेतावनी दिखती है कि एफएंडओ में सौदा करने वाले दस में से नौ कारोबारियों को नुकसान होता है। मतलब साफ है, आगे खतरा है। मगर इस चेतावनी के बावजूद मुनाफे के लालच में लाखों लोग हर रोज इसी आंख कुएं में छलांग लगा रहे हैं।

एफएंडओ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आम जुबान में इसे वायदा का सौदा भी कहा जाता है। वायदे दो तरह के होते हैं। एक, फ्यूचर्स यानी दो लोगों के बीच भविष्य की एक तय तारीख में एक तय भाव पर किसी शेयर के लेन-देन का सौदा। यहां से भाव गिरने पर बेचने वाले को फायदा होगा, क्योंकि उसने पहले ही ऊंचे भाव पर शेयर बेचने का सौदा कर लिया है। और बढ़ने पर खरीदने वाले को, क्योंकि वह पहले ही सस्ते में खरीद का सौदा कर चुका था। हो सकता है कि बेचने वाले के पास शेयर हों और हो सकता है कि न हों। ऐसे में, या तो वह बाजार से खरीदकर शेयर खरीदार को सौंपेगा या फिर दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ मुनाफे की रकम का लेन-देन हो जाए, न किसी को शेयर लेने पड़े, न किसी को देने। ज्यादातर मामलों में यही होता है।

वायदे की दूसरी शक्ल है, ऑप्शंस। इसका शाब्दिक अर्थ है, विकल्प। यहां भविष्य में शेयर का सौदा करने वाले दो लोगों में से एक के पास विकल्प रहता है कि वह उस तय तारीख को तय दाम पर सौदा करे या न करे। अगर उसे सौदा अपने फायदे का दिखता है, तो वह सौदा कर सकता है, और अगर उसे नुकसान होता दिखे, तो उसे पूरी छूट है कि वह सौदा करने से इनकार कर दे। वैसे, सामने वाले को भी इसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस विकल्प की कीमत चुकानी होती है, जिसे ऑप्शंस प्रीमियम कहा जाता है। सौदा कितना असलियत के नजदीक है, इसके आधार पर यह प्रीमियम तय होता है और यह प्रीमियम चुकाकर ही ऑप्शन खरीदा जाता है। दूसरी पार्टी के लिए फायदा यह है कि उसे शुरू में ही प्रीमियम मिल जाता है। अब अगर सौदा करने वाला सौदे से इनकार भी कर दे, तो उसकी यह रकम पक्की है। आप पूछ सकते हैं कि अगर इनकार नहीं हुआ और घाटे का सौदा करना ही पड़ा, तब तो नुकसान होगा। हो सकता है, मगर आम तौर पर विकल्प बेचने का काम बाजार के बड़े घाघ कर रहे होते हैं, जिनकी बाजार की नब्ज पर मजबूत पकड़ होती है।

साफ है, हमारे शेयर बाजारों में आने वाले नए छोटे खिलाड़ी या निवेशक इस काम में नुकसान उठाने के लिए अभिशप्त हैं। सेबी इसीलिए बार-बार और जोर-जोर से इस पर खतरे की घंटी बजाता रहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। पिछले ही हफ्ते सेबी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके नतीजे दिल दहलाने वाले हैं। जिस देश में पांच हजार करोड़ रुपये के घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वहां पिछले तीन कारोबारी सालों में एफएंडओ सौदों में छोटे कारोबारियों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। यह नुकसान एक करोड़ तेरह लाख इंडिविजुअल ट्रेडरों, यानी छोटे कारोबारियों को हुआ है। इसमें से 75,000 करोड़ रुपये की रकम तो सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 में डूबी है। इसमें सौदे के घाटे के साथ-साथ दलाली, यानी ब्रोकरेज और एक्सचेंज को दी गई फीस भी शामिल है। इन लोगों को होने वाले घाटे का औसत निकालने पर हरेक को औसतन दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले साढ़े तीन फीसदी ट्रेडरों को औसतन 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

वित्त वर्ष 2023-24 में छोटे ट्रेडरों को 61,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। दूसरी तरफ, एल्गो, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ट्रेडिंग करने वाले प्रोप्राइटरी ट्रेडरों, यानी ब्रोकरों या मोटे असामियों ने 33,000 करोड़ रुपये और विदेशी निवेशकों या एफपीआई ने 28,000 करोड़ रुपये की कमाई की। गणित एकदम साफ है। बाजार में किस्मत आजमाने उतरे आम आदमी की जेब से निकलकर पूरी रकम बड़ी मछलियों के खजाने में पहुंच गई। फिक्र की बात यह है कि नुकसान उठाने वाले इन ट्रेडरों में से 75 फीसदी की सालाना कमाई पांच लाख रुपये से कम है। और, उससे भी बड़ी चिंता इस रिपोर्ट में यह है कि बरसों से नुकसान उठाने के बाद भी तीन-चौथाई ट्रेडर बार-बार एफएंडओ में सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

इसी का नतीजा है कि इस साल मार्च में भारत में वायदा कारोबार का टर्नओवर 8,740 लाख करोड़ रुपये हो गया था। कैश यानी लेन-देन के सौदों के मुकाबले यह सौदा करीब चार गुना और डिलीवरी सौदों के मुकाबले 900 गुना हो चुका है। दुनिया के किसी भी बाजार में यह अनुपात इतना ज्यादा नहीं है। यही नहीं, दुनिया भर के वायदा कारोबार में भारत के सट्टेबाजों की हिस्सेदारी 81 फीसदी तक पहुंच गई है। असली बाजार के मुकाबले वायदा सौदे का इस हद पर पहुंचना एक चिंताजनक संकेत है।

उधर इन तीन वर्षों में सिर्फ 7.2 प्रतिशत ऐसे छोटे ट्रेडर फायदे का सौदा कर पाए हैं और उनमें से भी एक लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब लोग मात्र एक फीसदी हैं। ऐसे में, कहीं बाजार में तेज गिरावट आई, तो क्या होगा, यह समझना कठिन नहीं है।

आज की तारीख में भारत में बहुत बड़ी तादाद में लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंडों की तरफ खिंचे आ रहे हैं। मगर यह खतरनाक संकेत है कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले एफएंडओ सौदों में ज्यादा लोग आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि सेबी इस पर सतर्क है और चिंतित भी। आज सेबी की बोर्ड बैठक है, जिस पर पूरे बाजार की नजरें टिकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेबी का काम सिर्फ चेतावनी देना है? उम्मीद है, आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले सामने आएंगे, ताकि बेलगाम भाग रहे एफएंडओ के घोड़े पर नकेल कसी जा सकेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

संभावना से भरी पहाड़ी सड़कों पर आपदाओं की आशंका

यहां स्कैन करें

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली | पर्यावरण कार्यकर्ता

किसी भी देश-समाज में सड़कें विकास की निशानी होती हैं, मगर हमारे देश में पहाड़ की सड़कों को, कम से कम स्थानीय लोगों के परिप्रेक्ष्य में, आपदाओं की उत्प्रेरक के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों और उत्तराखंड के चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर के अनेक गांवों में गिरते शिलाखंडों, धंसती जमीनों और मलबों से लोग भयभीत हैं। इन जिलों के सौ से भी अधिक भयभीत गांवों के लोग अन्यत्र पुनर्वासित होने पर विचार करने लगे हैं। अपने कष्ट का कारण वे लोग गांव के ऊपर या नीचे से जाने वाली सड़कों को मानते हैं, विडंबना यह है कि वे इन सड़कों के करीब रहने के लोभ से बच भी नहीं पाते।

निस्संदेह, सड़कें बेहतर भविष्य की आस जगाती हैं और उनके बनने के बाद आस-पास की जमीनों के भाव भी बढ़ जाते हैं। मगर पहाड़ों में सड़कें जब चौड़ी की जाने लगती हैं, तो इसके लिए चट्टानों को ज्यादा गहराई तक काटना पड़ता है। विस्फोट से पहाड़ों के हिस्से उड़ाने पड़ते हैं। ऐसे में, सड़क संबंधी आपदाएं भी ज्यादा गहराने और पसरने लगती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जगह-जगह ऐसे बोर्ड लगे हैं, जिन पर लिखा है, सड़क के इन हिस्सों में रुकना खतरनाक है। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जब खड़े वाहनों या सड़क पर चलते लोगों के ऊपर पहाड़ से मलबा-पत्थर आ गिरा और लोग मारे गए।

पहाड़ों में पर्यटकों के फंसने के क्रम में ही प्रायः सड़कें खबर बनती हैं। उन सड़कों के कारण आने वाली आपदाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

पहाड़ों में तीर्थयात्रियों व पर्यटकों के फंसने के क्रम में ही प्रायः सड़कें खबर बनती हैं। उन सड़कों के कारण आने वाली आपदाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। विडंबना यह है कि सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के जो उपाय किए जाते हैं, उनसे भी कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर गहराई तक पहाड़ों को काटकर रास्तों को तत्काल साफ तो कर दिया जाता है, लेकिन इससे जो स्थिर ढालें अस्थिर हो जाती हैं, उनको स्थिर करने की आवश्यकता पर काम नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में भारी बोल्डर्स लुढ़कते रहते हैं। सड़कों के समीप बसे अधिकांश ग्रामीणों का यही कहना है कि सड़कों पर रोक दीवार अवश्य बनाई जानी चाहिए।

आखिर पहाड़ों में सड़क बनाने का उद्देश्य क्या है? वे यहां के निवासियों की जरूरतें पूरी कर रही हैं या फिर बढ़ा रही हैं? पहाड़ों में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं व चिंतकों को एक सवाल दशकों से बेचैन किए हुए है कि ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ों में अंतराल तक तो छोटे-बड़े मालवाहक वाहन भर-भरकर पहुंचते हैं, परंतु वहां से लौटते हुए अधिकांश खाली ही होते हैं? यह इस बात का भी संकेत है कि पहाड़ प्रमुखतः खरीदार है, विक्रेता नहीं। यह किसी भी क्षेत्र की अनुकूल आर्थिक दिशा नहीं हो सकती। पहाड़ों के संदर्भ में एक विडंबना यह भी है कि जरूरी नहीं, मोटर सड़कों से दूरियां कम हो गई हों। ऐसे अनेक उदाहरण आपको यहां मिल जाएंगे, जहां दो गांवों के बीच की पैदल दूरी आधा किलोमीटर है, किंतु मोटर सड़कों से सात किलोमीटर हो गई है। अब इन्हीं सड़कों के अवरोधन होने पर उन दूरियों को पैदल तय करने के बजाय घंटों सड़क खुलने का इंतजार करते लोग मिल सकते हैं।

सड़कों पर अति-विश्वास के कारण पहाड़ी किसानों व बागवानी करने वालों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी खबरों से स्थानीय अखबार भरे रहते हैं कि जब फल या खेती की अन्य नगदी फसलें तैयार हैं और उनको बेचने का समय है, तब ऐन उसी समय मोटर सड़कें कई-कई दिनों तक अवरुद्ध रहीं। प्रख्यात गांधीवादी व पर्यावरण कार्यकर्ता चण्डी प्रसाद भट्ट चमोली जिले में सड़कों के निर्माण के बाद भूस्खलन में बढ़ोतरी की बात तस्वीरों और आंकड़ों के जरिये बताते रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें कहां और कैसे बनाई जानी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ी सड़कें आधा कटान-आधा भरान की पद्धति से बननी चाहिए और नदी-नालों व खेतों में उनका मलबा बेतरतीब ढहा देने की जगह उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए, ताकि वे यहां के निवासियों के लिए मुसीबत न बनें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

देवी का दिव्य रूप

देवी शब्द दिव से बना है। दिव यानी प्रकाश, इसलिए जो प्रकाश से ओत-प्रोत है, वह देवी या देव है। यह कल्पना कहां से आई? भारत के मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने प्रकाश की ऊर्जा को अनुभव किया होगा। वह ऊर्जा-स्रोत देवी बन गया। आगम शास्त्र कहते हैं, सृष्टि के बनने से पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था, तब देवी थी : अकेली, आत्मनिर्भर; सृजन की ऊर्जा के रूप में। उसने अपनी ही छाया को देखा और उससे शिव को उत्पन्न किया। विज्ञान की कसौटी पर यह तर्कसंगत मालूम होता है, क्योंकि पहले सृजन का स्रोत होगा, बाद में चीजें उत्पन्न होंगी। शिव को देवी ने अपना पति बनाया। अतः देवी का एक नाम है 'स्वाधीनवल्लभा', यानी जिसका पति उसके अधीन है।

देवी वह ऊर्जा है, जो सर्व-प्राणियों के बीच बसती है, लेकिन एक गुणवत्ता की तरह। जहां-जहां कुछ भी उत्पत्ति हो रही है, वहां-वहां देवी का वास है। देवी स्तोत्र में यह बात सुंदरता से कही गई है कि देवी समूची सृष्टि के अंदर शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, लज्जा, बुद्धि, स्मृति, शांति, कांति, निद्रा, भ्रांति और माता के रूप में बसती है। मतलब ये सारे गुण आपके अंदर बस जाएं, तो आप देवी हो गए! उन गुणों को यदि हम अपने स्वभाव का अंग बनाते हैं, तो देवी की अलग से पूजा करने की क्या जरूरत?

आज जिस देवी को पूजा जाता है, उसकी मूर्ति फिल्मों से प्रभावित वेशभूषा में प्रस्तुत की जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि जरूरी नहीं है, देवी स्त्री रूप में ही हो। *देवी भागवत* में लिखा गया है कि देवी का ध्यान स्त्री रूप में या पुरुष रूप में भी कर सकते हैं या उसे अरूप में भी महसूस कर सकते हैं। प्रकाश ही जिसका अंग-प्रत्यंग है, उसका कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से देवी से संबंधित ये सारे गहरे आशय खो गए हैं। जैसे-जैसे आदमी की समझ संकीर्ण होती गई, देवी को उसने मानवीय स्त्री के रूप में ढाल दिया। जिस मात्रा में मनुष्य भौतिकवादी होता गया, कामिनी और कंचन के पीछे भागने लगा, उसी मात्रा में स्त्री का शरीर महत्वपूर्ण होता गया। और इधर देवी का दिव्य रूप खो गया।

अगर देवी की भक्ति करनी है, तो सबसे पहले यह देखें कि नौ दिन तक हम देवी-प्रतिमा के साथ क्या करते हैं। सबसे बड़ी नासमझी यह है कि देवताओं से हम हमेशा मांगते रहते हैं : यह कामना पूरी करो, यह वासना पूरी करो। क्या परमात्मा का और हमारा इतना ही संबंध है? जब हम कुछ मांगते हैं, तो मांगों का एक थुआं सा खड़ा होता है, हमारे और उसके बीच। फिर हम उससे प्रेम कब करेंगे? क्या यह मनुष्य की गरिमा के खिलाफ नहीं है? अजीब बात है, मनुष्य खुद देवी की मूर्ति को बनाता है और फिर वही उसके सामने मांगने खड़ा हो जाता है। यह खेल जब बंद होगा, तभी नवरात्रि होगी।

देवी समूची सृष्टि के अंदर शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, लज्जा, बुद्धि, स्मृति, शांति, कांति, निद्रा, भ्रांति और माता के रूप में बसती है। मतलब ये सारे गुण आपके अंदर बस जाएं, तो आप देवी हो गए!

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों को मेरा यही पैगाम है कि आइए, हम अपनी दुनिया को अधिक जवाबदेह बनाएं। इसमें असमानता कम से कम हो और न्याय अधिकतम। अनिश्चितता कम और अवसर अधिक हों।

अनुवाद कहीं से भी मौलिक काम नहीं

'अनुवाद' शब्द संस्कृत के 'वद्' धातु से बना है। 'वद्' का अर्थ है बोलना। इसमें 'अनु' उपसर्ग जोड़कर 'अनुवाद' शब्द बना, जिसका अर्थ है- प्राप्त कथन को पुनः कहना। मगर अंग्रेजी शब्द 'ट्रांसलेशन' लैटिन भाषा के शब्दों 'ट्रांस' (पार करना) और 'लैटस' (ले जाना) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, एक भाषा में प्रस्तुत की गई सामग्री को दूसरी भाषा में पुनः पेश करना। साफ है, अनुवाद मौलिक कार्य नहीं है, चूंकि अनुवाद एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों और संदेशों को दूसरी भाषा में सटीकता से प्रस्तुत करता है और इस कार्य में अनुवादक की व्यक्तिगत रचनात्मकता व भाषायी कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए कुछ विद्वान इसे मौलिक कार्य मान लेते हैं।

यह ठीक है कि अनुवाद-कार्य में अनुवादक की भाषा पर पकड़, सांस्कृतिक समझ और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, ताकि अनुवाद सटीक और प्रभावशाली हो। मगर इस काम में मौलिकता की वह परिभाषा लागू नहीं होती, जो पूरी तरह नए सृजन से संबंधित होती है। तकनीकी दृष्टि से अनुवाद को मौलिक कार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें विचार, भाव या संदेश पहले से ही किसी और के द्वारा रचे-कहे गए होते हैं। अनुवादक नई सामग्री का निर्माण नहीं करता, बल्कि पहले से मौजूद सामग्री को एक भाषा से दूसरी में बस परिवर्तित करता है। कानूनी अर्थों में भी अनुवाद को व्युत्पन्न कार्य ही माना जाता है, इसीलिए कॉपीराइट कानून अनुवाद को मौलिक कार्य का दर्जा नहीं देते हैं।

विधि, प्रशासन, वाणिज्य, विधायिका जैसे कई क्षेत्रों में अनुवाद में जरा सी स्वतंत्रता (मौलिकता) अर्थ का अनर्थ कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द परिभाषित होता है और उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शब्द 'चेयरपर्सन' के लिए हिंदी में अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभापति जैसे तमाम शब्द हैं, लेकिन विधायिका में इसका एक ही अर्थ है- राज्यसभा के सभापति, यानी उप-राष्ट्रपति। इसी तरह 'अध्यक्ष' शब्द लोकसभा स्पीकर के लिए रूढ़ है। अगर अनुवाद इतना ही मौलिक होता, तो बाबू देवकीनंदन खत्री के कालजयी उपन्यास *चंद्रकांता संतति* को पढ़ने के लिए लोग हिंदी नहीं सीखते, क्योंकि इस उपन्यास के अनुवाद कई भाषाओं में उपलब्ध रहे हैं। असल में, जो रस मौलिकता में है, वह अनुवाद में नहीं। संभवतः इसीलिए नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर भी मानते थे कि अनुवाद करने से मूल कृति का मर्म नष्ट हो जाता है। जाहिर है, अनुवाद कभी मौलिक नहीं होता, बल्कि मौलिक का भाषांतरण होता है।

विनय सिंह बैस, अनुवाद अधिकारी

अनुलोम-विलोम
अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस

यहां मूल लेखन से भी ज्यादा मौलिकता

अनुवाद किसी भी मामले में कमतर काम नहीं। कई मायनों में तो मौलिक से भी ज्यादा श्रमसाध्य है। मूल लेखन में अगर आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्द नहीं मिल रहे, तो आप अन्य भाषा के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्यों में बदलाव भी कर सकते हैं। मगर अनुवादक को यह छूट नहीं मिलती। उसे मूल लेखन जैसा भाव ढूंढ़कर लाना ही पड़ता है। हालांकि, एक हद तक इससे अनुवादक की शब्द-संपदा में इजाफा होता है और वह अधिक समृद्ध बनता है, क्योंकि उसे मूल लेखन के शब्द ढूंढ़ने पड़ते हैं। मगर इससे अनुवाद के लिए उसे कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ता है। असल में, अनुवाद दो देश, दो अलग-अलग समाज, दो अलग-अलग संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है। इसके लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान और सृजनशीलता बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सृजनशील नहीं है, वह अच्छा अनुवादक कभी नहीं हो सकता। कभी-कभी तो लेखक से कहीं अधिक सृजनशीलता की उम्मीद अनुवादक से की जाती है। इन्हीं सबको देखकर यह कहा जाता है कि अनुवाद मूल से कहीं अधिक मौलिक कर्म है। यह करते वक्त अनुवादक को लेखक की तरह छूट नहीं मिलती।

सोनी कुमारी, टिप्पणीकार

गुणवत्ता के मामले में भी बेहतर

अनुवाद के अच्छे या बुरे होने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां प्रचलित हैं। आरोप लगाया जाता है कि मूल की तुलना में अनुवाद अपूर्ण रहता है, अनुवाद में मूल के सौंदर्य की रक्षा नहीं हो पाती, अनुवाद दोयम दरजे का काम है आदि। अनुवाद-कर्म पर लगाए जाने वाले ये आरोप मुख्य रूप से अनुवादक की अयोग्यता के कारण हैं। अनुवाद में मूल भाव-सौंदर्य और विचार-सौष्ठव की रक्षा तो हो सकती है, पर भाषा-सौंदर्य की रक्षा इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि भाषाओं में रूप-रचना और प्रयोग की रूढ़ियों की दृष्टि से भिन्नता होती है। इसलिए मूल-भाषा जैसी स्वाभाविकता या मधुरता अनुवाद में नहीं आ पाती। असल में, मौलिक लेखन के बाद ही अनुवाद होता है, इसलिए बेशक वह क्रम की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, पर इसका यह मतलब नहीं कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी वह दूसरे स्थान पर है। जिस प्रकार मौलिक लेखन बढ़िया हो सकता है और घटिया भी, उसी प्रकार अनुवाद भी घटिया-बढ़िया हो सकता है। उक्त आरोपों से अनुवाद-कार्य का महत्व कम नहीं होता। मेरा मानना है, एक अच्छे अनुवादक के लिए अच्छा लेखक होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा लेखक होना उसे एक अच्छा अनुवादक बनाता है और सौभाग्य से अच्छा अनुवादक होना उसे एक अच्छा लेखक भी बनाता है।

शिवान कृष्ण रैणा, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 193

आगे बढ़ने का वक्त

दूरसंचार उद्योग एक बार फिर केंद्र सरकार से राहत की अपेक्षा कर रहा है। वह समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित अपने बकाये के मामले में राहत चाहता है क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक उपचारात्मक याचिका खारिज कर दी है। अब दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आगे बढ़ते हुए अपने बूते मजबूत भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। यह एक तथ्य है कि दूरसंचार उद्योग को हालिया अतीत में उल्लेखनीय उथलपुथल का सामना करना पड़ा है और बकाया एजीआर के मामले में राहत मिलने से इन दूरसंचार कंपनियों को 4जी और 5जी सेवाओं में निवेश करने तथा उनकी नेटवर्क क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। परंतु यह बात भी सही है कि हर उद्योग उतार-चढ़ाव से गुजरता है और सरकार हर समय शुल्क और प्रभारों में कमी करके दखल देने को बाध्य नहीं है। भले ही कंपनियों को बचे रहने के लिए उसके हस्तक्षेप की जरूरत हो।

दूरसंचार कंपनियों की बात करें तो वित्तीय मुश्किलों से दो-चार वोडाफोन आइडिया का बकाया एजीआर 70,000 करोड़ रुपये से अधिक है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले का सबसे अधिक असर देखना होगा। कंपनी की बैलेंस शीट की हालत खराब है और उसकी देनदारियां 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी हैं। इसके बावजूद यह याद रखना जरूरी है कि दूरसंचार कंपनियां खासकर वोडाफोन को हालिया अतीत में सरकार और अदालती निर्णयों से फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए दूरसंचार कंपनियों को दो कंपनियों के दबदबे की स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने दो साल पहले वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी ली थी और कंपनी की ब्याज देनदारी को शेयरों में तब्दील किया था। 2022 में सरकार 33 फीसदी के साथ वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार थी और कंपनी के फॉलोऑन पब्लिक ऑफर के बाद उसने अपनी हिस्सेदारी कम की थी। अगस्त 2024 में सरकार के पास कंपनी के 23.1 फीसदी शेयर थे। इस उद्योग को राहत का एक और उदाहरण यह है कि उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा 2020 में की गई मांग के बाद उन्हें बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया था। इन पहलों के अलावा दूरसंचार उद्योग को 2021 में भी सरकार से राहत पैकेज मिला था। इसमें सांविधिक बकाये के भुगतान पर चार साल का स्थगन शामिल था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में जो याचिका खारिज की है वह वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज समेत दूरसंचार कंपनियों ने 2019 के एक फैसले के विरुद्ध दायर की थी जो एजीआर बकाये के भुगतान से संबंधित था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों के पीठ ने सरकार के आकलन के तरीके को सही ठहराते हुए राशि की पुनर्गणना के सरकार के कंपनियों के आग्रह को ठुकरा दिया था। कंपनियों की दलील थी कि बकाये के लिए सरकार का आकलन खामियों भरा है और इस पर दोबारा नजर डालने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के अनुसार वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल का बकाया एजीआर 1.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था।

उपचारात्मक याचिका के रूप में झटका लगने के बाद वोडाफोन आइडिया प्रबंधन ने निवेशकों और विश्लेषकों से बातचीत में कहा कि यह सरकार के ऊपर है कि वह बकाये के गलत आकलन के मुद्दे को हल करती है या नहीं। एजीआर के आकलन में सुधार से भी कंपनियों को मदद मिल सकती है लेकिन उन्हें अपनी कारोबारी योजना सरकार से कोई मदद मिलने की उम्मीद के बिना तय करनी चाहिए। उद्योग जगत को भविष्य में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे प्रति उपयोगकर्ता बेहतर औसत राजस्व हासिल हो सकेगा। ऐसा करने से यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि दूरसंचार क्षेत्र में केवल दो कंपनियों का दबदबा नहीं रह जाए और वह पूरी तरह जीवंत कारोबारी क्षेत्र बना रहे।

सेना और आस्था के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था

इंडोनेशिया, मलेशिया व तुर्किये इस्लाम और श्रीलंका बौद्ध मत के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और स्थिर बने हुए हैं लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ऐसा नहीं है।

अगर आप वादा करें कि जवाब तलाशने में गूगल की मदद नहीं लेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में आपने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अलावा और कौन सा नाम सुना है? पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महा सभा से इतर अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम पश्चिमी देशों के उदारवादी नेताओं ने यूनुस की सराहना की।

अब दूसरा सवाल। ऐसा क्यों है कि उपमहाद्वीप के अन्य पड़ोसी देशों में लोकतंत्र इतना कमजोर रहा है? इसका स्वतः स्फूर्त जवाब होगा- इस्लाम। कहा जाएगा कि इस्लाम और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। हालांकि आज के माहौल में इसी जवाब की उम्मीद की जा सकती है लेकिन यह तथ्यों की जांच में सही साबित नहीं होता।

सुदूर पूर्व की ओर देखें तो इंडोनेशिया में ही यह दलील विफल हो जाती है जो दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। मलेशिया में भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी परिवर्तन हुए, भले ही चुनावों में महातिर मोहम्मद को चुना गया। पश्चिम की ओर देखें तो तुर्किये में रेचेप तैय्यप एर्दोआन उदार लोकतांत्रिक नेता नहीं हैं। उन्हें महातिर का कई गुना बड़ा संस्करण ही माना जा सकता है। परंतु उन्हें भी चुनावों का सामना करना पड़ता है और हमने कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र कमियों से रहित होता है। इंडोनेशिया और तुर्किये आबादी के मिश्रण के हिसाब से उतने ही इस्लामिक हैं जितने कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। इससे यह विचार ध्वस्त हो जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह स्थिति इसलिए है कि इस्लाम और लोकतंत्र में तालमेल नहीं है।

मैं बात करता हूं एक और देश म्यांमार की। वहां इस्लाम नहीं है। अगर वहां कुछ हुआ है तो यह कि अधिकांश मुस्लिम आबादी यानी रोहिंग्या का दमन किया है और उन्हें निकाल बाहर किया है। वह पूरी तरह बौद्ध देश है। वहां ज्यादातर तानाशाहों का शासन रहा है और मिलिट्री जुंटा यानी सैन्य शासन है। फरवरी 2021 में उन्होंने एक दृढ़ तक लोकतांत्रिक मानी जाने वाली और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को भी गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार में लोकतंत्र नहीं होने के लिए इस्लाम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तब किसे दोषी ठहराया जाए, बौद्ध मत को?

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

परंतु हम अपने पड़ोस पर नजर रखते हुए इस तर्क को भी खारिज कर सकते हैं। श्रीलंका मुख्य रूप से बौद्ध बहुल देश है। परंतु उसका धार्मिक समुदाय प्रायः हिंसक, नस्लवादी और कम उदारवादी रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में हम यह भूल गए हैं कि जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) के मूल आतंकी अवतार के दौरान श्रीलंका में क्या हुआ। इसी पार्टी के नेता अब नए नाम के साये में सत्ता में आए हैं। हिंसक दौर में बौद्ध भिक्षुओं ने न केवल संप्रदाय आधारित और निशाना बनाकर की गई हत्याओं को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। ऐसे में यह विचार भी सही नहीं है कि लोकतंत्र के लिए बौद्ध धर्म अच्छा है लेकिन इस्लाम बुरा। इस्लाम या किसी अन्य आस्था से इतर इस्लाम के लिए कुछ और चीजें हैं जो बुरी हैं।

यहां मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा: बांग्लादेश में बदलाव के बाद आपने यूनुस के अलावा कौन सा नाम सबसे अधिक सुना? वह नाम है जनरल वकार उज्जमां। उन्हें हसीना ने निर्वासित होने से कुछ सप्ताह पहले यानी 23 जून को सेना प्रमुख बनाया था।

उन्होंने इस सप्ताह के आरंभ में रॉयटर्स से बातचीत में हमें वह बताया जो यूनुस ने नहीं बताया यानी अगले चुनाव की समय-सीमा और वह अवधि जब नया अंतरिम प्रशासन सत्ता संभाल लेगा। यह अवधि 12 से 18 महीने की है। याद रहे कि वर्तमान व्यवस्था अनिर्वाचित है और वह बिना संविधान के शासन कर रही है। इसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके पास कोई राजनीतिक या कार्यपालिक पद नहीं है। यूनुस को मुख्य सलाहकार कहा जा रहा है। कम से कम हाल फिलहाल में तो यह नहीं सुना गया कि 17 करोड़ की आबादी वाला कोई देश मुख्य सलाहकार द्वारा चलाया जा रहा हो।

जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने के बाद यह कोशिश की थी खुद को राष्ट्रपति कहलाने से बचने के लिए उन्होंने 'मुख्य कार्यकारी' का पदनाम चुना था। वह पद भी कम से कम मुख्य सलाहकार से तो ठीक ही था। हालांकि वह ज्यादा समय तक सैन्य वर्दी में नहीं रहे। आगरा शिखर बैठक के बहाने उन्होंने खुद को राष्ट्रपति बना लिया। आखिर कोई मुख्य कार्यकारी भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में पाकिस्तान का प्रतिनिधि कैसे हो सकता था।

मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि यूनुस भी अपना पद बदल लेंगे या फिर यह जनरल सत्ता हथिया लेंगे। अब सैन्य अधिकारियों के लिए सत्ता संभालना बहुत असहज करने वाला बन चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन्होंने यह दिखाया है कि पर्दे के पीछे से कैसे नेतृत्व किया जाता है।

अब तक तो जनरल जमां आश्वस्त करने वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने रॉयटर्स के देवज्योत घोषाल और रूमा पाल से कहा, 'मैं हर हाल में यूनुस के पीछे खड़ा रहूंगा। ताकि वे अपना मिशन पूरा कर सकें।' उन्होंने न्यायपालिका, पुलिस और वित्तीय संस्थानों में जरूरी सुधार का वादा किया ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। उन्होंने कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि 12 से 18 महीने की समय सीमा होनी चाहिए। इस अवधि में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रवेश कर लेना चाहिए।' उनकी कही बातें महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि वे सब कौन कह रहा है?

अब हम वापस शुरुआत की बात करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किये और श्रीलंका क्रमशः इस्लाम और बौद्ध धर्म के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और स्थिर कैसे बने रहे जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार नहीं बने रह सके? किसी देश में लोकतंत्र को खतरा केवल आस्था से नहीं होता है बल्कि आस्था और सेना का मेल खतरा पैदा करता है। अगर सेना को एक ऐसे संस्थान के रूप में महत्ता दी जाएगी जिसका सम्मान होना चाहिए और धर्म उसे पवित्र बनाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे नतीजे होंगे। अगर सेना की मंजूरी नहीं होती तो ढाका में यह बदलाव नहीं होता। जब तक सेना हां न कहे वहां संविधान और चुनाव के जरिये लोकतांत्रिक व्यवस्था की वापसी नहीं होगी। इस माह के आरंभ में बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। यह एक दुर्लभ अवसर था। ढाका नैशनल प्रेस क्लब में आयोजित इस समारोह में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त भी शामिल हुए। वक्ताओं ने बताया कि क्यों बांग्लादेश में जिन्ना को याद किया जाना चाहिए। अगर उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं दिया होता तो बांग्लादेश कैसे बनता?

बीते तमाम दशकों में दलील यह रहती आई है कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने अलग होकर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को ही ध्वस्त कर दिया। अब जिन्ना को नए ढंग से स्थापित किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर धर्म आपकी राष्ट्रीय विचारधारा के इतना करीब है और सेना को सीमाओं की रक्षा करने वाला इकलौता संस्थान माना जा रहा है तो संविधान का दर्जा खुद कमजोर हो जाता है। म्यांमार में बौद्ध सेना की अतियों को वैधता दे रहे हैं।

1971 के बाद अब तक के 53 साल के इतिहास में बांग्लादेश ने उतनी ही नई संवैधानिक व्यवस्थाएं और सैन्य शासक देख लिए जितने कि पाकिस्तान ने। सैन्य-असैन्य सभी सरकारों ने संविधान से छेड़खानी की। अब सड़कों पर चुनी गई अनौपचारिक शासन व्यवस्था नया संविधान बनाएगी। चुनौतियां सभी लोकतंत्रों के सामने आती हैं। भारत में भी ऐसा हुआ जब आपातकाल में इंदिरा गांधी ने लगभग संविधान का पुनर्लेखन कर दिया। परंतु जब उनके उत्तराधिकारियों ने खराब बदलावों को हटाया तो इंदिरा की पार्टी ने उनका साथ दिया। आज भारत को समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बताने वाली प्रस्तावना को प्रगतिशील माना जाएगा। यह इसलिए हो सका क्योंकि किसी धार्मिक शक्ति ने इन बदलावों को वैधता नहीं दी और न ही किसी सेना ने इसका समर्थन किया।

यही वजह है कि मेरे पीछे आप भी दोहरा सकते हैं: अपने आप में कोई धर्म लोकतंत्र का शत्रु नहीं है। जब हम धर्म को अपने राष्ट्रीय विचार के केंद्र में रखते हैं और सेना को अपनी शक्ति के केंद्र में, तब समस्या पैदा हो सकती है।

जीएसटी ऑडिट क्षमता में सुधार की दरकार

उम्मीद थी कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर से मिलने वाला राजस्व बढ़ता ही जाएगा। यह उम्मीद दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, जीएसटी की संरचना कुछ इस प्रकार तैयार की गई है कि कच्चे माल से लेकर खुदरा कारोबार तक सभी इसके दायरे में आ गए हैं। इसके कारण कराधान के स्रोत बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा सिद्धांत यह था कि जीएसटी के तहत कर अनुपालन बढ़ेगा क्योंकि इसके प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए खरीदार स्वयं ही विक्रेताओं से सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहेंगे और विक्रेताओं की ऐसा करने की आदत पड़ जाएगी।

जीएसटी दरों को औचित्यपूर्ण बनाने पर चर्चा चल रही है। हाल में संपन्न जीएसटी परिषद की बैठक में भी इसका जिक्र हुआ है। बैठक में 14.8 प्रतिशत की राजस्व तटस्थ दर बहाल करने पर चर्चा हुई, जो जीएसटी लागू होने से पहले थी। अब इसे 12.2 प्रतिशत कर दिया गया है। मगर बैठक में नियमों का अनुपालन पक्का करने के लिए आवश्यक हुनर विकसित करने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि राज्य वाणिज्यिक कर विभाग में अधिकारियों में ऑडिट की अधिक क्षमता विकसित करना आवश्यक है। केंद्र के कर विभाग में इस लिहाज से अच्छी स्थिति है क्योंकि 1996 से 2006 के बीच सरकार ने कनाडा सरकार के साथ मिलकर नई तरह की ऑडिट परियोजना शुरू की थी। इससे ऑडिट क्षमता सुधारने में काफी मदद मिली और इससे मानक प्रशिक्षण एवं ऑडिट नियमावली (मैनुअल) तैयार करने की शुरुआत हो गई। हाल में केरल में संपन्न ऑडिट प्रशिक्षण परियोजना से मिले अनुभव बताते हैं कि प्रशिक्षण में सिखाई बातें सही ढंग से अमल में लाई जाएं तो राज्यों का राजस्व नुकसान काफी कम हो सकता है। एक महत्त्वपूर्ण सीख यह मिली कि पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जाना चाहिए ताकि उनकी प्रतिक्रिया एवं जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। ऑडिट प्रशिक्षण परियोजना शुरू करने से पहले जरूरतों का विस्तार से आकलन करना बहुत जरूरी है।

वीएस कृष्णन

नियमित कर रिटर्न सत्यापन की तुलना में ऑडिट प्रणाली अधिक फायदेमंद होती है मगर इसके लिए कौशल भी अधिक चाहिए। ऑडिट प्रशिक्षण परियोजना के लिए तीन हुनर - जीएसटी कानून की जानकारी, वित्तीय खातों की जानकारी और जिस क्षेत्र का ऑडिट होना है, उसकी पर्याप्त जानकारी - का समावेश करना होगा। सबसे पहले विभाग से कामकाजी जानकारी एवं हुनर के आधार पर कुछ लोगों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। उसके बाद ये लोग दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्य में बाहरी प्रशिक्षक भी मदद करेंगे।

ऑडिट काफी फायदेमंद है क्योंकि यह मानक विधि पर काम करता है। यह विधि वैज्ञानिक है और हर जगह स्वीकार्य होती है। यह सात चरणों पर आधारित है। पहले चरण में जोखिम मानकों के आधार पर इकाइयों का चयन, दूसरे चरण में जुटाई गई जानकारी की समीक्षा (डेस्क रिव्यू), तीसरे चरण में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन, चौथे चरण में ऑडिट योजना की तैयारी, पांचवें चरण में योजना के अनुरूप ऑडिट करना, ऑडिट के बिंदुओं का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी समिति की बैठक और सातवें चरण में ऑडिट के पश्चात होने वाली निगरानी शामिल है। यह प्रणाली पारदर्शी है क्योंकि इसमें ऑडिट प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हुए कामकाज का पूरा ब्योरा रखा जाता है। कामकाज और सत्यापन के ये पत्र विभाग का ज्ञान भंडार (नॉलेज रिपॉजिटरी) बन गए हैं। केंद्र का अनुभव बताता है कि मासिक निगरानी समिति जैसी संस्थाएं तैयार करने की जरूरत है। इनमें वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ऑडिटर मामूली मसले नहीं उठाएं और समिति पेचीदा मसलों को ही आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार करे।

इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि प्रत्येक राज्य के लिए ऑडिट कार्यक्रम उस राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर तैयार किए जाएं। छोटी इकाइयों का ऑडिट करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा कि उन्हें परेशानी नहीं हो। इसके लिए उनके परिसरों में जाने के बजाय उनके बारे में जुटाई गई जानकारी की समीक्षा करना बेहतर रहेगा। जीएसटी में 'जी' और 'एस' के लिए सूक्ष्म ऑडिट कार्यक्रम की जरूरत है क्योंकि 'जी' का अर्थ वस्तु है, जो हमारे हाथ में होती है। 'एस' सेवा होती है, जो अमूर्त होती है। इसके अलावा बड़ी इकाइयों की ऑडिट के लिए कंप्यूटर की मदद से चलने वाले ऑडिट कार्यक्रम (सीएएपी) की जरूरत है क्योंकि इनसे जुड़े आंकड़े अधिक होते हैं और उन्हें समझना भी थोड़ा जटिल होता है।

क्षमता प्रशिक्षण की कई परियोजनाएं अधिक कारगर साबित नहीं होती हैं क्योंकि अधिकारियों के पास सभी विधि, लेखा (अकाउंटिंग) और बेहतर संवाद क्षमता के साथ क्षेत्र विशेष का ज्ञान जैसे सभी जरूरी कौशल नहीं होते। दरों पर चर्चा एवं कानूनों को सरल बनाने का अधिकार जीएसटी परिषद के पास जरूर है मगर राज्यों के साथ मिलकर वाणिज्यिक कर विभागों के अधिकारियों को हुनरमंद बनाने पर केंद्र सरकार को ही ध्यान देना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच इस साझेदारी में इकाइयों के ऑडिट के समय आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा सकता है।

चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि कर संग्रह का काम उसी तरह होना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद निकालती है और फूल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। मगर करदाताओं की यह शिकायत आम है कि सरकार कर जुटाने में असहज तरीकों का इस्तेमाल करती है। पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों वाली मजबूत ऑडिट प्रणाली करदाताओं को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक राजस्व जुटाने में सरकार की मदद कर सकती है।

(लेखक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

अपने दिल की देखभाल करें

रविवार 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है। मगर अफसोस की बात है कि आज हमने आधुनिकता और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में हमने सच्चे धन की परवाह करना ही छोड़ दिया है, इस कारण आज दुनिया में जानलेवा बीमारियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्ष 2000 में दुनियाभर में लगभग 1.4 करोड़ लोगों की मौत हृदयाघात के कारण हुई और साल 2019 में यह संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ पहुंच गई। विकसित राष्ट्र अमेरिका में भी हर एक मिनट में 2 लोगों की जान हृदयाघात से चली जाती है। हमारा देश भी इसमें शामिल हो चुका है। चिकित्सकों के मुताबिक हमारे शरीर के सभी अंग महत्त्वपूर्ण हैं मगर दिल का तंदुरुस्त रहना तो सबसे जरूरी है। दुनिया में बढ़ते दिल की बीमारी के मरीजों की संख्या पर चिंता करते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) हृदय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और इस सन् 2000 में इस दिवस को मनाने का एलान किया था। पहले इसे सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन एक दशक पहले इसकी तारीख बदलकर 29 सितंबर कर दी गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करना है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर दिल की बीमारियों से बचना है तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने खानपान और जीवनशैली पर ध्यान देना होगा, चिंता से बचना होगा, प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, साफ सफाई का ख्याल रखना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

हैदराबाद में विश्व हृदय दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा में भाग लेते लोग

भारत का प्रबल समर्थक बनकर उभर रहा है अमेरिका

हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में, समुद्री क्षेत्र चीन के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है, जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरता है। ऐसे में, सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। इसके अलावा भारत, मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव या समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों को बुनियादी ढांचा सहायता एवं संपर्क के लिए पहल तथा इसी तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। क्वाड, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है तथा इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। दूसरी ओर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संबंध में अमेरिका ने चीन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के बजाय क्षेत्र में सभी हितधारकों को साथ लाने की भारतीय नीति का समर्थन किया है, जो इस क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण से एक बड़ी सफलता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्त्व को दर्शाता है। इसके साथ ही 'ब्लू डॉट नेटवर्क' जैसे प्रयासों से भारत को इस क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

न्यूयॉर्क में अल्जीरिया के विदेश मंत्री अहमद अत्ताफ (दाएं) के साथ बैठक करते केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर।

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

शांति बल प्रयोग के जरिये नहीं, बल्कि आपसी समझ से ही कायम रखी जा सकती है। -अल्बर्ट आइंस्टीन

हिजबुल्ला के प्रमुख सैयद हसन नसरल्ला की इस्राइल के घातक हमले में हुई मौत से ईरान, उसके सहयोगी देशों व हमास जैसे अन्य आतंकी संगठनों को भी गंभीर झटका लगा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशिया में स्थितियां किस तरफ करवट बदलती हैं।

नसरल्ला की मौत

लेबनान पर इस्राइली हमले तो सितंबर के मध्य से ही हो रहे थे, लेकिन 27 सितंबर की शाम राजधानी बेरूत के घनी आबादी वाले दक्षिणी हिस्से में स्थित हिजबुल्ला मुख्यालय में हुए हमले में हिजबुल्ला प्रमुख सैयद हसन नसरल्ला की मौत ने पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया में स्थितियों को और जटिल तो बनाया ही है, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम के प्रयासों को लेकर उम्मीदें भी कम हुई हैं। इससे ईरान, उसके सहयोगी देशों व हमास जैसे अन्य आतंकी संगठनों को भी गंभीर झटका लगा है। दरअसल, ईरान के संरक्षण में पनपे आतंकी संगठनों, लेबनान में हिजबुल्ला व फलस्तीन में हमास ने न केवल अपने क्षेत्रों में अशांति फैलाई, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आतंकवादी हमलों और चरमपंथी गतिविधियों के जरिये अस्थिरता का माहौल तैयार किया। इन आतंकी समूहों की कार्रवाईयां लाखों निर्दोषों की जान ले चुकी हैं और इनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि अब जो कुछ भी हो रहा है, उसकी शुरुआत पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा इस्राइल पर किए गए खौफनाक हमले से ही हुई थी। उल्लेखनीय है कि हिजबुल्ला के नेतृत्व की डोर 1992 में नसरल्ला के हाथों में आ गई, तब उसकी उम्र सिर्फ बत्तीस वर्ष थी। लेकिन, इसके बाद तीन दशकों के भीतर ही नसरल्ला ने इस शिया संगठन को विश्व का सबसे शक्तिशाली सशस्त्र गुट बना दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अगर इस्राइली सेना दक्षिणी लेबनान पर कब्जे से पीछे हटने को विवश हुई थी, तो इसके पीछे नसरल्ला का ही दिमाग था। पिछले कुछ समय में इस्राइल ने हमास, हिजबुल्ला और ईरान के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया है। हाल ही में पेजर विस्फोट प्रकरण में भी बड़ी तादाद में हिजबुल्ला के सदस्यों पर हमला किया गया था। महज दो महीने के भीतर इस्राइल ने जिस तरह से हिजबुल्ला का पूरा नेतृत्व खत्म-सा कर दिया है, उससे उसका संरक्षक ईरान भी दबाव में आया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए नसरल्ला की मौत ऐसे समय में मनोबल बढ़ाने वाली है, जब उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन नसरल्ला की मौत के निहितार्थ हिजबुल्ला से कहीं आगे तक जाते हैं। लिहाजा इस्राइल की यह जीत महत्वपूर्ण होने के बावजूद जोखिम से भरी है। इस्राइल ने जहां हमले जारी रखने की बात कही है, वहीं ईरान, हिजबुल्ला व हमास इस्राइल से हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में, देखने वाली बात होगी कि इससे आने वाले समय में बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशिया में स्थितियां किस तरफ करवट बदलती हैं।

हिजबुल्ला हर किसी के लिए समस्या है

पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हमलों के जरिये इस्राइल ने हिजबुल्ला के नेतृत्व को लगभग ध्वस्त ही कर दिया है। पर इस्राइल को लेबनान के लोगों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। सर्वेक्षण बताते हैं कि अपने शिया गढ़ों को छोड़कर हिजबुल्ला अपनी हरकतों के चलते ज्यादातर लेबनानियों के बीच भी अलोकप्रिय है।

बेट स्टीफेंस
द न्यूयॉर्क टाइम्स

वर्ष 2006 में हिजबुल्ला ने इस्राइल में गुरिल्ला हमले शुरू किए थे। इसकी वजह से 34 दिन तक चले युद्ध में लेबनान तबाह हुआ, तो इस्राइल को भी इससे नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर युद्ध विराम हुआ, जिसका मकसद आतंकी गुट को निशस्त्र करना और इसकी सेनाओं को इस्राइली सीमा से दूर रखना था। हालांकि उस प्रस्ताव का खास असर नहीं हुआ। इसके उलट, तेहरान में बैठे हिजबुल्ला के संरक्षकों की अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं ने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां आज हम हैं। दक्षिण बेरूत में हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हुए इस्राइली हमले में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला के ढेर होने से हम एक संघर्ष के शिखर पर पहुंच गए हैं, जिसके आगे गाजा की लड़ाई भी बौनी साबित हो सकती है। क्या पूर्ण युद्ध से बचा जा सकता है? कहना मुश्किल है। लेकिन क्या 2006 के अनुभवों से सबक लेते हुए कुछ बेहतर नतीजों की ओर बढ़ा जा सकता है? यह महत्वपूर्ण सवाल है।

पहला सबक : सामरिक प्रतिभा ठोस रणनीति का विकल्प नहीं है। वर्ष 2006 में इस्राइल की काबिल वायु सेना युद्ध की दूसरी रात ही खेल को पलट सकती थी। दरअसल, वह हिजबुल्ला के लंबी दूरी के रॉकेट को खत्म करने में सक्षम थी, जो अक्सर घरों में छिपा कर रखे जाते थे। इस स्ट्राइक से निश्चित रूप से सैकड़ों तो नहीं, लेकिन कई इस्राइली लोगों की जान बचाने में मदद मिलती। लेकिन इस्राइल को इसका अंदाजा बहुत कम था कि उसे युद्ध को कैसे आगे लेकर जाना है, सिवाय बमबारी के, जिसकी तीव्रता ने सिर्फ युद्ध रोकने के लिए ही कूटनीतिक दबाव बनाया। इसके अलावा, इस्राइल द्वारा देर से शुरू किए गए जमीन अभियान को हिजबुल्ला ने बुरी तरह कुचल दिया। क्या इस्राइल के पास आज कोई बेहतर योजना है?

दूसरा सबक : हिजबुल्ला इस्राइल का मुख्य शत्रु नहीं, बल्कि ईरान है। पूर्व इस्राइली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तेहरान ऑक्टोपस का सिर, तो हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोहियों की तरह इसका केवल एक हाथ है। जाहिर है कि हिजबुल्ला के साथ द्वितीयक स्तर पर युद्ध कर इस्राइल खुद को थकाने का जोखिम उठा रहा है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं कि इस्राइल हिजबुल्ला को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि इसकी करीब दो लाख मिसाइलें सीधे इस्राइल पर ही तनी हैं। लेकिन इस्राइल को अपनी ताकत को कुछ इस तरह खर्च करना चाहिए कि उसका निशाना बेरूत नहीं, बल्कि तेहरान में बैठे हिजबुल्ला के आका हों।

तीसरा सबक : लेबनान के लोगों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। अरब बैरोमीटर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अपने शिया गढ़ों को छोड़कर हिजबुल्ला ज्यादातर लेबनानियों के बीच अलोकप्रिय है। दरअसल, हिजबुल्ला ने उनके देश पर कब्जा कर लिया, उनके लोकप्रिय नेताओं की हत्याएं कीं, देश के ज्यादातर हिस्से को एक लक्ष्य बना दिया और देश के संसाधनों को विशाल सैन्य ढांचा तैयार करने का औजार बना दिया, भले ही इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई हो। हालांकि, इस्राइल, लेबनान से सहयोगी बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। यह कल्पना तो 1982 में लेबनान के इस्राइल-गठबंधन के नियंत्रित राष्ट्रपति बशीर गेमायेल की सीरियाई समर्थित हत्या के साथ ही खत्म हो गई थी। लेकिन पाशविक बल प्रदर्शन के जरिये इसके निवारण की उसे 2006 वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। बीते दिनों जिस तरह लक्षित कर पेजर हमले हुए, वे हिजबुल्ला की साख को नुकसान पहुंचाने के नजरिये से भी काफी प्रभावी रहे।

चौथा सबक : संयुक्त राष्ट्र को इससे दूर रखें। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701, जिसने 2006 में युद्ध रुकवा दिया था, ने हिजबुल्ला की सेना को इस्राइली सीमा से दूर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को अधिकार दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति बलों ने अमेरिकी करदाताओं के अरबों डॉलर बर्बाद करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। यदि अमेरिका या यूरोप के लोग इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच एक प्रतिरोधक क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो नाटो के ध्वज के तले अपने सैनिकों को तैनात करना चाहिए, अथवा अरब देशों को सेना भेजने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो दक्षिणी लेबनान में 1985 से 2000 तक रहे इस्राइली नियंत्रण वाले सुरक्षा क्षेत्र की फिर से बहाली ही सबसे कम बुरा विकल्प होगा, भले ही लंबे समय के लिए इसके कुछ भी निहितार्थ निकलें।

पांचवां सबक : संकट में अमेरिका की उचित भूमिका कूटनीतिक समाधान निकालने की नहीं, बल्कि इस्राइल को जीतने में मदद करने की है। 11 सितंबर, 2001 को हुए अलकायदा के हमले से पहले तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने उतने अमेरिकियों की हत्या नहीं की थी, जितनी हिजबुल्ला कर चुका है। बेरूत में इस्राइल के हमले में बीते दिनों हिजबुल्ला का कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया, जिसने 1983 में अमेरिकी दूतावास और मरीन बैरकों पर हुए हमलों का बदला लिया, जिसमें 258 अमेरिकी मारे गए थे। हिजबुल्ला ने बाद में अनगिनत सीरियाई लोगों की हत्या कर अपने ही लोगों के खूनी दमन में बशर अल-असद की मदद की। उन अपराधों को कभी भुलाया और माफ नहीं किया जाना चाहिए।

छठा सबक : इस्राइल की विभिन्न लड़ाइयों को क्षेत्रीय मामलों के रूप में देखते हुए इन्हें अमेरिकी चिंताओं से दूर मानना भी मूर्खतापूर्ण है। अब हम स्वतंत्र और परोक्षीय दुनिया के बीच एक और प्रतिस्पर्धा के शुरुआती चरण में हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है, जो रूस के साथ नॉर्वे की सीमा से लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ईरानी लोगों के संघर्ष से लेकर दक्षिण चीन सागर के तटों तक पहुंचता है। शायद यह कई दशकों तक चलेगा। इस लड़ाई में एक तरफ इस्राइल है और हिजबुल्ला दूसरी ओर। आगामी दिनों और हफ्तों में जो भी हो, लेकिन कोई भी देश उनके बीच तटस्थ होने का दिखावा नहीं कर सकता।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

कार्ल सेगन

जब हम मरते हैं, तो असल में मरते नहीं हैं। हमारे भीतर कुछ सोचने, महसूस करने और याद रखने की क्षमता बनी रहती है। यह कुछ भी हो सकती है- आत्मा या भावना अथवा किसी तरह की ऊर्जा या शायद कुछ और।

पिता के साथ वह अंतिम बार गले लगना

मेरे माता-पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं। जाहिर है कि मुझे उनकी याद आती है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा हो कि ज्यादा नहीं, बस साल में चार-पांच मिनट मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाया करे। काश! मैं उन्हें उनके पोते-पोतियों और मेरे जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में बता पाता। मेरे पिता ने जो आखिरी शब्द कहे, वह थे, 'अपना ख्याल रखना।' जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भी मेरे लिए चिंतित था, ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाले माता-पिता ही हो सकते हैं। और, मैं उनसे बस पूछना चाहता हूं कि वे ठीक तो हैं। कभी-कभी मैं सपने में उन्हें देखता हूं, उनसे बातें भी करता हूं, लेकिन जब जागता हूं, तो अपने भीतर वही खालीपन महसूस करता हूं। मुझे याद आता है पिता के साथ वह अंतिम बार गले लगना। कभी-कभी यह सोचकर रोता हूं कि उनके अंतिम दिनों में शायद अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाया। अगर निभाता, तो उन्हें बचा न लेता। अपनी इस गलती के लिए न जाने कितनी बार ईश्वर से और उनसे माफी मांगता हूं। अभी भी ऐसा लगता है कि मानो पिताजी मुझसे बात कर रहे हैं और मां मुझे घर से निकलने से पहले स्वेटर पहनने के लिए कह रही हों। लेकिन होश में आने पर फिर वही शोक। यह स्पष्ट रूप से लगता है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन पर यकीन रखता है और इस बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता कि इसके लिए कोई ठोस सबूत है या नहीं। इसलिए, मैं कभी भी उस महिला पर नहीं हंसता, जो अपने पति की कब्र पर जाती है और कभी-कभी, शायद उसकी पुण्यतिथि पर, उससे बातें करती हो। कई लोगों को यह बचकाना लगता है। इसे समझना मुश्किल नहीं है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है कि वह अपने पति की कब्र के सामने बात कर रही है। यह इन्सानों के इन्सान होने के बारे में है। लगभग पंद्रह प्रतिशत लोग मानते हैं कि किसी न किसी स्तर पर उन्होंने मृतकों से संपर्क साधे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसे किसी भी माध्यम के दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जो लोग प्रिय दिवंगत की आत्माओं को संदेश भेजने का दावा करते हैं, जबकि मुझे पता है कि ज्यादातर मामलों में यह काम धोखाधड़ी से भरा हुआ है।

कभी-कभी मैं सोचता हूं कि मेरे माता-पिता अपने शरीर को सांप की केंचुली की तरह छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह के विचार मुझे ठगी का शिकार भी बना सकते हैं। दरअसल, मृत्यु के बाद के जीवन के साक्ष्य अगर प्रयोगों पर निष्पक्ष प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, तो उनके प्रति मैं निस्संदेह उत्सुक रहूंगा। मुझे लगता है कि जब हम मरते हैं, तो हम असल में मरते नहीं हैं। क्योंकि हमारे भीतर कुछ सोचने, महसूस करने और याद रखने की क्षमता बनी रहती है। जो कुछ भी हो सकती है-आत्मा या भावना, किसी तरह की ऊर्जा या शायद कुछ और। लेकिन अगर मृत्यु एक अंतहीन स्वप्नहीन नींद से ज्यादा कुछ नहीं है, तो यह एक निराशाजनक उम्मीद है। शायद इस नजरिये ने मुझे जिंदा रहने के लिए थोड़ी अतिरिक्त प्रेरणा दी है।

जीवन पर भरोसा रखें

सूत्र

मृत्यु के बाद की राह तो किसने ही देखी है। लेकिन कुछ तो है, जो मरने के बाद भी बचा रहता है। यह कुछ, जिसमें वर्तमान जीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं। जो समय मिला है, उस पर भरोसा रखें और उसमें जो करना चाहिए, वह सब करें।

दूसरा पहलू

मथुरा के हाथी पुनर्वास केंद्र में सर्वेक्षण, रामलीला और साधुओं से घुहाए हाथी शांत जीवन का आनंद ले रहे हैं।

गहरी पीड़ा से गुजरने के बाद आए खुशी के पल

भूपेंद्र कुमार

हाथी को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा को नष्ट किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को पैजान कहा जाता है।

घुमन्तु सेंटर में टिकने भी हाथी हैं, सबके पीठ एक दर्दनाक अतीत है। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब वे आजाद हैं, यमुना में नहाने या आपस में खेलने के लिए। अब उन्हें किसी के इशारे पर नहीं नाचना।

उनकी आंखों में देखने पर आप कुछ सेकंड के लिए खुद को भूल जाएंगे। वहां एक गहरी करुणा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आखिर उन्होंने, जो जिंदगी पहले जी और जहां वे अब हैं, दोनों में इतना अंतर जो है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, हाथी सवारी करने के लिए होते हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क में इन पर बैठकर वन्य जीवों को निहारा जा सकता है। सर्कस में हाथी को फुटबाल खेलते देखना रोमांचित कराता था। पर क्या आपने सोचा कि हमसे कई गुना ताकतवर और आकार में बड़ा यह शानदार जीव किसी 60 किलो के इन्सान के इशारों पर क्यों नाचने को तैयार हो जाता है।

इसका जवाब पाने के लिए आपको वाइल्ड लाइफ एसओएस के चुरमुरा (मथुरा) स्थित हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र आना होगा। यहां करीब 30 हाथी हैं, जिन्हें अलग-अलग जगह नारकीय जीवन से बचाकर लाया गया है। इस केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से 2010 में की गई थी। बाद में यहां देश का पहला हाथी अस्पताल भी बनाया गया।

हाथी को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा को नष्ट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पैजान कहा जाता है। इस क्रूर प्रक्रिया की शुरुआत नन्हे हाथी को मां से अलग करने से होती है। इस यातना से परेशान हाथी मर न जाए, इसलिए महावत सातों दिन उसके साथ ही रहता है। हाथी को रस्सों से बांध दिया जाता है, जिससे वह बैठे नहीं। इन्हें अंधेरे जगह पर लगातार लाठियों से पीटा जाता है। जब महावत थोड़ा-सा चारा लेकर इनके पास जाता है, तो उसका आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगर कोई हाथी नहीं मानता, तो उसके पैरों में कीलों वाला लोहे का शिकंजा पहना दिया जाता है, जिसके चिंघने से कीलें मांस में धुस जाती हैं, तब असहनीय पीड़ा होती है।

कई बार हाथी इससे बचने के लिए अपनी सूंड पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है, ताकि दम घुटने से वह मर जाए। पर महावत ऐसा नहीं होने देते। सेंटर में एक जगह पर ये सांकल, शिकंजे व अंकुश रखे हैं, जिनसे हाथियों को नियंत्रित किया जाता है। खासकर अंकुश से उनके कान के पास सबसे नरम हिस्से पर वार किया जाता है, जिससे वह इच्छानुसार चले। सेंटर के सहसंस्थापक कार्तिक सत्यनारायण कहते हैं कि हाथियों को छुड़ाना आसान नहीं। सेंटर में जितने भी हाथी हैं, सबके पीछे एक दर्दनाक अतीत है। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब वे आजाद हैं, यमुना में नहाने या आपस में खेलने के लिए। अब उन्हें किसी के इशारे पर नहीं नाचना।

आंकड़े

योगाभ्यास

दुनिया भर में लोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए योग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनमें महिलाएं योगाभ्यास को लेकर काफी सजग हैं।

आंकड़े योगाभ्यास करने वाली महिलाओं के, प्रतिशत में | स्रोत : SCI

गुडाकेश ने भगवान से वरदान में उनके चक्र से मृत्यु मांगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना पर चक्र द्वारा उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके अपने पास बुला लिया।

असुर की भक्ति और तांबा

अंतर्यात्रा
संकलित

सृष्टि के प्रारंभ में ही महासुर गुडाकेश तांबे का शरीर धारण कर चौदह हजार वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। उसकी निश्चयपूर्ण तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। गुडाकेश भगवान को देखकर खुशी के मारे आंखों से आंसू बहाने लगा।

भगवान विष्णु ने मुस्कराते हुए कहा, 'हे निष्पाप गुडाकेश! कर्म से, मन से या वाणी से तुम्हें जो भी अच्छा लगता हो, वह मांग लो।' भगवान की बात सुनकर गुडाकेश ने विशुद्ध हृदय से कहा, 'भगवन! यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं, तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहां भी जन्म लूं, आपके चरणों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे।' गुडाकेश ने कहा, 'प्रभु! एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु आपके चक्र से ही हो और जब चक्र से मैं मर जाऊं तब मेरे मांस, मज्जा आदि तांबे के रूप में हो जाएं और उसी तांबे के पात्र से आपकी पूजा हो। मरने पर भी मेरा शरीर आपके ही काम में आए।' भगवान ने प्रसन्नता से उसकी प्रार्थना स्वीकार की। और चक्र द्वारा उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके अपने पास बुला लिया। उसके शरीर के जो टुकड़े हुए, वे सब तांबे में परिवर्तित हो गए। मान्यता है कि तभी से वैष्णव लोग तांबे के पात्र से भगवान का अर्घ्य आदि अर्पित करते हैं। तांबे के मल से ही सीसा, कांस्य, लाख, ऊषर और सोना आदि बने हैं। भक्त का शरीर होने के कारण भगवान को तांबा अत्यंत प्रिय है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 जून, 1960

विश्व को विनाश से बचाने की जिम्मेदारी बड़े देशों पर

विश्व को विनाश से बचाने की जिम्मेदारी बड़े देशों पर
भारत-रूस सहयोग की चर्चा

राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि विश्व को युद्ध एवं विनाश से बचाने के लिए सोवियत संघ जैसे बड़े देशों की विशेष जिम्मेदारी है। धैर्य, संकल्प एवं निरंतर प्रयत्नों द्वारा ही युद्ध का भय दूर किया जा सकता है।

पराली से होने वाले प्रदूषण से कैसे निपटेंगे

हर साल पराली पर दो महीने की और पटाखों पर हफ्ते भर की हाय-तौबा के बाद 10-11 महीनों की चुप्पी से समाधान कैसे होगा?

ऋतुपर्ण दवे

पर्यावरण

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर लताड़ा है। पराली जलाने के वैकल्पिक उपकरणों का जमीनी स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों की जरूरत जताने के साथ ही बेहतर अनुपालन पर बल दिया। सीएक्यूएम के अध्यक्ष को दो टूक कहा कि आपने अब तक अधिनियम के एक भी प्रावधान का अनुपालन क्यों नहीं किया? यह भी पूछा कि निदान के लिए बनी समितियां क्या हवा में हैं?

ऐसे में पराली से होने वाले वायु प्रदूषण से कैसे निपटेंगे? आयोग तीन महीने में एक बार बैठता है। अगली बैठक तक नया संकट आ खड़ा होता है। तीन साल से अस्तित्व में आयोग कुल 82 निर्देश जारी कर सका, जो नाकाफी हैं। आयोग आकलन करे कि उसके निर्देशों से अनुपालन कम हो रहा है या नहीं? दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर्मचारी भी नाकाफी हैं। अन्य पांच प्रदूषण फैलाने वाले राज्यों में भी यही स्थिति है। 30 अप्रैल 2025 तक सभी जगह रिक्त पद भरें, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।

पिछले वर्ष भी जब पराली पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को दो टूक कहा गया कि किसान संगठनों से बात करें, ताकि प्रदूषण घटे। 20 नवंबर, 2023 यानी दिवाली के आठ दिन बाद फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार को फटकारा और नासा की तकनी ताजा तस्वीरों का हवाला दिया, जिसमें उसी रात दिखे धुएं के लाल आसमान व धुंध की कालिमा साफ थी। तब भी तमाम हस्तक्षेपों के बावजूद पराली जलाने की 33,000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुईं। शीर्ष अदालत ने 21 नवंबर, 2023 को भी आगे की सुनवाई में हरियाणा से सीखने की नसीहत दी। किसानों के साथ हमदर्दी भी दिखाई और कहा कि वे अकारण खलनायक बनते हैं, उनकी भी सुनें। पूछा कि किसान किसे नोटिस दें? मानवीय संवेदनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी नौकरशाह और माननीयों के लिए बड़ा इशारा और चेतावनी है। न्यायालय की जबरदस्त पैरोड़ी भी कि मास्क लगा काम कर रहे अधिकारियों से कहा जाए कि वे उसे हटाएं और लोगों की तकलीफ महसूस करें।

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में वक्त-बेवक्त दिल्ली-एनसीआर भी आ जाता है। पटाखों पर रोक के बावजूद बीती दिवाली पूरा क्षेत्र दोहरे प्रदूषण की गिरफ्त में धुआं-धुआं हुआ। नौबत कृत्रिम बारिश तक की आई थी और सलाह-मशविरा जारी था कि ऊपर चले ने दया कर दी। बीती दिवाली जब सारा देश दीयों की रोशनी से नहाया था, तभी सर्वोच्च न्यायालय की आस का दीपक बुझ गया। लाख प्रतिबंधों के बावजूद देर रात और दो-तीन रात बाद तक समूचे एनसीआर में प्रतिबंधित पटाखों की आवाज और उनके धुएं ने सबको धता बता दिया। हर जगह बारूदी धुएं की गंध, आसमान में आतिशबाजी के रंग बिखेरते प्रतिबंधित रसायनों के पटाखे फूटते रहे। दिवाली के बाद की सुबह दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता दुनिया में सबसे बदतर रही। कई क्षेत्रों में सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 999 तक पहुंच गया। पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले कारणों और उसके आसान निदानों के बेअसर उपायों पर कब गंभीरता से सोचा जाएगा? आखिर कब समझेंगे कि दिवाली के पहले और बाद भी जहरीला धुआं हरेक सांस पर भारी है।

पराली-पटाखे जलाने पर पुलिस प्रकरण स्थायी हल नहीं है। धान काटते समय पराली भी काट लेना असंभव कैसे है? हर साल पराली पर दो महीने की और पटाखों पर हफ्ते भर की हाय-तौबा के बाद 10-11 महीनों की चुप्पी से समाधान कैसे होगा? समझना होगा कि कैसे जमीन के कार्बनिक तत्व, कीमती बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह पराली जलाने से नष्ट होते हैं। इससे पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान, तो ग्लोबल वार्मिंग अलग बढ़ती है। अनजाने या मजबूरन उसी खेत का कम से कम 25 प्रतिशत खाद भी नष्ट होता है। प्रति एकड़ पराली के ठूठ जलाकर कई पोषक तत्वों सहित करीब 400 किलो ग्राम फायदेमंद कार्बन, एक ग्राम मिट्टी में मौजूद 10 से 40 करोड़ बैक्टीरिया और एक से दो लाख फफूंद भी जला बैठते हैं, जो फसल के हितैषी और जबरदस्त पोषक होते हैं। विडंबना देखिए कि फसल के पोषण के लिए वही तत्व, किसान दोबारा ऊंची-ऊंची कीमतों में अलग-अलग नाम से फिर खरीदते हैं, जिसे पहले बेकार समझ जला डालते हैं।

पराली की खुबियों को भी जनस्वास्थ्य, जल-जीवन, स्वच्छता मिशन जैसे सबको समझाया जाए, ताकि किसान भी इसके सदुपयोग को समझें, कमाई भी करें और खेतों को नई उर्वरा दें। इसके लिए स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, औद्योगिक घराने, किसानों को उन्नत मशीनें मुहैया कराएं, जो दोनों के लिए लाभकारी होगा। अलख यह हो कि पराली जलाने के लिए नहीं, किस्मत बदलने के लिए है। edit@amarujala.com